रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ का विशेषांक

प्रभात

अंदर के पन्नों में...
★ नोटबंदी का एक साल 10
★ हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ 15
★ उत्तर कोरिया का धिक्कार 17
★ शिक्षाकर्मियों के आंदोलन 23
★ दमन और जन प्रतिरोध 27
★ अमर शहीदों की जीवनियां 32
★ जिनुगू नरसिंहा रेड्डी की गद्दारी 47

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख–पत्र
वर्ष–29 अंक–4 अक्टूबर–दिसंबर 2017 सहयोग राशि–15 रुपए

रूसी क्रांति में निहित सारतत्वों की विश्वजनीन सच्चाई को सदा बुलंद रखें!

भारत की विशिष्टताओं के अनुरूप उसे व्यवहार में लागू करें!

– केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माओवादी) के संदेश के मुख्य अंश

विदित है कि 1917 के 7 नवंबर, महान रूसी क्रांति का विजय दिवस था. वह रूस तथा दुनिया के मजदूर, किसान व मेहनतकश अवाम के लिए एक ऐसे दिन के बतौर सामने आया जिस दिन वे वर्ग शोषण व वर्ग अत्याचार से मुक्ति मार्ग की ओर एक कदम अग्रगति के रूप में खुशियां मनाने के साथ–साथ शपथ भी लेते हैं. इसे और सुस्पष्ट कर कहने से रूसी क्रांति को वे पूंजीवाद के सीमाहीन शोषण व प्रचंड जुल्म से मुक्ति की ओर अग्रसर होने के रास्ते में एक मील का पत्थर जैसी विजय के रूप में देखते हैं. वाकई में जब से समाज में वर्गों का उदय हुआ और वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई, तब से रूसी नवम्बर क्रांति ही दुनिया की सबसे पहली ऐसी क्रांति है जिससे पुराने शोषक–शासक वर्गों का तख्ता उलट कर मजदूर वर्ग का तथा मजदूर, किसान, मेहनतकशों का राज स्थापित हुआ. कामरेड माओ ने कहा, ''अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने न केवल रूस के इतिहास में, बल्कि विश्व के इतिहास में भी एक नए युग का सूत्रापात किया है''. महान रूसी अक्टूबर क्रांति की 40वीं वर्षगांठ पर रूस में यू.एस.एस.आर. के सुप्रीम सोवियत (जिसमें सोवियत युनियन और तमाम राष्ट्रीयताओं के सोवियत शामिल थीं) के सामने कामरेड माओ द्वारा दिए गए एक भाषण (नवम्बर–1957) में उन्होंने कहा, ''जैसे कि हमारे क्रांतिकारी शिक्षक कामरेड लेनिन ने इस बात को दर्शाया है कि 40 वर्षों पहले सोवियत जनता द्वारा संचालित महान

रूसी क्रांति के महान नेता

कामरेड लेनिन कामरेड स्तालिन

महान रूसी समाजवादी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को जय–जयकार

रूसी क्रांति विश्व इतिहास में एक नया युग की शुरूआत की है ... ... इतिहास में अनेकों प्रकार के क्रांतियां देखी गयीं. पर, अक्टूबर समाजवादी क्रांति के साथ तुलना करने लायक एक भी नहीं है. विगत हजारों वर्षों से समूचा विश्व के श्रमजीवी जनता और प्रगतिशील ताकतें एक ऐसा समाज की स्थापना की बात करते थे जहां एक मानव द्वारा दूसरे मानव पर शोषण नहीं रहेगा. उस सपने का कार्यान्वयन तब–ही संभव हुआ जब दुनिया के एक चौथाई क्षेत्र में पहली बार अक्टूबर क्रांति सफल हुई.''

'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' के जरिए ही सबसे पहले महान मार्क्स–एंगेल्स ने पूंजीवाद के ध्वस्त होने व समाजवाद की स्थापना होने की अनिवार्यता की बात कही

दुनिया के मजदूर–किसान–मेहनतकश जनता सहित आम जनता इस बात से अवगत हैं कि पूंजीवाद को ध्वस्त कर समाजवाद की स्थापना होना अनिवार्य है– का सिद्धांत महान मार्क्स ने ही सबसे पहले सामने लाया था. जैसाकि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र में हम पाते हैं कि ''बुर्जुआ वर्ग सर्वोपरि अपनी कब्र खोद देने वालों को ही पैदा करता है. उनका पतन और सर्वहारा की विजय, दोनों समान रूप से अवश्यंभावी हैं''. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र हमें सिखाया है कि, ''कम्युनिस्टों का तात्कालिक लक्ष्य वही है, जो अन्य सभी सर्वहारा पार्टियों का है, अर्थात सर्वहारा एक वर्ग के रूप में गठन, बुर्जुआ प्रभुत्व का तख्ता उलटना, सर्वहारा द्वारा राजनीतिक सत्ता का जीता जाना'' (मार्क्स–एंगेल्स– कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र)

मार्क्स–एंगेल्स के ऐतिहासिक सिद्धांत को व्यवहार में कार्यान्वित कर पाने के लिए यानी बुर्जुआ प्रभुत्व का तख्ता उलटकर सर्वहारा द्वारा राजनीतिक सत्ता को जीतने के लिए 1917 तक इंतजार करना पड़ा. हालांकि, 1871 में स्थापित पेरिस कम्युन सर्वहारा की पहली राज्यसत्ता था, लेकिन पेरिस कम्यून के सर्वहारा वर्ग ने राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए पहली बार वीरतापूर्ण संघर्ष किया था. मगर, पूंजीपति वर्ग के सशस्त्र दमन के परिणामस्वरूप उसमें हार खानी पड़ी.

रूसी क्रांति का इतिहास टेढ़–मेढ़ा व उतार–चढ़ाव की तीन क्रांतियों के दौर से गुजरा

जाहिर है कि महान लेनिन व स्तालिन और उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में संचालित सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के नेतृत्व में 1917 के 7 नवम्बर (रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर) की समाजवादी क्रांति सफल हुई. पर, एक ही चोट या कोशिश में यह समाजवादी क्रांति विजय हासिल नहीं कर सकी. बल्कि, तीन क्रांतियों से गुजरते हुए ही 1917 की समाजवादी क्रांति सफल हुई. ये तीन क्रांतियां थीः 1905 की पूंजीवादी–जनवादी क्रांति, फरवरी 1917 की पूंजीवादी–जनवादी क्रांति और अक्टूबर 1917 की समाजवादी क्रांति.

पर, पहली 1905 की रूसी क्रांति का अंत पराजय में हुआ. जिन कारणों से यह पराजय हुई उसे गहराई से समझना हमारे लिए बहुत जरुरी है. क्योंकि हम भी भारतीय क्रांति के मौजूदा दौर में उतार–चढ़ाव, पीछे हटना, ध्क्का खाना आदि का सामना कर रहे हैं. जो भी हो, पहली रूसी क्रांति की पराजय के मूल कारणों को रूसी बोल्शेविक पार्टी ने समीक्षा करते हुए जिन बातों को सामने लाया, संक्षेप में वे हैं:

1. क्रांति में जारशाही के खिलाफ अभी मजदूरों और किसानों का पक्का सहयोग कायम नहीं हुआ था.
2. किसानों का काफी बड़ा हिस्सा जारशाही का खात्मा करने के लिए मजदूरों से सहयोग करने में अनिच्छुक था. उसका असर फौज के व्यवहार पर भी पड़ा. फौज में ज्यादातर सिपाहियों की वर्दी पहने हुए किसानों के बेटे थे. जार की फौज के कई दस्तों में असंतोष और विद्रोह फूट पड़ा, लेकिन अधिकांश सैनिकों ने अभी भी मजदूरों की हड़तालें और विद्रोह दबाने में जार की मदद की.
3. मजदूरों की कार्रवाई भी काफी सुगठित नहीं थी. क्रांतिकारी संघर्ष में वे 1906 में ज्यादा सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे, लेकिन उस समय तक मजदूर वर्ग का हिरावल काफी कमजोर हो चुका था.
4. मजदूर वर्ग क्रांति की पहली और प्रधान शक्ति था. लेकिन मजदूर वर्ग की पार्टी की कतारों में आवश्यक एकता और दृढ़ता का अभाव था. रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी–मजदूर वर्ग की पार्टी–दो दलों में बंटी हुई थीः बोल्शेविक और मेंशेविक. बोल्शेविक जारशाही का खात्मा करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया था. मेंशेविकों ने अपनी समझौतापरस्त कार्यनीति से क्रांति में बाधा डाली, मजदूरों के बड़ी तादाद के मन में उलझन पैदा कर दी। इसलिए, मजदूरों ने क्रांति में हमेशा एकजुट होकर काम नहीं किया. अभी खुद अपनी कतारों में एकता नहीं होने की वजह से, मजदूर वर्ग क्रांति का सच्चा नेता नहीं बन सका.
5. निरंकुश जारशाही को 1905 की क्रांति का दमन करने में पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादियों से मदद मिली.
6. सितम्बर 1905 में, जापान से शांति–संधि हो जाने पर जार को काफी मदद मिली. संधि होने से जार का पाया मजबूत हुआ.

अब दूसरी क्रांति पर नजर डाली जाएः दूसरी क्रांति तो फरवरी, 1917 में हुई. जिसके जरिए जारशाही का पतन

हुआ तथा मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियतों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ तथा दोहरी सत्ता अस्तित्व में आयी. इस तरह फरवरी की पूंजीवादी–जनवादी क्रांति की जीत हुई. रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) ने दिखाया है कि ''क्रांति की जीत इसलिए हुई कि इसका हिरावल मजदूर वर्ग था. फौजी वर्दी पहने हुए और 'शांति' रोटी और आजादी मांगते हुए, लाखों किसानों के आंदोलन का मजदूर वर्ग ने नेतृत्व दिया. सर्वहारा वर्ग के दृढ़ नेतृत्व ने ही क्रांति की सफलता निश्चित कर दी.''

क्रांति के प्रारंभिक दिनों में कामरेड लेनिन ने लिखा था, ''क्रांति मजदूरों ने की थी. मजदूरों ने वीरता दिखाई; उन्होंने अपना खून बहाया; अपने साथ मेहनतकश और गरीब जनता को बहा ले गये.''

कामरेड लेनिन ने लिखा, ''1905–1907 के तीन वर्षों में ही सोवियतें बन गयीं. विजयी क्रांति को मजदूर और फौजी प्रतिनिधियों की सोवियतों के समर्थन का आधार मिला. जिन मजदूरों और सैनिकों ने विद्रोह किया, उन्होंने मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियतें बना लीं. 1905 की क्रांति ने दिखला दिया कि सोवियतें सशस्त्र विद्रोह का साधन थीं, और साथ ही एक नयी क्रांतिकारी सत्ता का बीज थीं. आम मजदूर जनता के मन में सोवियतों की बात जीवित रहीं और जैसे ही जारशाही का तख्ता उलटा गया, वैसे ही उसे अमल में ले आयी. अंतर इतना था कि 1905 में सिर्फ मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियतें बनी थीं, जबकि फरवरी 1917 में बोल्शेविकों की पहलकदमीं पर मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियतें बनीं.''

मगर, सोवियत की कार्यकारिणी समिति के समाजवादी–क्रांतिकारी और मेंशेविक नेताओं ने सत्ता पूंजीवादियों को सौंप दी. फिर भी, जब मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों ने यह सब जाना, तो उसके बहुमत ने, बकायदा बोल्शेविकों के विरोध के बावजूद, समाजवादी–क्रांतिकारी और मेंशेविक नेताओं के काम को पास कर दिया.

इस तरह रूस में एक नयी राज्यसत्ता पैदा हुई जिसमें, लेनिन के शब्दों में, ''पूंजीपतियों और पूंजीपति बन जाने वाले जमींदारों'' के प्रतिनिधि शामिल थे.

लेकिन पूंजीवादी हुकूमत के साथ–साथ, एक दूसरी सत्ता मौजूद थी–मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियत. सोवियत में सैनिक प्रतिनिधि ज्यादातर किसान थे, जो युद्ध के लिए भर्ती किये गये थे. मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियत जारशाही के खिलाफ मजदूरों और किसानों के सहयोग के संस्था थी और इसके साथ ही उनकी सत्ता की संस्था थी, मजदूर वर्ग और किसानों के अधिनायकत्व की सत्ता थी.

विंटर पैलिस पर हमला

इसका फल यह हुआ कि दो सत्ताएं, दो अधिनायकत्व विचित्र ढंग से आपस में गुंथ गयेः पूंजीपतियों का अधिनायकत्व, जिसकी प्रतिनिधि अस्थायी सरकार थी और मजदूरों और किसानों का अधिनायकत्व, जिसकी प्रतिनिधि मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियत थी.

अब, तीसरी क्रांति यानी रूसी अक्टूबर समाजवादी क्रांति पर नजर डाली जाए. पहले यह हमें याद रखना चाहिए कि पहला विश्वयुद्ध 1914 से 1918 तक चला और रूसी समाजवादी क्रांति 1917 के अक्टूबर में सफल हुई.

जिस प्रक्रिया के जरिए रूसी नवंबर क्रांति सफल हुई उसके बारे में कहा जा सकता है कि 1917 के 3 अप्रैल की रात को कामरेड लेनिन ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने समाजवादी क्रांति की विजय के लिए लड़ने के लिए आम जनता का आह्वान किया. 'समाजवादी क्रांति जिंदाबाद'– इन शब्दों के साथ कामरेड लेनिन ने अपना यह भाषण खत्म किया. इसी समय कामरेड लेनिन ने युद्ध और क्रांति के विषय पर बोल्शेविकों की एक मीटिंग में उन्होंने रिपोर्ट दी और उसके बाद मेंशेविकों और बोल्शेविकों की एक मिली–जुली मीटिंग में रिपोर्ट की सैद्धांतिक स्थापनाओं (थीसीस) को दोहराया. ये कामरेड लेनिन की मशहूर अप्रैल थीसीस थी, जिससे पार्टी और सर्वहारा वर्ग को पूंजीवादी क्रांति से समाजवादी क्रांति की तरफ बढ़ने के लिए एक स्पष्ट क्रांतिकारी नीति मिली.

अक्टूबर 1917 से फरवरी 1918 तक, देश के विशाल

26 अक्टूबर, 1917 को अखिल रूसी दूसरी कांग्रेस में भाषण देते हुए कामरेड लेनिन

प्रदेशों में सोवियत क्रांति इतनी तेजी से फैली कि कामरेड लेनिन ने उसे सोवियत सत्ता की 'विजय' यात्रा कहा.

महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की विजय हुई

रूस में समाजवादी क्रांति की इस अपेक्षाकृत आसान विजय के कई कारण थे. नीचे संक्षेप में लिखे हुए मुख्य कारण ध्यान देने योग्य हैं:

(1) अक्टूबर क्रांति का दुश्मन अपेक्षाकृत ऐसा कमजोर, ऐसा असंगठित और राजनीतिक रूप से ऐसा अनुभवहीन था जैसे कि रूसी पूंजीपति. रूसी पूंजीपति आर्थिक रूप से कमजोर थे और पूरी तरह सरकारी ठेकों पर निर्भर थे. उनमें राजनीतिक आत्मनिर्भरता और पहलकदमीं इतनी नहीं थी कि परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ़ सकें. मसलन, बड़े पैमाने पर राजनीतिक गुटबंदी और राजनीतिक दगाबाजी में उन्हें फ्रांसीसी पूंजीपतियों का सा तजुर्बा नहीं था, और न ही अंग्रेज पूंजीपतियों की तरह उन्होंने विशद रूप से सोची हुई चतुर समझौता करने की शिक्षा पायी थी. फरवरी क्रांति ने जार का तख्ता उलट दिया था और सत्ता खुद पूंजीपतियों के हाथ में आ गयी थी लेकिन बुनियादी तौर से घृणित जार की नीति पर ही चलने के सिवा उन्हें और कोई चारा नहीं था. जार की तरह, उन्होंने 'विजय तक युद्ध करने' का समर्थन किया, हालांकि युद्ध चलाना देश की शक्ति से परे था और जनता तथा फौज दोनों युद्ध से बुरी तरह से चूर हो चुके थे. जार की तरह कुल मिलाकर वे भी बड़ी जागीरी जमीन बनाये रखने के पक्ष में थे, हालांकि जमीन की कमी और जमींदारों के जुए बोझ से किसान मर रहे थे. जहां तक उनकी मजदूर नीति का संबंध था, वे मजदूर वर्ग से नफरत करने में जार को भी कान काट चुके थे. उन्होंने कारखानेदार के जुवे को बनाये रखने और मजबूत करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर तालेबंदी करके उसे असहनीय बना दिया. कोई ताज्जुब नहीं कि जनता ने जार की नीति की और पूंजीपतियों की नीति में बुनियादी भेद नहीं देखा, और जो घृणा उसके दिल में जार के लिए थी वही पूंजीपतियों की अस्थायी सरकार के लिए हो गयी.

जब तक समाजवादी–क्रांति और मेंशेविक पार्टियों का थोड़ा–बहुत असर जनता पर था, तब तक पूंजीपति उन्हें पर्दे की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी सत्ता कायम रख सकते थे. लेकिन, जब मेंशेविकों और समाजवादी–क्रांतिकारियों ने जाहिर कर दिया कि वे साम्राज्यवादी पूंजीपतियों के दलाल हैं और इस तरह जनता में उन्होंने अपना असर खो दिया, तब पूंजीपतियों और उनकी अस्थायी सरकार का कोई मददगार नहीं रहा.

(2) अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व रूस के मजदूर वर्ग जैसे क्रांतिकारी वर्ग ने किया. यह ऐसा वर्ग था जो संघर्ष की आंच में तप चुका था, जो थोड़ी ही अवधि में दो क्रांतियों से गुजर चुका था और तीसरी क्रांति के शुरू होने से पहले शांति, जमीन, स्वाधीनता और समाजवाद के लिए संघर्ष में जनता का नायक माना जा चुका था. अगर क्रांति का नेता रूस के मजदूर वर्ग जैसा न होता, ऐसा नेता जिसने जनता का विश्वास पा लिया

था, तो मजदूरों और किसानों की मैत्री न होती और इस तरह की मैत्री के बिना अक्टूबर क्रांति की विजय असंभव होती.

(3) रूस के मजदूर वर्ग को क्रांति में गरीब किसानों जैसा सुदृढ़ साथी मिला, जो किसान जनता का भारी बहुसंख्यक भाग था. सर्वहारा और गरीब किसानों की मैत्री दृढ़ हुई. मजदूर वर्ग और गरीब किसानों की इस मैत्री के कायम होने से, मध्यम किसानों की भूमिका स्पष्ट हो गयी. ये मध्यम किसान बहुत दिन तक ढुलमुल रहे थे और अक्टूबर विद्रोह के शुरू होने से पहले ही पूरी तरह क्रांति तरफ आये थे और उन्होंने गरीब किसानों से नाता जोड़ा था. कहना न होगा कि इस मैत्री के बिना अक्टूबर क्रांति विजय न होती.

(4) मजदूर वर्ग का नेतृत्व राजनीतिक संघर्षों में तपी और परखी हुई बोल्शेविक पार्टी जैसी पार्टी ने किया था. बोल्शेविक पार्टी इतनी साहसी पार्टी थी कि निर्णायक हमले में जनता का नेतृत्व कर सके. शांति के लिए आम जनवादी आंदोलन, जागीरी जमीन छीनने के लिए किसानों का जनवादी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता और राष्ट्रीय समानता के लिए उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का आंदोलन और पूंजीपतियों का तख्ता उलटने के लिए और सर्वहारा अधिनायकत्व कायम करने के लिए सर्वहारा वर्ग का समाजवादी आंदोलन–इन सबको ऐसी ही पार्टी क्रांति कारी धरा में मिला सकती थी.

इसमें संदेह नहीं कि इन विभिन्न आन्दोलनों की धाराओं के एक ही सामान्य शक्तिशाली क्रांतिकारी धारा में मिलने से रूस में पूंजीवाद की तकदीर का फैसला हो गया.

(5) अक्टूबर क्रांति ऐसे समय आरंभ हुई जबकि साम्राज्यवादी युद्ध अभी जोरों पर था, जबकि प्रमुख पूंजीवादी राज्य दो विरोधी खेमें में बंटे हुए थे और जब परस्पर युद्ध में फंसे रहने और एक–दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहने से, वे 'रूसी मामलों' में मजबूती से दखल नहीं दे सकते थे और सक्रिय रूप से अक्टूबर क्रांति का विरोध नहीं कर सकते थे.

अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने सर्वहारा अधिनायकत्व कायम किया और विशाल देश की हुकूमत का काम मजदूर वर्ग को सौंप दिया. इस तरह से उसे शासक वर्ग बना दिया.

इस तरह अक्टूबर की समाजवादी क्रांति ने मनुष्य जाति के इतिहास में एक नया युग, सर्वहारा क्रांतियों का युग आरम्भ किया.

रूसी क्रांति का ऐतिहासिक सबक

रूसी क्रांति का ऐतिहासिक सबकों के संबंध में दो/चार बातें इस प्रकार हैं:

(1) सर्वहारा क्रांति की विजय, सर्वहारा अधिनायकत्व सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी के बिना असंभव है. सिर्फ नयी तरह की पार्टी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी (अभी मा–ले–माओवादी पार्टी), सामाजिक क्रांति की पार्टी, पूंजीपतियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए सर्वहारा को तैयार कर सकने वाली और सर्वहारा क्रांति की विजय संगठित कर सकने वाली पार्टी ही ऐसी पार्टी हो सकती है;

(2) मजदूर वर्ग की पार्टी वर्ग नेता की अपनी भूमिका तब तक पूरी नहीं कर सकती, जब तक कि वह मजदूर आंदोलन के आगे बढ़े हुए सिद्धांत (अभी मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी सिद्धांत) में माहिर नहीं होती.

मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांत समाज के विकास का विज्ञान है, मजदूर–किसान व मेहनतकशों के आंदोलन का विज्ञान है. विज्ञान की हैसियत से, यह एक जगह रुकता नहीं बल्कि उसका निरंतर विकास होता है. मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांत कठमुल्लापन नहीं है, बल्कि काम करने के लिए मार्ग–दर्शक है;

(3) पार्टी मजदूर वर्ग की हिरावल भूमिका पूरी नहीं कर सकती यदि सफलता से बदहवास होकर उसमें घमंड आ जाये, वह अपने काम में दोष न देखे, अपनी गलतियां मानने से और समय रहते खुलकर और ईमानदारी से उन्हें सुधारने से डरे. पार्टी अजेय होती है यदि वह आलोचना और आत्मालोचना से न डरे, यदि वह अपने काम में गलतियों से सबक लेकर कार्यकर्ताओं को सिखाये–पढ़ाये और यदि वह समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना नहीं जानती, जब तक मजदूर वर्ग की पार्टी अपनी ही कतारों में उत्पन्न होने वाले अवसरवादियों के खिलाफ लगातार कड़ा संघर्ष नहीं करती, जब तक अपने ही भीतर पैदा होने वाले समर्पणवादियों का मुकाबला नहीं करती, तब तक वह अपनी कतारों में एकता और अनुशासन कायम नहीं रख सकती. हकीकत में बोल्शेविक पार्टी के आंतरिक जीवन के विकास का इतिहास पार्टी के भीतर अवसरवादी गुटों के खिलाफ अर्थवादियों, मेंशेविकों, त्रास्तकीवादियों, बुखारिनपंथियों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है.

(4) (अ) रूसी क्रांति के पहले कामरेड लेनिन के सामने बतौर एक नमूना पेरिस कम्यून 1871 का विद्रोह था जो शहरों पर कब्जा जमाकर हीं शुरू हुआ था. उसी अनुभव से सबक लेकर कामरेड लेनिन ने रूसी क्रांति के मार्ग के रूप में बगावत

रेड गार्ड्स

का मार्ग अपनाया.

(आ) अतः कहा जा सकता है कि रूसी क्रांति बगावत के जरिए सफल हुई. जिसका अर्थ है पहले शत्रु का अड्डा स्थल शहर पर कब्जा जमाकर बाद में गांवों (देहातों) पर कब्जा जमाना.

पर, रूसी क्रांति के महान नेताओं पहले कामरेड लेनिन और बाद में कामरेड स्तालिन की मृत्यु के बाद रूसी समाजवाद भी टिक नहीं सका. जो अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत–ही दुखद घटना है. कारण निम्न रूप हैः

विदित है कि 21 जनवरी, 1924 में महान लेनिन की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अधीन रूस देश में समाजवाद की अग्रगति का जिम्मा कामरेड स्तालिन के कंधे पर आ पड़ा जो कामरेड स्तालिन के कुशल नेतृत्व ने बखूबी निभाया. जबकि कामरेड स्तालिन के सामने समाजवादी निर्माण–कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था. उन्होंने न केवल रूस में समाजवादी निर्माण कार्य को आगे बढ़या, बल्कि साथ ही साथ विश्व सर्वहारा तथा कम्युनिस्ट आंदोलन में भी नेतृत्व दिया. कामरेड स्तालिन के नेतृत्व में ही रूसी लाल सेना की अभूतपूर्व साहसिक जवाबी कार्यवाही के जरिए दूसरा विश्वयुद्ध के चरम फासीवादी ताकतों के सरगना हिटलर को बुरी तरह से परास्त किया गया और तमाम फासीवादी ताकतों का कमर तोड़ दिया गया. पर, पार्टी में छिपे हुए चरम संशोधनवादी व गद्दार ख्रुश्चेव गुट द्वारा 01 मार्च, 1953 को कामरेड स्तालिन की मृत्यु के बाद पार्टी व सत्ता पर कब्जा जमा लिया गया और पहले पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करके और बाद में रूसी समाजवाद को सामाजिक साम्राज्यवाद में बदल दिया गया. इस तरह से दुनिया के सर्वहारा वर्ग व उत्पीड़ित राष्ट्र व जनता के सामने एक नकारात्मक अनुभव रखा. जिससे महान माओ ने सबक लेकर चीन में समाजवाद को आगे बढ़ाया. रूसी समाजवादी निर्माण कार्य में जो भी भूल व त्रुटि हुई थी उनसे सीख लेकर और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को जारी रखते हुए चीन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को और मजबूत बनाया गया तथा गद्दार संशोधनवादी व पूंजीवाद के राहगीरों को पार्टी से निकाल–बाहर कर दिया गया. पर, समाजवाद का गद्दार देङ–गुट के नेतृत्व में 09 सितंबर, 1976 में कामरेड माओ की मृत्यु के बाद पार्टी व सत्ता पर कब्जा जमा लिया गया और चीन को पहले पूंजीवाद में और अभी साम्राज्यवाद में बदल दिया गया. इस तरह से दुनिया के सर्वहारा वर्ग व उत्पीड़ित जनता के सामने रूस के अधःपतन के बाद समाजवादी चीन का अधःपतन और एक नकारात्मक उदाहरण पेश आया. अब दुनिया के किसी भी देश में समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है और इन दो नकारात्मक अनुभवों से सबक लेकर समाजवादी क्रांतियों को और आगे बढ़ाने व मजबूत बनाने का काम का जिम्मा सच्चे कम्युनिस्टों के कंधे पर आ पड़ा. इस महत्वपूर्ण काम को सही तौर पर निभाने के लिए दुनिया के कम्युनिस्टों को खुद को तैयार करना–ही होगा और इसलिए महान माओ द्वारा चीन में समाजवाद को मजबूत बनाने हेतु जो भी नीतियों को सूत्रबद्ध किया गया उसे गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा और क्रियान्वयन करना होगा. समाजवाद की जीत की दिशा भी स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सारे कुछ को तैयार करना होगा.

रूसी समाजवादी क्रांति का विश्वजनीन तात्पर्य को आत्मसात करें

खूब संक्षेप में कहने से महान रूसी समाजवादी क्रांति का तात्पर्य निम्न रुप में हैः

(अ) विदित है कि वर्ग समाज उदभव के बाद समूची दुनिया के सामाजिक विकास का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है. इस इतिहास के अंदर महान रूसी अक्टूबर समाजवादी क्रांति एक युगांतकारी घटना है. क्यों यह युगांतकारी घटना है. क्योंकि रूसी समाजवादी क्रांति के जरिए पूर्व में हुए तमाम विद्रोह व क्रांति के साथ एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा भी खींची गयी. जैसेः रूसी क्रांति के पहले जितने भी विद्रोह या क्रांतियां हुई, महान माओ के अनुसार, वे सब पुरानी बुर्जुआ जनवादी क्रांति का हिस्सा थी जिसका मूल मकसद था बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में बुर्जुआ समाज या पूंजीवादी समाज की स्थापना करना; और बुर्जुआ वर्ग मजदूर–किसान को लामबंद कर सशस्त्र उपायों में बुर्जुआ क्रांति के जरिए खुद के वर्ग स्वार्थ में ही सामंती समाज को चकनाचूर करते हुए बुर्जुआ या पूंजीवादी समाज की स्थापना करना. पर, उसने देख लिया कि पूंजीवादी समाज स्थापित होने के बाद मजदूर–किसान चुपचाप नहीं बैठे रहे. बल्कि, आगे

आकर 1917 में रूसी समाजवादी क्रांति के जरिए बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग को ही उखाड़ फेंका और मजदूर राज की स्थापना कर लिया. इससे आतंकित होकर बुर्जुआ वर्ग 1917 के बाद से और कहीं भी बुर्जुआ क्रांति का झंडा नहीं लहराया. यानी बुर्जुआ वर्ग बुर्जुआ क्रांति का जिम्मा और नहीं निभाया. अब यानी 1917 के बाद से बुर्जुआ क्रांति के जरिए सामंतवाद को कब्र में डालने का जिम्मा मजदूर वर्ग के कंधे पर–ही आ पड़ा. जिसे राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति यानी नई जनवादी क्रांति के रूप में कामरेड माओ ने परिभाषित किया; और महान रूसी क्रांति के बाद जितने भी क्रांतियां हुई तथा हो रही हैं, वे सब के सब सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में विश्व सर्वहारा क्रांति का हिस्सा बन गया है. और विश्व सर्वहारा क्रांति की दो धाराएं हैं, पहला समाजवादी क्रांति और दूसरा है नई जनवादी क्रांति. समाजवादी क्रांति का मूल मकसद है मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व के अधीन समाजवादी समाज और नई जनवादी क्रांति का मूल मकसद है मजदूर वर्ग के नेतृत्व में 90 प्रतिशत जनता का जनवादी अधिनायकत्व के अधीन नई जनवादी समाज की स्थापना करना; और बाद में नई जनवादी समाज को आगे बढ़ाते हुए सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अधीन समाजवादी समाज की स्थापना करना;

(आ) क्रांति की मूल बात है राजसत्ता पर कब्जा जमाना जो बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है. जिसे हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए.

रूसी क्रांति की धारावाहिकता के अभिन्न अंश के रूप में ही हुई चीनी क्रांति और रूसी व चीनी क्रांति की धारावाहिकता के अभिन्न अंश के रूप में ही जारी भारतीय क्रांति

हमें मालूम है कि साम्राज्यवाद के युग में सर्वहारा क्रांतियों के अनुभवों का निचोड़ निकालते हुए चीन की विशेषताएं और क्रांतिकारी युद्ध के बारे में माओ ने कहा, ''सशस्त्र बल द्वारा राजसत्ता छीनना, युद्ध द्वारा मसले को सुलझाना, क्रांति का केन्द्रीय कार्य और सर्वोच्च रूप है. क्रांति का यह मार्क्सवादी–लेनिनवादी उसूल सर्वत्र लागू होता है, चीन पर और अन्य सभी देशों पर लागू होता है.

लेकिन उसूल एक ही होने पर भी जब सर्वहारा वर्ग की पार्टी उसे अमल में लाती है तो वह अलग–अलग परिस्थितियों के अनुरूप उसकी अभिव्यक्ति के अलग–अलग तरीके अपनाती है. पूंजीवादी देश, जब वे फासिस्टवादी नहीं होते अथवा युद्ध में उलझे नहीं होते तो वे अपने देश के भीतर बुर्जुआई–लोकशाही पर अमल करते हैं; अपने वैदेशिक संबंधों में वे दूसरे राष्ट्रों के उत्पीड़न का शिकार नहीं होते बल्कि खुद दूसरे राष्ट्रों का उत्पीड़न करते हैं. उनकी इन विशेषताओं के कारण, पूंजीवादी देशों के सर्वहारा वर्ग की पार्टी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह

महिला बेटालियन

दीर्घकालीन कानूनी संघर्ष के जरिए मजदूरों को शिक्षित करे तथा अपनी शक्ति का संचय करे और पूंजीवाद का तख्ता अंतिम रूप से उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी करे. उक्त देशों में मसला यह है कि दीर्घकाल तक कानूनी संघर्ष चलाया जाय, पार्लियामेंट को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाय, आर्थिक व राजनीतिक हड़तालें की जाएं, ट्रेड यूनियनों को संगठित किया जाए और मजदूरों को शिक्षित किया जाए। उन देशों में संगठन का रूप कानूनी होता है और संघर्ष का रूप रक्तपातहीन (गैर–फौजी). युद्ध के मसले के बारे में, पूंजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां अपने खुद के मुल्कों द्वारा छेड़े गए साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध करती हैं; अगर इस प्रकार के युद्ध हो तो इन कम्युनिस्ट पार्टियों की नीति ऐसी होती है जो अपने देश की प्रतिक्रियावादी सरकारों को पराजित करने में सहायक हो. जो युद्ध वे करना चाहती हैं, वह गृहयुद्ध होता है जिसकी वे तैयारी कर रही है. लेकिन यह बगावत और युद्ध तब तक नहीं छेड़ना चाहिए जब तक पूंजीपति वर्ग वास्तव में असहाय नहीं हो जाता, जब तक सर्वहारा वर्ग का बहुसंख्यक जन–समुदाय सशस्त्र विद्रोह करने और युद्ध चलाने के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो जाता, तथा जब तक किसान जन–समुदाय स्वेच्छा से सर्वहारा वर्ग को मदद नहीं देता. और जब इस प्रकार की बगावत और युद्ध का समय आ जाएगा, तो पहला कदम यह होगा कि शहरों पर कब्जा कर लिया जाए और फिर देहातों की तरफ बढ़ा जाए, न कि इसके विपरीत कदम उठाया जाए. पूंजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने ऐसा ही किया है, तथा रूस की अक्टूबर क्रांति ने इस बात को सही साबित कर दिया है.

''लेकिन चीन एक भिन्न प्रकार का देश है. चीन की विशेषता यह है कि वह एक स्वाधीन जनवादी देश नहीं है, बल्कि अर्द्ध–औपनिवेशिक और अर्द्ध–सामंती देश है; अंदरूनी तौर पर चीन में लोकशाही का अभाव है और वह सामंती उत्पीड़न का शिकार है, तथा उसके वैदेशिक सम्बंधों में राष्ट्रीय स्वतंत्राता का अभाव है और वह साम्राज्यवादी

उत्पीड़न का शिकार है. इस प्रकार यहां न तो इस्तेमाल करने के लिए कोई पार्लियामेंट है, और न मजदूरों को हड़ताल के लिए संगठित करने के लिए कोई कानूनी अधिकार ही. बुनियादी तौर पर, यहां कम्युनिस्ट पार्टी के सामने न तो यह कार्य है कि वह बगावत अथवा युद्ध शुरू करने से पहले एक लंबे अरसे तक कानूनी संघर्षों के दौर से गुजरे, और न यह कि पहले शहरों पर कब्जा कर लिया जाए और फिर देहातों पर अधिकार किया जाए. उसके सामने जो कार्य है वह इसके एकदम उल्टा है'' (उद्धरण– माओ के 'युद्ध और रणनीति की समस्याएं' नामक लेख से). इस रूप से दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए ही 1949 में महान माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति सफल हुई.

अनुभव हमें सिखाया है कि महान रूसी अक्टूबर समाजवादी क्रांति अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और जनता के क्रांतिकारी संघर्षों की अनिवार्य परिणति थी तथा महान चीनी क्रांति उसी प्रक्रिया की धारावाहिकता थी. अब हमारी भारतीय क्रांति भी अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और जनता के क्रांतिकारी संघर्षों का अभिन्न अंग है. अतः भारतीय क्रांति का भी केंद्रीय कार्य सशस्त्र बल द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा जमाना है. भारत में भी सर्वहारा वर्ग की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए विश्व समाजवादी क्रांति के अनुभवों का, खासकर रूस और चीन की दो महान क्रांतियों के अनुभवों का अध्ययन करना नितांत अनिवार्य है.

चूंकि, भारत एक अर्द्ध–औपनिवेशिक व अर्द्ध–सामंती देश है, इसलिए यहां कि क्रांति के लिए जो तरीका अपनाना होगा, वह है, ''यदि कोई देश किसी साम्राज्यवादी शक्ति या शक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासित हो और एक ऐसा अर्द्ध–सामंती देश हो जहां कि जनता को कोई आजादी या जनवादी अधिकार नहीं हो, वहां सर्वहारा वर्ग की पार्टी बिलकुल शुरू से ही जनता को सशस्त्र संघर्ष के लिए जागृत और गोलबंद करती है. क्रांति की प्रधान शक्ति के रूप में किसान वर्ग रहती है, क्रांति, पिछड़े हुए क्षेत्रों को अपने कामकाज का मुख्य केन्द्र बनाती है, जनसेना और जन मिलिशिया का निर्माण करती है, विस्तीर्ण देहाती क्षेत्रों में निर्भरयोग्य, मजबूत और आत्मनिर्भर आधार क्षेत्रों या मुक्त इलाकों की स्थापना करती है, दीर्घकालीन लोकयुद्ध के दौर से उनका निरंतर विस्तार करती है और प्रतिक्रियावादियों की राजसत्ता पर निर्णायक व विध्वंसक प्रहार करने के जरिए शहरों को घेरकर उनपर अंतिम रूप से कब्जा जमा लेती है तथा समूचे देश में जनता की राजनीतिक सत्ता व राज्य–व्यवस्था की स्थापना करती है.''

भारत में लंबे समय से चली आ रही विभिन्न रूपों की संशोधनवादी लाइन व कार्य क्रम की पृष्ठभूमि में संसदीय चुनाव पर हमारा एक सही दृष्टिकोण व उस अनुसार कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है. इस पर हमारा रणनीति–कार्यनीति दस्तावेज में लिखित अंश के अंतर्वस्तु को गहराई से आत्मसात करना चाहिए और उसके अनुसार स्लोगन व कार्यक्रमों को भी तैयार करना चाहिए. हमें याद रखना है कि चुनाव में भाग लेना या बहिष्कार करने का सवाल अवश्य–ही कार्यनीति से संबंध रखता है. लेकिन ख्रुश्चेव संशोधनवाद के उद्‌भव के बाद, जब संसदीय रास्ता और चुनाव में भागीदारी आधुनिक संशोधनवाद की रणनीति बन गई है, तब इस पहलू के मद्देनजर हम इस सवाल को महज कार्यनीतिक मामला कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते. साथ ही ''अभी पार्टी पहाड़–जंगल इलाके की थोड़ी–सी जगह के अंदर सिमट कर रह गयी है'', ''बहुत सारी जगहों या प्रांतों में पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था हावी हो गयी है'', ''संसदीय व्यवस्था या चुनाव पर जनता में मोह है''– इत्यादि तर्कों तथा दलीलें बेबुनियाद हैं और भारत की ठोस जमीनी वास्तविकताओं से इनका कोई लेना–देना नहीं है.

हमारे देश में ''अब तक के ऐतिहासिक अनुभव ने सिर्फ यही साबित किया है कि जिन्होंने चुनाव में भाग लिया उनमें से अधिकांश या तो संशोधनवादी हो गये हैं या उन्होंने क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष को कानूनी और शांतिपूर्ण मार्गों पर भटका दिया. अतः निष्कर्ष के बतौर हम यह कह सकते हैं कि चुनावों का बहिष्कार हालांकि कार्यनीति का सवाल है, पर भारतवर्ष की ठोस परिस्थितियों में यह रणनीति का महत्व प्राप्त कर लेता है क्योंकि चुनावों में भागीदारी दीर्घकालीन लोकयुद्ध की रणनीति से बिलकुल ही मेल नहीं खाती.

अतः खूब संक्षेप में कहने से हमें अवश्य–हीं भारत की नई जनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए सशस्त्र कृषि–क्रांति तथा दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते पर अडिग रहना होगा.

रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ पर शपथ लें

भारतीय नई जनवादी क्रांति को सफल करें, अपना फौरी, प्रधान व केंद्रीय कर्तव्य पर अडिग रहें

रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ मनाने के दो तरीके होते हैं– एक पेटी–बुर्जुआ संशोधनवादी तरीका और दूसरा क्रांतिकारी तरीका. संशोधनवादी तरीका का मतलब केवल दिखावे के रूप में रूसी क्रांति का और कामरेड लेनिन–स्तालिन का जयगान करना, कुछ लंबा–चौड़ा भाषण देना, पर व्यवहार में उसे कतई लागू नहीं करना. और क्रांतिकारी तरीका का मतलब है केवल दिखावे के रूप में नहीं, बल्कि रूसी क्रांति के तात्पर्य को यानी क्रांति के जरिए सत्ता पर काबिज होने का कर्तव्य को अपना–अपना देश की विशेषता के अनुसार आगे बढ़ाने की शपथ लेना. इसलिए हमें अवश्य–ही संशोधनवादी तौर–तरीके का कड़ा विरोध करना होगा और क्रांतिकारी तौर–तरीके के अनुसार

रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ मनाना होगा.

रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें भी यही शपथ लेनी चाहिए ताकि भारतीय क्रांति की मौजूदा चुनौतियों का तथा मोदी सरकार की हर फासीवादी नीति व कार्यवाहियों का साहस के साथ मुकाबला कर एक नया जनवादी भारत का निर्माण करना और समाजवाद–साम्यवाद की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश करना होगा.

हमारे कर्तव्य

कामरेडो, हमें यह समझ लेना होगा कि मोदी सरकार द्वारा माओवादी पार्टी व माओवादी आंदोलन को पूरी तरह कुचल डालने की योजना, निश्चित रूप से मोदी सरकार का एक प्रमुख काम के बतौर उजागर हुआ है. लेकिन, यह केवल भारत की किसी एक पार्टी की सरकार का अपना मनमौजी निर्णय नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है. क्योंकि भारत के शासक पार्टियां सामंतवाद व साम्राज्यवाद के दलाल हैं. इसलिए चाहे कोई भी पार्टी हो या किसी भी रंग की सरकार क्यों न हो, साम्राज्यवाद खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद का निर्देशन–अनुसार एलआईसी पॉलिसी (या कम तीव्रता वाला युद्ध) के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरह लागू कर रहे हैं. यूपीए जमाने की तुलना में अभी एनडीए जमाने में भी इन नीतियों पर और आक्रामक ढंग से अमल हो रहा है.

ब्राह्ममणीय हिन्दुत्ववादी–फासीवादी मोदी सरकार द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद सहित अन्य तमाम साम्राज्यवादियों व प्रतिक्रियावादियों से हर प्रकार की मदद लेकर ही क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह रौंद डालने के लिए अपनायी जाने वाली तमाम क्रांति–विरोधी पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए हमारा पहला व प्रधान काम है, सीसी से एसी व जन संगठनों के नेतृत्व तक रक्षा करना, पार्टी को और बोल्शेवीकरण करना तथा दुश्मन के चौतरफा हमले का मुकाबला चौमुखी जवाबी हमले के जरिए करने के लिए पूरी पार्टी कतार व लड़ाकू जनता को हर प्रकार से शिक्षित–दीक्षित करना व और बेहतर प्रतिरोधी कार्रवाई चला सके, इसलिए सैनिक प्रशिक्षण बढ़ाएं ताकि जवाबी हमले को सही मायने में जनयुद्ध के रूप में बदल दिया जा सके. हमें अवश्य–ही राजनीतिक–सांगठनिक व सैनिक तैयारियों के काम को एक अभियान के बतौर आगे बढ़ाना होगा, सैनिक हमले का जवाबी प्रतिरोधी लड़ाई, दुष्प्रचार का जवाबी प्रचार अभियान व ज्वलंत जन–समस्याओं को लेकर जन–आंदोलन का निर्माण आदि के लिए हमें जी–तोड़ प्रयास चलाना होगा. साथ ही साथ तमाम प्रगतिशील–जनवादी शक्तियों सहित ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी शक्तियों के खिलाफ तमाम मित्र शक्तियों से मिलकर आंदोलन के निर्माण के लिए प्रयास करते रहना होगा. अखिल भारतीय स्तर पर यथासंभव शीघ्र एक संयुक्त मोर्चा या विशाल मंच का गठन कर देश की जनता के सामने रखने की जरुरत है.

कामरेडों, भारतीय क्रांति की अग्रगति के अगले दौर को भारी चुनौतीभरी परिस्थिति का सफलतापूर्वक मुकाबला करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं. इसलिए हमें हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने हेतु सभी प्रकार की तैयारियां पूरी करनी होगी. इसका मतलब है, उल्लेखित जितने किस्म की कर्त्तव्यों की बातों का जिक्र किया गया है तथा उसे पूरी तरह से कार्यान्वित करना हमारा फौरी व अहम् कर्त्तव्य है.

ऐसा करके ही हम क्रांति के तीन जादुई हथियार यानी पार्टी, जनसेना व संयुक्त मोर्चा के निर्माणों को सुदृढ़ व लगातार मजबूती प्रदान कर सकते हैं. हमें याद रखना है कि पार्टी को सही अर्थ में बोल्शेवीकरण किये बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. आवें, हर प्रकार की कमी,–कमजोरी को केवल कथनी में ही नहीं, करनी में दूर हटाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं और पार्टी की अंदरूनी एकता को आंख की पुतली जैसी रक्षा करते हुए उसे और मजबूत बनाएं तथा हर प्रकार के संशोधनवाद, चाहे 'वाम' संशोधनवाद हो या दक्षिण, उसे परास्त करते हुए पार्टी की सही लाइन, नीति व कार्यशैली का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करें.

निस्संदेह, रास्ता टेढ़ा–मेढ़ा, कठिन व जटिल है, पर मा–ले–मा व पार्टी लाइन पर अडिग रहने से हम सारी बाधाओं को लांघते हुए भारत की नई जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आधार इलाकों के निर्माण के लिए 'गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध' में बदल डालो, 'पीएलजीए को पीएलए' में बदल डालो' जैसे अहम व फौरी कर्त्तव्य को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं.

आवें, महान शहीदों के अधूरे कार्यों व सपनों को पूरा करने हेतु साहस के साथ वर्गयुद्ध के मैदान में कूद पड़ें.

इतिहास गवाह है कि अंतिम जीत जनता की ही होगी. रात के अंधेरे के बाद भोर की उजाला होगी ही. भारतीय क्रांति सफल होगी ही यानी पहले नव जनवादी क्रांति और इसके तुरन्त बाद समाजवादी क्रांति भी सफल होगी ही.

रूसी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ के तात्पर्य को सही मायने में केवल भारत की नई जनवादी क्रांति में तेजी लाकर व उसे सफल बनाकर ही तथा क्रांति का अगला कदम समाजवादी समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ाकर ही सही रूप से मनाया जा सकता है यही पार्टी का आह्वान है.

★

नोटबंदी का एक साल

कॉरपोरेट आबाद–अर्थ व्यवस्था बर्बाद

मोदी के विमुद्रीकरण और पुनरमुद्रीकरण की जन विरोधी नीति को अमल में आए इस 8 नवंबर को एक साल पूरा हो गया है. नोटबंदी के एक साल पूरा होने के अवसर पर एक ओर सत्तारूढ़ भाजपा ने देश भर में उसकी विजय का जश्न मनाया तो विपक्षी कांग्रेस ने बरसी मनाते हुए 8 नवंबर, 2017 को 'काला दिवस' घोषित करके देश के कई इलाकों में धरना–प्रदर्शन करके विरोध जताया. सबके अपनी–अपनी डफली, अपने–अपने राग.

आएं! इस मौके पर देश की अर्थ व्यवस्था एवं जन जीवन पर इसके असर एवं पक्ष, विपक्ष के तर्क–वितर्कों व कुतर्कों की असलियत पर नजर दौड़ाते हैं.

आंकड़ों के आइने में असलियत को परखें:

नोटबंदी के पहले देश में मौजूद 'कालाधन' के बारे में कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं था. 2012 में संसद में रखे गए श्वेत पत्र में नकद में बड़ी मात्रा में कालाधन होने को लेकर कोई बात नहीं कही गयी थी. नकदी और बैंक खातों में जमा रकम को लिक्विड वेल्थ माना जाता है. भारत में कुल लिक्विड वेल्थ में नकदी का हिस्सा केवल 14 फीसदी है जो 1950 में 50 फीसदी थी. मोदी की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि करीब 10–11 लाख करोड़ रुपए बैंको में लौटेंगे. सुप्रीम कोर्ट सहित देश की जनता को दिग्भ्रमित किया गया कि 4–5 लाख करोड़ 'कालाधन' बैंकों में जमा नहीं होगा और अर्थ व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा. अब इसका 99 फीसदी हिस्सा बैंकों से गुजरकर हाथों में वापस पहुंच जाएगा. ज्ञात रहे रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि 500 एवं 1000 रुपए के नोटों के कुल राशि 15.44 करोड़ में से 15.28 करोड़ वापस बैंकों में जमा हो गई है. यदि हम मानते हैं कि कालाधन बैंकों में जमा नहीं हुआ तब यह मानना पड़ेगा कि सिर्फ 16 हजार करोड़ कालाधन ही देश में था. कालाधन को समाप्त करने के लिए नोटबंदी वाली बात मोदी का झूठ थी. दूसरे मायने में यह भी कहा जा सकता है कि देश की अघोषित आय घोषित हो गयी. काले धन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गयी.

नोटबंदी से भ्रष्टाचार के खात्मे का जहां तक सवाल है, यह सफेद झूठ ही साबित हुआ. रोज नए–नए घोटाले तो उजागर हो ही रहे हैं. भ्रष्टाचार के पुराने रूप तो बेरोकटोक जारी हैं. ऊपर से नोटबंदी भ्रष्टाचार के नए नमूने लेकर आयी. इसने बैंक अधिकारियों को पांच महीनों के लिए सुल्तान बना दिया था. नोटों की अदला–बदली में बैंकिंग तंत्र भ्रष्ट हो गया और जन धन ध्वस्त हो गया था.

नोटबंदी का एक और उद्देश्य जाली नोटों पर लगाम लगाना बताया गया. साथ ही बड़े नोटों के प्रचलन को कम करना. लेकिन सच यह है कि नोटबंदी के बाद 19.53 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए. जाली नोटों को पकड़ने का काम पहले भी चलता रहा. नोटबंदी के बाद भी यह जारी है. 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद उनसे भी बड़े 2000 रुपए के नोट छापे गए. अब जाली नोट बनाने वाले 2000 के नोटों को भी छाप रहे हैं. और यह छपाई नोटबंदी के बाद काफी बढ़ गयी. अतएव जाली नोटों को अर्थ व्यवस्था से बाहर करने मोदी का दावा भी खोखला ही साबित हुआ.

मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने अगस्त, 2017 में यह झूठ फैलाया कि नोटबंदी के कारण जनधन योजना में खोले गए जीरो बैलंस अकाउंट कम हुए हैं. सच्चाई पर नजर डाले तो यह साफ हो जाता है कि सितंबर 2014 में जीरो बैलंस अकाउंट 76.81 फीसदी थे. जबकि अगस्त 2017 में यह आंकड़ा 21.41 फीसदी हो गया. इतना ही कह देने से मोदी का झूठ पकड़ में नहीं आएगा. सच यह है कि 26 सितंबर 2017 को ही यानी नोटबंदी के कई सप्ताह पहले ही यह आंकड़ा घटकर 24.1 फीसदी पर आ चुका था. नोटबंदी से परे जीरो बैलंस अकाउंट कम हो रहे थे.

नोटबंदी से वित्त वर्ष 2016–17 में आरबीआई (रिजर्व बैंक) का बैलंस 53.46 प्रतिशत घटकर 30,659 करोड़ रह गया था. देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व निजी बैंकों को अथाह मुनाफा पहुंचाने की कवायद में रिजर्व बैंक को भारी मात्रा में चपत लगायी गयी.

नोटबंदी से मानो पूरा देश ही बैंकों व एटीएम के आगे लाइन में खड़ा हो गया. लोगों को अनगिनत तकलीफें हुई. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के शुरुआती दस दिनों में ही लाइन में 33 लोगों की मौत हो गयी थी. नोटबंदी के दौरान पूरे देश में कुल 107 लोगों की मौत होने की रिपोर्टें आयीं. दूसरी ओर शुरुआती तीन महीनों तक बैंकों ने नोट बदलने के सिवाय कोई दूसरा मुख्य काम ही नहीं किया.

यह सर्वविदित है कि देश में 60 फीसदी से ज्यदा आबादी निम्न और मध्यम वर्ग से है. नोटबंदी से सबसे ज्यादा यही वर्ग प्रभावित हुआ. रोजगार सिर्फ 20 से 30 फीसदी ही रह गए. महंगाई बढ़ गयी. एक ओर आयात में 23 फीसदी की वृद्धि तो दूसरी ओर विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावटदर्ज की गयी. जबकि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ

11.7 फीसदी से 5.1 फीसदी की उतार देखी गयी. नोटबंदी जनता की गाड़ी कमाई से अमीरों को और अमीर बनाने की साजिश थी. स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने से अमीर खुश हो गए.

अर्थ व्यवस्था पर असरः

मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली नोटबंदी का अर्थ व्यवस्था पर सकारात्मक असर होने का दंभ भर रहे थे. जबकि वास्तविकता ठीक उल्टा है. नोटबंदी से अर्थ व्यवस्था का दम घुट गया. सरकार ने स्वयं ही अपने 7.1 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को कम कर लिया था. आरबीआई ने भी ग्रोथ रेट कम रहने का अनुमान लगाया था. नोटबंदी के बाद 12 माह में 7.9 फीसदी से जीडीपी 5. 7 फीसदी पर पहुंची. यह पिछले तीन वर्ष का निचला स्तर था. आयात के बढ़ने व निर्यात के घटने से व्यापारिक घाटा 23 बिलियन डालर से 41 बिलियन डालर तक बढ़ गया. एनआईपीएफपी के आकलन के मुताबिक नए नोटों की छपाई, जीडीपी में गिरावट, रिजर्व बैंक व बैंकों को हुए नुकसान, छोटे व मध्यम स्तर की कंपनियों को हुई घाटा, रोजगारी में कमी, कार्य दिवसों का नुकसान कुल मिलाकर नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को 12 लाख करोड़ रुपए की चपत लगाई है. यहां यह गौर करने वाली बात है कि जीएसटी के नुकसानों को इसमें जोड़ा नहीं गया है. नोटबंदी से सरकारी योजनाएं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं. छोटे कारोबारियों को बांटे जाने वाले कर्ज में काफी कमी आयी.

नोटबंदी के बाद अप्रैल से 5 अगस्त 2017 तक 56 लाख नए करदाता जुड़े हैं जबकि इसी अवधि में पिछले साल 22 लाख करदाता बढ़े. 2016 की तुलना में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 3.21 करोड़ से बढ़कर 3.78 करोड़ यानी 24.7 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई. पर्सनल इनकम टैक्स एडवांस्ड कलेक्शन में 41.79 प्रतिशत वृद्धि हुई. पिछले साल की तुलना में 34.25 प्रतिशत सेल्फ असेसमेंट टैक्स बढ़ गया. अप्रैल–अक्टूबर में प्रत्यक्ष कर संग्रह से खजाने में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4.39 लाख करोड़ जमा हो गए. ई–पेमेंट 13.5 प्रतिशत बढ़ गया. इससे साफ है कि नोटबंदी से सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में आवक बढ़ गयी.

कृषि क्षेत्रः

कृषि क्षेत्र की विकास दर जो नोटबंदी के समय 7 थी, वह 2.34 प्रतिशत पर आ गयी. एक वर्ष में 24 लाख करोड़ रुपए की पैदावर होती है जो जीडीपी का 17.9 प्रतिशत है. अप्रैल से जून 2017 के बीच कृषि उपज की कीमतें पिछले साल की तुलना में 2 प्रतिशत गिर गयी. अब स्थिति यह है कि कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी से निपटने के लिए आगामी 15 वर्षों तक हर साल दसियों लाख नौकरियों का सृजन करना होगा जोकि इस लुटेरी सरकार के लिए असंभव है.

चूंकि कृषि एवं ट्रांसपोर्ट नकद के व्यापार हैं, इसलिए नोटबंदी के बाद देश के किसान अपनी कृषि उपज विशेषकर खरीफ फसलों का 25 से 50 प्रतिशत हिस्सा बेच नहीं सकें. इतना ही नहीं, कृषि उपजों की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गयी. रबी की बुआई भी काफी हद तक प्रभावित हुई. किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया. नतीजतन एक ओर किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला बेरोकटोक जारी रहा तो दूसरी ओर देश के विभिन्न राज्यों–मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ में किसानों ने कर्ज माफी, फसलों के उचित समर्थन मूल्य एवं अन्य मांगों को लेकर जुझारु आंदोलन किए. हालांकि कुछ राज्यों ने कर्ज माफी की नौटंकी रची लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ.

चूंकि नोटबंदी के बाद कैश का इंतजाम पहले शहरों में फिर गांवों में किया गया था, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लान की ग्रोथ रेट में भारी कमी देखी गयी. यह नोटबंदी के शुरुआती 5 महीनों में 12.9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक घट गयी. यहां गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है.

उद्योगः

नोटबंदी के कारण देश के करीबन सवा दो लाख छोटी व मंझोली कंपनियां बंद हो गयी. 80 फीसदी उद्योग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं. 3 करोड़ रोजगार देने वाले एवं जीडीपी में 17 फीसदी हिस्सेदारी वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर जो नोटबंदी के समय 8.3 प्रतिशत थी, 5 गुना कम होकर मार्च 2017 में 1.6 प्रतिशत तक पहुंच गई. आरबीआई के अनुसार नोटबंदी के बाद की पहली तिमाही में 25 करोड़ से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों के उत्पदों की बिक्री में 57.6 फीसदी की गिरावट आयी थी. एक साल पहले इनकी विकास दर 10. 6 फीसदी थी. आज भी माइक्रो, स्माल अैर मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर्स अपनी पुनरुत्थान के लिए जूझ रहे हैं.

देश के 8 प्रमुख शहरों में किए गए सर्वे के अनुसार नोटबंदी के बाद मकानों की बिक्री में 41 प्रतिशत कमी आयी. नए प्रोजेक्टों को लॉच करने में तो 61 प्रतिशत कमी आयी. हाउसिंग लोन ग्रोथ में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी. कुल मिलाकर रिअल एस्टेट व्यापार में 60 प्रतिशत की कमी आयी जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा. लाखों अस्थायी मजदूर काम से वंचित हो गए.

सेवा क्षेत्रः

नोटबंदी के बाद बैंक खातें और लेन–देन यानी ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ने से बैंकों के कारोबार में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई. बैंक अपने ग्राहकों से मिनिमम बैंक बैलेंस चार्ज, एटीएम कार्ड फीस, चेक की फीस, एसएमएस चार्ज, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्ज, कार्ड स्वाईप चार्ज, बैंक स्टेटमेंट चार्ज आदि कई किस्म के चार्ज लेते हैं. न्यूनतम बैलंस पर फाइन का प्रावधान किया गया है जोकि आम जनता को परेशान करने वाला है. कुछ ट्रांजेक्शन एटीएम से करने के बाद चार्ज वसूला जा रहा है. सामान खरीदने पर कार्ड से पेमेंट करते समय सरचार्ज लगाया जा रहा है. पीओएस यानी स्वाइप मशीनों का किराया और ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में बैंक वाले 500 से 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं. 80 प्रतिशत लोग ट्रांजेक्शन चार्ज से हलाकान हैं. 1 जुलाई से यानी जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से हर चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त लिया जा रहा है. बैंकों में तीन लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं.

डिजिटल/कैशलेस इकॉनॉमी लोगों की जेबें खाली करने की नौटंकी भर है. नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों की संख्या दोगुनी होकर 70 हो गयी है. स्वाइप मशीनों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गयी. एक साल में ऑनलाइन पेमेंट 57 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. इससे लोगों की जेबों से बैंको को टैक्स के रूप में बड़ी रकम मिलेगी. देश को जल्द से जल्द कैशलेस बनाने के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट की मशीनें बेचने वाली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने मशीनों की ताबड़तोड़ खरीदी की गयी. अफसरों के बीच कैशलेस गांव घोषित करने की होड़ सी मची थी. लेकिन जमीनी सच्चाई जानने के लिए छत्तीसगढ़ के कुंदरु पंचायत के सरपंच यश्वंत वर्मा और रायखेड़ा के सरपंच बबलू भाई के बयान काफी हैं. वर्मा ने कहा, 'जिला पंचायत के अफसर कह गए कि यह गांव आज से कैशलेस है. मुझे भी नहीं बताया कि यह क्या होता है?' बबलू भाई ने कहा, 'हमें बाद में पता चला कि हमारा गांव भी कैशलेस है. कोई डिजिटल पेमेंट नहीं होता. पता ही नहीं है'. साल भर बाद की स्थिति पर बात बदलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेट्ली ने कहा कि देश को कैशलेस नहीं लेस कैश इकॉनॉमी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया था. नोटबंदी के बाद सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पिछले तीन साल में पहली बार कम हुई.

रोजगारः

सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी के सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि नोटबंदी के बाद जनवरी से अप्रैल, 2017 के बीच देश में कुल 15 लाख नौकरियां खत्म कर दी गयी. यानी करीबन 75 लाख लोगों की रोजी–रोटी छिन गयी. सभी क्षेत्रों में मिलाकर देश भर में नोटबंदी के बाद से अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं. 73 फीसदी निर्माण क्षेत्र में नौकरी देने वालों ने यह भी कहा था कि जुलाई से अगस्त तक कोई नई नौकरी नहीं दे सकते. देश में लगभग 2.85 लाख चार्टर्ड अकाउंटंट्स–सीए हैं. नोटबंदी से इनकी मांग 25 प्रतिशत बढ़ गयी.

पक्ष–विपक्ष के असत्य व अर्ध–सत्यः

मोदी ने नोटबंदी से काला धन पर रोक लगने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने, जाली नोटों के बंद होने व आतंकवाद के कम होने का दावा किया. भाजपा द्वारा नोटबंदी को ऐतिहासिक कहे जाने के जवाब में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को भाजपा सरकार की सबसे बड़ी भूल और संगठित लूट करार दिया और 8 नवंबर को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी काला दिन कहा. आईसीआईसीआई बैंक की चीफ एक्जीक्यूटिव चंदा कोचर के इस बयान से कि नोटबंदी से बैंकों की ताकत बढ़ेगी व दूसरे सेक्टर्स भी छोटे कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे एवं म्युचुअल फंड व इंश्योरेंस में फंड्स का फ्लो बढ़ा, नोटबंदी की सच्चाई स्वयमेव उजागर हो गयी. पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने प्रेस से कहा कि वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे. इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है, कंपनियों का धंधा चौपट हो सकता है. अर्थशास्त्र के नोबल विजेता अमर्त्य सेन ने नोटबंदी को निरंकुश कार्रवाई करार दिया. सीपीआईएम सचिव सीताराम येचूरि ने कहा कि मोदी की इस राष्ट्र विरोधी कदम को भारत कभी माफ नहीं करेगा.

सत्ता पक्ष के सारे दावे ही सफेद झूठ हैं. विपक्ष चाहे कोई भी दल क्यों न हो अर्ध सत्य ही कह रहे हैं. नोटबंदी के पीछे की असलियत को उजागर न कर रहे हैं न कर सकते हैं और वे न कभी करेंगे. क्योंकि वे सभी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं. अर्थशास्त्र के नोबल विजेता अमर्त्य सेन हो या कोई और उदारपंथी जनवादी बुद्धिजीवी या अर्थशास्त्री, इस दुनिया को पूरी तरह बदलना नहीं चाहते हैं. इसी व्यवस्था के दायरे में कुछ छोटे–मोटे बदलावों, सुधारों तक ही सीमित होकर रहना चाहते हैं.

उपरोक्त आंकड़ों से यह सच्चाई अपने–आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. मोदी ने नोटबंदी के जो कारण गिनाए, वो सिर्फ और सिर्फ देश की उत्पीड़ित जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ही है. मोदी ने जान बूझकर झूठे कारण बताए ताकि लोगों का ध्यान अपने ढाई साल के शासन काल की विफलताओं से भटका सके और भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में व्याप्त आक्रोश को भुना सके. 'सबका साथ, सबका विकास', 'विदेशी बैंकों में छुपाकर रखे गए काला धन को वापस लाकर प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने', 'भ्रष्टचार मुक्त भारत' आदि जुमलों से निजात पा सके और पांच राज्यों के तत्कालीन चुनावों में विजय हासिल कर सके.

दरअसल नोटबंदी बहुत बड़ी साजिश थी. अवैध कमाई

प्रेस वक्तव्य

दिनांकः 30 अक्तूबर, 2017

वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी!

विरोध के स्वर को दबाने की भाजपा सरकारों केफासीवादी चरित्र व आचरण की ही निरंतरता है!

वरिष्ठ पत्रकार एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य विनोद वर्मा की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है और देश भर के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों व प्रगतिशील–बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि वे इस घोर फासीवादी कदम के विरोध में आवाज बुलंद करें.

यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी गिरती साख बचाने, अपने लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के भ्रष्ट व अवैध–अनैतिक व्यवहार पर परदा डालने की कोशिश के तहत अपनी पुलिस द्वारा झूठे व मनगढ़ंत आरोपों में उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकारों के संपूर्ण सहयोग से विगत 27 अक्तूबर को गाजियाबाद स्थित उनके निवास से विनोद वर्मा को आधी रात अवैध तरीके से गिरफ्तार करवायी है. अपने बेईमान, नीच व घृणित करतूतों वाले मंत्री को बर्खास्त व गिरफ्तार करने की बजाए उनके बचाव में पत्रकार के खिलाफ साजिश रचकर मुख्यमंत्री रमण सिंह ने अपनी सरकार के जन विरोधी, भ्रष्ट, अनैतिक, अवैध, चरित्र व आचरण का स्वयं एक बार और पर्दाफाश किया है. उग्र हिन्दुत्व विचारधारा वाले संघ परिवार की भाजपा सरकारों का चरित्र व आचरण फासीवादी है. उनकी जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के हीन चरित्र, घोटालों, अवैध संबंधों, अनैतिक आचरण आदि के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का सिलसिला भाजपा शासित राज्यों में पिछले तीन सालों से तेज गति से बढ़ा है. आयकर विभाग जैसे केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न जांच एजेन्सियों द्वारा फर्जी केसों में फंसाने, पुराने लंबित या बंद पड़े मामलों को नए सिरे से शुरु करने के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों, प्रगतिशील–जनवादी पत्रकारों, जनता के प्रति संवेदनशील अधिकारियों को जेल भेजने, नौकरियों से निलंबित या बर्खास्त करने के तानाशाहीपूर्ण तरीके अपनाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, भाजपा सरकारों के संपूर्ण संरक्षण व सहयोग से देश भर में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की ताकतें दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, ईसाइयों सहित प्रगतिशील–जनवादी लेखकों, बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों पर लगातार हमलें कर रही हैं. विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजना इसी का हिस्सा है जिसके खिलाफ सभी को सड़कों पर उतरना चाहिए.

विकल्प

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

को वैध बनाने का तरीका था. कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों को रफा–दफा करने की योजना के तहत उठाया गया कदम था. यानी उनके द्वारा बैंकों से लिए गए भारी कर्जों जिन्हें वे कभी पटाना नहीं चाहते हैं, को माफ करने का वैध रास्ता नोटबंदी के नाम से खोजा गया. दिवालिया होने वाले बैंको को पुनर्जीवन प्रदान करना, दोबारा कॉरपोरेट दिग्गजों को कर्जा उपलब्ध कराना, इसका मकसद है. यहां यह बताना लाजिमी होगा कि 3 लाख करोड़ की संपत्ति वाले अंबानी, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वाले अदानी जो देश के दलाल बड़े पूंजीपती हैं, के करीबन 81 हजार करोड़ रुपयों के कर्ज माफ करने की कोशिशें जारी हैं. एक साल फसल ऋण न पटाने पर घर के दरवाजे उखाड़ ले जाकर किसान के इज्जत को नीलाम करके उसे आत्महत्या के लिए विवश करने वाले बैंक, एक महीने का बिजली बिल न पटाने पर घर का बिजली कनेक्शन काटने की व्यवस्था अपने विभाग को देने वाली सरकार कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफी के प्रति इतना उदार क्यों है? क्या इससे यह साफ जाहिर नहीं होता है कि ये सरकारें देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व सामंती ताकतों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं?

नोटबंदी से देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाया गया. जनधन को जबरन बैंकों में जमा कराया गया. बैंकों के कारोबार को बढ़ा दिया गया. सरकारी खजाने को भरने की कोशिश की गयी. आम आदमी व देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की कीमत पर कॉरपोरेट को आबाद करने का जन विरोधी व देश विरोधी कदम ही था, नोटबंदी.

इसीलिए शोषक–शासक वर्गों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित, जुझारु व मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा. लुटेरे वर्गों की राज्यसत्ता को उखाड़ फेंककर, शोषण विहीन समतामूलक समाज व्यवस्था को हासिल करने के लिए हथियारबंद लड़ाई के रास्ते आगे बढ़ना होगा. ★

पीएलजीए की 17वीं स्थापना वर्षगांठ जोर–शोर से मनी!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के आह्वान पर 2 से 8 दिसंबर तक जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) की 17वीं स्थापना वर्षगांठ दण्डकारण्य के गांव–गांव व गली–कस्बों में शानदार ढंग से मनायी गयी. इन समारोहों में तमाम पार्टी कमेटियां, सदस्य, पीएलजीए के लाल कमांडर व योद्धा, जन मिलिशिया बल, क्रांतिकारी जनताना सरकारों एवं जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ता तथा उत्पीड़ित जनता जोशो खरोश के साथ शामिल हुई.

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन के सफाए के लिए 2009 से चलाए जा रहे देशव्यापी फासीवादी सैनिक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के हमलों को 2014 से भाजपा की मोदी सरकार द्वारा तेज करते हुए पिछले साल मिशन–2016 संचालित की गयी थी जिसे पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए, जन सरकारों, जन संगठनों एवं जनता ने हिम्मत व साहस के साथ लड़कर परास्त किया था. इस साल चलाए गए मिशन–2017 का भी कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान एवं प्रतिरोध कार्यक्रमों के जरिए डटकर मुकाबला करते हुए उसे रोका गया. पार्टी, पीएलजीए एवं जनता द्वारा देश भर में संचालित राजनीतिक, सांगठनिक व सैनिक कार्यों ने केंद्र व राज्य सरकारों को मिशन–2017 की जगह नयी प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी रणनीतिक योजना 'समाधान' (2017–22) बनाने मजबूर किया.

पिछले साल भर में दण्डकारण्य में पीएलजीए द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए चार बड़े हमलों–कोत्ताचेरुवु, बुरकापाल, कारमपल्ली व तोंडामरका सहित कइयों छोटी कार्रवाइयों में 75 पुलिस, अर्धसैनिक, कमांडो व डीआरजी बलों का सफाया किया गया जबकि 115 को घायल किया गया जिनसे 21 एके–47 रायफलों सहित 35 आधुनिक हथियार, 3,500 कारतूस व अन्य सामग्री जब्त की गयी. पीएलजीए की इन शानदार सफलताओं व उन्हें हासिल करने के लिए अपनी जानें कुरबान करने वाले वीर शहीदों की शहादत को ऊंचा उठाते हुए उनके आदर्शों पर चलने के बारे में पीएलजीए की इस स्थापना वर्षगांठ के दौरान जनता के बीच में पर्चा, पोस्टर, पुस्तिका, नुक्कड़ सभाओं, रैलियों, आमसभाओं आदि के जरिए व्यापक रूप से प्रचार किया गया. इस मौके पर दुश्मन की दिवालिया आत्मसमर्पण नीति को लात मारते हुए, पीएलजीए को संगठित व मजबूत करने के लिए आगामी दिसंबर एवं जनवरी महीनों में भर्ती अभियान संचालित करके युवाओं को बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती करने का दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने पार्टी, पीएलजीए व जनताना सरकारों की कतारों का आह्वान किया है. न सिर्फ स्थापना वर्षगांठ सप्ताह के दौरान बल्कि आगे भी प्रतिरोध को लगातार जारी रखने, दुश्मन बलों का सफाया करके हथियार जब्त करने, जनता पर निर्भर करके व जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ छापामार युद्ध–जनयुद्ध को तेज करके नयी प्रतिक्रांतिकारी दमन योजना 'समाधान' का सामना करने व उसे हराने स्पेशल जोनल कमेटी ने पीएलजीए के तीनों बलों व उत्पीड़ित–संघर्षशील जनता का आह्वान किया है.

वर्षगांठ सभाओं का आयोजन करीबन सभी पंचायत स्तर की जनताना सरकार इलाके के गांवों में किया गया. परिस्थिति को नजर में रखकर कइयों जगह तीन जनताना सरकार इलाकों के गांवों की जनता को इकट्ठा करके सभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं में सीएमसी द्वारा जारी संदेश को जन–जन तक पहुंचाया गया.

जनता के बीच में यह प्रचारित किया गया कि 2 दिसंबर, 2000 को गठित पीएलजीए–जन मुक्ति छापामार सेना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में उत्पीड़ित वर्गों यानी मजदूर, किसान, छोटे पूंजीपति, देशी पूंजीपति जनता को शोषण और दमन से मुक्त करके नवजनवादी राज्य सत्ता स्थापित करने के लिए शोषक–शासक वर्गों यानी सामंती वर्ग, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग एवं साम्राज्यवादियों की सशस्त्र ताकत के खिलाफ जनयुद्ध संचालित कर रही है. वह जनता के जल, जंगल, जमीन व संसाधनों को बचाने के लिए युद्ध करती है. आदिवासी जनता के अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है. वह पार्टी, क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जन संगठनों एवं जनता की सुरक्षा के लिए लड़ रही है. वह दुश्मन की प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक, फासीवादी हमले की योजना 'समाधान' को हराने के लिए लड़ रही है.

पीएलजीए द्वारा पिछले साल भर में हासिल सफलताओं खासकर कोत्ताचेरुवु, बुरकापाल, तोंडामरका, कारमपल्ली घटनाओं, दुश्मन बलों के सफाए व हथियारों की जब्ती के बारे में एवं हमारे शहीद साथियों के लड़ाकू जीवनी एवं उनकी कुरबानियों के बारे में व्यापक रूप से प्रचार किया गया. पीएलजीए सप्ताह से शुरु करके पूरे दो माह–दिसंबर एवं जनवरी तक भर्ती अभियान संचालित करने के पार्टी आह्वान को जनता तक ले जाने की भरसक प्रयास कर रही है. पीएलजीए प्रतिरोध को सिर्फ इस सप्ताह के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा जारी रखने, दुश्मन के नेटवर्क को चिह्नित करने, जनता की निगरानी रखने, जब का तब ध्वस्त करने पर जोर देने, छापामार आधार इलाकों में घुसने वाले दुश्मन को अवश्य नुकसान पहुंचाने–घायल करने, मारने, हथियार जब्त करने का संकल्प दोहराया गया.

★

भारत बंद

6 से 12 दिसंबर तक ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ कार्रवाई सप्ताह एवं 12 दिसंबर को भारत बंद सफल!

देश में बढ़ते ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी खतरे के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए देशव्यापी आह्वान के मुताबिक दंडकारण्य में 6 से 12 दिसंबर तक कार्रवाई सप्ताह एवं 12 दिसंबर को भारत बंद सफल बनाया गया है.

केंद्र में जब से ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनी तब से भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर जोर आजमाया जा रहा है. आरएसएस केंद्र एवं राज्य सरकारों, शासन–प्रशासन तंत्र पुलिस, अर्ध सैनिक बलों के प्रत्यक्ष संरक्षण, संवर्धन व मदद से, अपने पांच दर्जन से भी ज्यादा अनुषांगिक संगठनों के जरिए देश के दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों व ईसाइयों, महिलाओं के खान–पान, पहनावा–ओढ़ावा, रीति–रिवाज, आचार–व्यवहार की आदतों, निजी विश्वासों, जीने के अधिकार सहित तमाम जनवादी अधिकारों, यानी उनकी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनशैली पर प्रहार करते हुए उसे तहस–नहस करने पर तुला हुआ है. घर वापसी के नाम पर गरीब मुसलमानों व ईसाइयों का जबरिया ध र्मांतरण जारी है. गोमांस रखने, खाने या उस बहाने मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, उनकी बेदम पिटाई से लेकर हत्या तक करने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है. हेतुवादियों, वामपंथी व जनवादी–प्रगतिशील लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया व खामोश किया जा रहा है.

दूसरी ओर भाजपा की केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को मिट्टी के मोल देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर रही हैं. भाजपा की मोदी सरकार जब से सत्तारूढ़ हुई अपनी कॉरपोरेटपरस्त व जनविरोधी आर्थिक, औद्योगिक, कृषि व मजदूर नीतियों खासकर नोटबंदी व जीएसटी के जरिए जन जीवन को दूभर बना रखी है. किसानों की आत्महत्याएं बेरोकटोक बढ़ रही हैं. मजदूरों का हाल बेहाल है. छंटनी जारी है. छोटे उद्योग तबाह हो रहे हैं. बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है. तमाम सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आने मजबूर हैं. विस्थापन विरोधी जन आंदोलनों व तमाम जनवादी, मानवाधिकार, किसान, मजदूर आंदोलनों पर कहर बरपाया जा रहा है. देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक बनकर मोदी साम्राज्यवाद खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद की सेवा व गुलामी करने के साथ–साथ उसी के हित में युद्धोन्माद, देशभक्ति के नाम पर अंधराष्ट्रवाद फैला रहे हैं. अयोद्या में 6 दिसंबर, 1992 को हिन्दू धर्मोन्मादी ताकतों द्वारा गिरायी गयी ऐतिहासिक बाबरी मसजिद से लेकर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एमएम कलबुर्गी, गौरी लंकेश, अखलाक, ... तक लगातार जारी हत्याओं, उनाकांड से लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लेकर पूरे बस्तर संभाग में वाट्स एप पर 'भैंसासुर के औलादों को . ....' लिखकर आदिवासियों को गाली देने व पिछड़ा आदिवासी बहुल जिला नारायणपुर के रेमावंड गांव में गोमांस खाने से आदिवासियों को जबरन रोके जाने तक के हिन्दुत्व फासीवादी हमलें यही साबित कर रहे हैं कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद आज समस्त उत्पीड़ित जनता की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनशैली, उनके अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसम्मान के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है. सोशल मीडिया–वाट्सअप, फेस बुक आदि पर गाली देने, अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से लेकर सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना, बेदम पिटाई करना, बेरहमी से हत्या करना, धर्मोन्माद भड़काकर भीड़ द्वारा हत्या करवाना बेरोकटोक जारी है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो संसाधनों की कॉरपोरेट लूट, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद, प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी रणनीतिक दमन योजना–'समाधान' आज की भाजपा नीत एनडीए सरकार का असली चरित्र है. इसलिए उसे हराना, खत्म करना अति आवश्यक है. इसी पृष्ठभूमि में उक्त आह्वान दिया गया था.

देश के दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों–मुसलमानों व ईसाइयों, पिछड़ा वर्ग के लोगों, महिलाओं, क्रांतिकारी, प्रगतिशील–जनवादी व धर्मनिरपेक्ष ताकतों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनपक्षधर अधिवक्ताओं, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, कलाकारों को चाहिए कि वे सभी एकजुट होकर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ सभी स्तरों पर व्यापक, मजबूत एवं जुझारु संयुक्त मोर्चों व जन आंदोलनों का निर्माण करने की दिशा में कदम बढ़ाएं.

देश की तमाम उत्पीड़ित जनता को चाहिए कि वह ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ 6 से 12 दिसंबर के 'कार्रवाई सप्ताह' के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी वैचारिक संघर्ष, सांगठनिक कार्य व सैनिक कार्रवाई को लगातार जारी रखें.

इसके तहत ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी आरएसएस –संघ परिवार के तमाम अनुषांगिक संगठनों जैसे एबीवीपी, बीजेवायएम, महिला मोर्चा, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा आदि के खिलाफ वैचारिक, सांगठनिक एवं सैनिक मोर्चों पर संघर्ष संचालित करना चाहिए.

हिन्दुत्व फासीवाद के असली चरित्र, उसके दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, महिला और पिछड़ा वर्ग विरोधी विचारधारा का राजनीतिक रूप से भंडाफोड़ करते हुए जनता के बीच में पर्चा, पोस्टर, पुस्तिका, नुक्कड़ सभाओं, गीत–नृत्यों, जुलूसों व आमसभाओं, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, वाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से लगातार व्यापक प्रचार करना चाहिए. विभिन्न अवसरों पर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी सत्ता केंद्र के प्रतीक नरेंद्र मोदी–अमित शाह–मोहन भागवत की तिकड़ी व रमण सिंह, देवेंद्र फड़णवीस के पुतलों को जनअदालत में रखकर, सार्वजनिक तौर पर फांसी देनी चाहिए.

सांगठनिक तौर पर आरएसएस एवं अन्य हिन्दुत्ववादी संगठनों के फैलाव को हर संभव तरीके से रोकना होगा. संघर्ष इलाकों में घुसने व मजबूत होने के संघ परिवार के सभी कोशिशों को नाकाम करना होगा. उनकी सदस्यता अभियान, शाखाओं के संचालन, रैलियों, सभा–सम्मेलनों आदि के आयोजनों को जन भागीदारी के साथ विफल करना चाहिए. उन्हें संघर्ष इलाकों से खदेड़ने जनता को तैयार करना चाहिए. किसी भी नाम से आकर भाजपा या अन्य संघीय संगठनों का निर्माण या उन्हें मजबूत करने की कोशिश करने वालों को जनअदालत में रखकर संघ परिवार की जन विरोधी नीतियों के बारे में उनसे जवाब–तलब करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए. उत्पीड़ित वर्गों खासकर दलितों, मुसलमानों व आदिवासियों की अपनी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनशैली के बचाव में व्यापक रूप से प्रचार करके बीफ फेस्टिवलों का आयोजन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए. ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार के खिलाफ आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों–मुसलमानों, ईसाइयो, पिछड़ा वर्ग के लोगों, महिलाओं सहित तमाम धर्मनिरपेक्ष व वामपंथी ताकतों को जोड़कर व्यापक, जुझारु व संगठित संयुक्त मोर्चे का सभी स्तरों–गांव, पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तरों पर निर्माण करना चाहिए.

सैनिक तौर पर पार्टी कतारों, पीएलजीए की विभिन्न युनिटों, विभिन्न स्तरों की क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जन संगठनों व उत्पीड़ित–संघर्षशील जनता को चाहिए कि वे भाजपा नेताओं सहित हिन्दू कट्ठरपंथियों के गांवों, कस्बों में घुसने पर उन्हें जन अदालत के कटघरे में खड़ा करके भाजपा के देशद्रोही व जनविरोधी चरित्र एवं जनता के साथ उनके रहन–सहन व व्यवहार के बारे में जवाब–तलब करना चाहिए. दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खान–पान की आदतों, रीति–रिवाजों पर हमलों में, जन आंदोलनों व क्रांतिकारी आंदोलन के दमन में या खिलाफ में किसी भी तरह, किसी भी स्तर पर शामिल दोषी तत्वों को चिह्नित करके उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करनी चाहिए. भाजपा सहित संघ परिवार के सभी संगठनों के गुण्डा तत्वों, जनविरोधी व पार्टीविरोधी तत्वों, विभिन्न जन आंदोलनों व क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से सामने आने वालों, दमन अभियानों में सरकारी सशस्त्र बलों का सहयोग करने वालों, मुखबिरी करने वालों को मार भगाना चाहिए. उनकी गलतियों की तीव्रता के मुताबिक समुचित व आवश्यक सजाएं देनी चाहिए. ★

कृपया प्रभात के लिए डिविजनों से सही समय पर निम्नांकित रिपोर्ट्स जरूर भेजें!

★ *अमर शहीदों की जीवनियां, जिनके साथ तस्वीरें जरूर संलग्न हों.*
★ *पीएलजीए प्रतिरोध*
★ *जन प्रतिरोध विशेषकर महिला प्रतिरोध*
★ *जन संघर्षों की रपटें*
★ *सभा सम्मेलनों की रपटें*

– संपादक मंडल

अमेरिकी साम्राज्यवाद को धिक्कारता उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया पर अमेरिकी हमले के बादल मंडरा रहे हैं. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर सैनिक हमला करने की धमकी दी, तो उत्तर कोरिया ने पलटवार करते हुए कह दिया कि वह अमेरिकी सैनिक अड्डे–गुवाम द्वीप को उड़ा देगा. उत्तर कोरिया ने यह घोषणा की कि अमेरिका की किसी भी जगह पर हमला करने में वह सक्षम है. जबकि श्वेतभवन (व्हाईट हाउज) ने कहा कि उत्तर कोरिया विश्वसभ्यता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 सितंबर को दिए अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी. इस अवसर पर उनके द्वारा उत्तर कोरिया के प्रति पहले की तुलना में बेहद कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया. उत्तर कोरिया के अध्यक्ष किम जोंग उन का मखौल उड़ाते हुए उन्हें 'राकेट मैन' बताया गया. इसकी प्रतिक्रिया में किम जोंग उन ने कहा 'ट्रंप ने मेरा और मेरे देश का दुनिया के सामने अपमान किया और क्रूर युद्ध की घोषणा की. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अमेरिका में सर्वोच्च कमान का विशेष अधिकार संभाल रहे शख्स को यह बयान देने के लिए भारी कीमत चुकाना पड़े. इस पागल बुड्ढे को घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा.' ट्रंप की बातों का कड़ा जवाब उत्तर कोरिया के विदेशी मंत्री रि योंग हो ने भी संयुक्त राष्ट्र में दिया कि दुष्ट अध्यक्ष (ट्रंप) की बातों के बाद अमेरिका पर हमला अपरिहार्य हो गया. इसकी प्रतिक्रिया में ट्रंप ने ट्वीट किया कि किम और रि योंग अब ज्यादा देर जीवित रहने वाले नहीं हैं. इस टिप्पणी के विरोध में उत्तर कोरिया के राजधानी प्यांगांग के किम इल संग स्क्वेयर में अमेरिका के खिलाफ 23 सितंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ. खबरों के मुताबिक इस मौके पर कोरिया रेड गार्ड्स के कमांडिंग अधिकारी रे इल बे ने कहा, 'दुनिया से अमेरिका और दुष्ट अध्यक्ष को हटाने के लिए उस देश से आखिरी जंग करने अच्छे मौके के लिए हम इंतजार कर रहे हैं. अगर किम आदेश देंगे, तो आक्रामणकारियों के खात्मे के लिए हम तैयार हैं'. उपरोक्त टिप्पणियों से यह साफ जाहिर होता है कि एक ओर अमेरिका उत्तर कोरिया पर आक्रमणकारी युद्ध के लिए उतावला है जबकि उत्तर कोरिया अपनी आत्मरक्षा की सारी तैयारियां कर रहा है.

अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया को धमकियां देना और इसके चलते कोरिया प्रायद्वीप में जंग का माहौल बनना कोई नयी बात नहीं है. हालांकि फिलहालं जुबानी जंग और तेज हो गयी है. सतही तौर पर देखने से हमें यह लगता है कि हाल ही में उत्तर कोरिया जो मिसाइल, बालिस्टिक मिसाइल और परमाणु परीक्षण कर रहा है वही इस तनावपूर्ण स्थिति की वजह है. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में अमेरिका ऐसा माहौल निर्मित कर रहा है. यद्यपि यह सही है कि उत्तर कोरिया द्वारा इस वर्ष के 15 सितंबर तक पंद्रह मिसाइलों के परीक्षण किए गए हैं, जिनमें अल्प, मध्यम श्रेणी के अलावा बालिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं. प्रसार माध्यमों के मुताबिक 29 अगस्त को उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर में एक बालिस्टिक मिसाइल दागी. उत्तर कोरिया ने गर्व से घोषणा भी की कि उसने अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया. उतना ही नहीं उसका दावा है कि उसने उस बम को इतना छोटा बनाया कि उसे मिसाइल से जोड़ सकता है. यह माना जा रहा है कि वह उत्तर कोरिया का छठा परमाणु परीक्षण था. जबकि 2016 में ही उसने दो बार परमाणु परीक्षण किया. इस पृष्ठभूमि में इन परीक्षणों को बहाना बनाकर उस देश पर पहले से जारी प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए.. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अत्यंत कड़े प्रतिबंध लागू करने वाले प्रस्ताव को 15 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया. इन प्रतिबंधों के मद्देनजर उत्तर कोरिया के तेल आयात और खादी वस्त्रों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगा. अमेरिका की दलील यह है कि चूंकि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार के निर्माण और

परीक्षण की क्षमता के लिए तेल ही जीवनधारा की भूमिका निभा रहा है, इसलिए अमेरिका ने पहले उत्तर कोरिया के तेल निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया. हालांकि रूस और चीन जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, के हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्रतिबंधों की तीव्रता कुछ हद तक कम हुई. इन प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया के तेल निर्यातों में 30 फीसदी की कटौती हुई. गैस, डीजिल, हेवी फ्यूयेल ऑइल के निर्यात में 55 फीसदी की कटौती होगी. उत्तर कोरिया ने इन पाबंदियों के प्रति न सिर्फ विरोध जताया बल्कि इन पाबंदियों का जवाब और एक बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण से दिया. इन प्रतिबंधों के लगने के ठीक चार दिनों के बाद 15 सितंबर को जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर में इस मिसाइल का प्रयोग किया. अपने आसमान में दो मिनट तक गुजरने वाली इस मिसाइल प्रयोग से जापान भयकंपित हो गया.

इतिहास को नजरअंदाज करके आंखों के सामने घटने वाली घटनाओं का ही आकलन करने से हमें एहसास हो सकता है कि उत्तर कोरिया की गतिविधियां छेड़खानीपूर्ण हैं. लेकिन उन 'छेड़खानीपूर्ण गतिविधियों' के पीछे अमेरिका साम्राज्यवाद के प्रति उत्तर कोरिया का अंतहीन क्रोध है. धिक्कार है. उस अमेरिकी साम्राज्यवाद से लोहा लेने की हिम्मत भी है जिसने कोरिया प्रायद्वीप को लंबे समय तक युद्ध में झोंका था और वहां के जनजीवन को तहस–नहस किया था.

अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच मौजूदा युद्ध के माहौल को समझने के लिए हमें पूर्वी एशिया महाद्वीप के इतिहास में झांकना होगा. कोरियाई प्रायद्वीप पर 1910 में जापान कब्जा जमाया. कोरियाई जनता ने इस कब्जे के खिलाफ न सिर्फ शांतिपूर्ण बल्कि सशस्त्र लड़ाई लड़ी थी. दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद कोरिया के उत्तर प्रांत कामरेड स्तालिन के नेतृत्व वाली लाल सेना और दक्षिण प्रांत अमेरिकी सेना के काबू में गया. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में 1948 में आयोजित चुनाव के बाद ये दोनों प्रांत दो अलग–अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए थे. उत्तर इलाका जो उत्तर कोरिया के नाम से लोकप्रिय हो गया, डेमोक्रैटिक पीपुल्स रिपब्लिक आफ कोरिया के रूप में गठित किया गया. जबकि दक्षिण इलाका जो दक्षिण कोरिया के नाम से लोकप्रिय है, रिपब्लिक आफ कोरिया के रूप में गठित किया गया. उत्तर कोरिया में कोरियाई जनता के राष्ट्रीय नेता किम इल सुंग, जिन्होंने जापान के खिलाफ संचालित जनयुद्ध में प्रमुख भूमिका निभायी थी, के नेतृत्व और तत्कालीन समाजवादी रूस के मार्गदर्शन में समाजवादी सरकार का गठन हुआ. हालांकि उसके बाद दुनियाभर में साम्यवादी सरकारों के पतन की पृष्ठभूमि में उत्तर कोरिया नाम मात्र के कम्युनिस्ट देश के रूप में अस्तित्व में है. जब से देश का आविर्भाव हुआ तब से वहां किम का पारिवारिक शासन ही जारी है. किम इल सुंग के पोते ही हैं, वर्तमान में उत्तर कोरिया के अधिनेता किम जोंग उन. हालांकि उत्तर कोरिया में साम्यवादी शासन की विरासत जारी नहीं है लेकिन अमेरिका साम्राज्यवादी विरोधी विरासत तो मजबूती से बरकरार है.

यहीं पर दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा जानना चाहिए. अमेरिका के प्रति उत्तर कोरिया के विरोध को समझना है, तो अमेरिका–दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में समझना होगा. 1948 में आयोजित चुनाव के बाद दक्षिण कोरिया में सिंगमनरी नेतृत्व में अमेरिका की कठपुतली सरकार का गठन हुआ. एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवादियों की आक्रमणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सिंगमनरी ने विश्वसनीय सेवक की भूमिका निभायी. अकूत संसाधनों का भंडार उत्तर कोरिया को अपनी मुट्ठी में बांधे रखने के लिए अमेरिका दक्षिण कोरिया को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया. 1950 में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ी थी. तीन वर्ष तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा. कोरियाई जनता और चीनी वालंटियरों ने कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका की आक्रामणकारी सेना और उसकी विश्वसनीय सेवक सिंगमनरी की सेना को ठीक सबक सिखाया. हालांकि इस जंग में उत्तर और दक्षिण कोरिया की बुरी तरह तबाही हो गयी. उन दोनों देशों के अलावा अमेरिकी और चीनी सैनिक बड़े पैमाने पर मारे गए. अमेरिकी सेना के जनरल डग्लस मेकार्तर द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में पढ़ी गई रिपोर्ट में लिखा गया, 'पिछले एक वर्ष में ही 20 मिलियन आबादी वाले कोरिया को हमने ध्वस्त किया. इतने विनाश को मैं ने कभी नहीं देखा था. हालांकि इसके पहले मैं ने जितने खूनी बहावों और विनाश को देखा था, शायद ही अन्य जीवित व्यक्ति देखा हों, लेकिन कोरिया में जो विध्वंस हुआ है, वह मुझे बहुत ही विचलित कर दिया. आदमियों, महिलाओं व बच्चों की लाशों के ढेरों को देख कर मैं ने उलटी की. हम ऐसे ही आगे बढ़ने से जन संहार और ज्यादा बढ़ेगा'. और एक अधिकारी कर्टिस लीमे ने लिखा था,'उत्तर और दक्षिण कोरिया के सभी नगरों व शहरों को हमने आग के हवाले कर दिया. 10 लाख तक जनता को हमने मार दिया. उतनी ही तादाद में जनता को हमने गांवों से भगा दिया'. इससे हमें न सिर्फ युद्ध की तीव्रता को समझ सकते हैं बल्कि अमेरिका के प्रति कोरियाई जनता की नफरत के पीछे के कारण को भी समझ सकते हैं. अमेरिका के प्रति सिंगमनरी की गुलामी का अंत इस युद्ध से नहीं हुआ. देश की सारी जनता की आकांक्षाओं के विपरीत 1953 में अमेरिका के साथ सैनिक समझौता करके दक्षिण कोरिया को अमेरिका के सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील किया. हालांकि सिंगमनरी

सरकार के खिलाफ दक्षिण कोरियाई जनता का संघर्ष लगातार जारी रहा. भीषण दमन का इस्तेमाल करके भी इन संघर्षों को रोकने में विफल सिंगमनरी ने 1960 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उसके बाद आयोजित चुनाव में जनता ने सिंगमनरी को हरा कर, पोसुन्युन को अध्यक्ष चुना. हालांकि इनके शासन को जल्द ही खतम किया गया. 1961 में पार्क चुंगही गुट ने सैनिक विद्रोह करके अधिकार को अपने हाथों में ले लिया. पार्क चुंगही का प्रतिक्रियावादी इतिहास रहा था. जापान साम्राज्यवादियों की सेना में वे सैनिक तानाशह थे. और कोरियाई राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के नेता किम इल सुंग और उनकी गुरिल्ला सेना के खिलाफ उन्होंने क्रूर लड़ाई लड़ी थी. इसलिए अधिकार में आने के बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया को अमेरिकी और जापानी साम्राज्यवादियों के कठपुतली राज्य के रूप में ढाल दिया. अमेरिका के तरफ से उन्होंने वियतनाम के ऊपर सेना भेजी थी. इनके बाद दक्षिण कोरिया में जितने ही शासक आए थे, वे सब इनके ही रास्ते पर चले थे. पार्क चुंगही की बेटी पार्कगियुन–हेय भी दक्षिण कोरिया की अध्यक्षा रह कर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाल ही में पद छोड़ने मजबूर हो गईं. इस तरह दक्षिण कोरिया प्रारंभ से ही अमेरिका की गुलामी कर रहा है. हालांकि दक्षिण कोरिया की जनता तो अपने शासकों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती आ रही है.

हालांकि साम्राज्यवादी हितों ने कोरिया प्रायद्वीप को दो टुकड़े किए लेकिन कोरियाई जनता में तो फिर से एकजुट होने की मजबूत आकांक्षाएं जीवित हैं. उन आकांक्षाओं के विपरीत दोनों देशों के बीच में अगाध की सृष्टि करने वाले अमेरिका के प्रति कोरियाई जनता में व्याप्त नफरत जायज है.

हालांकि 1953 में उत्तर, दक्षिण कोरिया के दरमियान युद्ध रुक गया हो लेकिन युद्ध का खतरा उत्तर कोरिया का पीछा कर रहा है. उत्तर कोरिया में किम शासन को खतम करके अपने कठपुतली शासन को खड़ा करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है. दक्षिण कोरिया को अपना सैनिक अड्डा बनाने वाले अमेरिका ने वहां हजारों की संख्या में अपनी सेना को तैनात किया. जापान को भी उसने अपना सैनिक अड्डा बना दिया. ऐसे में उत्तर कोरिया में असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक है. 1970 से दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका हर साल युद्ध अभ्यास कर रहा है. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजनयिक किम इन रेओंग ने कहा कि उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है, जिस पर 1970 से ही परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है. इससे हम उत्तर कोरिया के डर को समझ सकते हैं.

इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर कोरिया के सामने दो ही रास्ते हैं. आत्मसमर्पण या प्रतिरोध. उत्तर कोरिया यह नहीं चहता है कि अपनी सुरक्षा एवं संप्रभुता को अमेरिका की कृपा पर छोड़ दें. उसने समझ लिया कि प्रतिरोध में ही आत्मरक्षा है. अमेरिका के आधिपत्य को धिक्कारने के लिए अपनी हथियार संपदा को बढ़ाने का निर्णय उसने लिया. इसी क्रम में उसने परमाणु कार्यक्रम की ओर अपना कदम बढ़ाया. हालांकि शुरुआत में ही उस कार्यक्रम को रोकने के लिए अग्र राज्यों ने कोशिशें की. साम्राज्यवादी देशों के पास इतने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार हैं कि वे इस सारे भूमंडल को हजारों बार राख कर सकते हैं. सिर्फ अमेरिका के पास ही दस हजार से जादा परमाणु हथियार हैं. उसके टट्टू देशों को भी वह परमाणु हथियारों की आपूर्ति करता है. इज्राइल के पास दो हजार परमाणु हथियार हैं. अमेरिका,रूस, चीन एवं कई यूरोपीय देशों ने अभी तक करीब दो हजार बार परमाणु परीक्षण किए. परमाणु बम से लगभग हजार गुना अधिक ताकतवर हाइड्रोजन बम भी अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड एवं फ्रांस के पास हैं. मगर ये देश अन्य पिछड़े देशों को परमाणु मुक्त बनाए रखने के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की. दुनिया भर के विरोध को दरकिनार करके जैविक, रासायनिक हथियार होने के झूठे आरोप लगाते हुए इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ कर बड़े पैमाने पर नरसंहार व विध्वंस को अंजाम दिया. इराक के तत्कालीन अध्यक्ष सद्धाम हुस्सैन को फांसी पर लटका दिया. रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए सिरिया पर हमला किया. ज्ञात हो कि 1998 में जब हमारा देश परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए. 2006 में भारत–अमेरिका के बीच में हुए परमाणु समझौते में भारत के परमाणु कार्यक्रम को आईएईए (इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी) के पर्यवेक्षण में लाने की शर्त रखी गयी है. चूंकि आईएईए के ऊपर अमेरिका का दबदबा चल रहा है, इसलिए नतीजा यह निकला कि भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की प्रभुता को स्वीकार किया.

इसी प्रकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए शीर्ष देश कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं. चीन, रूस, अमेरिका आदि छह देशों के विचार–विमर्श के चलते 2005 में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की घोषणा की. नान–प्रोलिफरेशन ट्रीटी–एनपीटी पर उसने हस्ताक्षर भी किया. परमाणु कार्यक्रम को रोकन के बावजूद आतंकवादी देशों की फेहरिस्त से उत्तर कोरिया को नहीं हटाया गया. समझौते की अन्य शर्तें भी इन देशों द्वारा लागू नहीं की गईं. इससे 2008 दिसंबर में उत्तर कोरिया ने यह घोषणा की कि छह देशों की बातचीत विफल हुई. उसके बाद उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को

फिर शुरू किया. साम्राज्यवादी देश खासकर अमेरिका द्वारा कई पाबंदियां लागू करने के बावजूद वह अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है. 2011 में किम जोंग उन के सत्तारूढ़ होने के बाद इस कार्यक्रम पर और जोर दिया गया. परमाणु हथियार संपत्ति में अमेरिका से बराबरी करने की अपनी चाहत को कई बार उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से इजहार किया.

परमाणु हथियार न सिर्फ मानव जाति बल्कि जीव जगत के अस्तित्व के लिए भी खतरा है. दूसरे विश्वयुद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों द्वारा कितना भयानक विनाश पैदा हुआ था, इससे दुनिया वाकिफ है. लगभग दो लाख लोगों ने इन हमलों में जानें गवाईं. उन हमलों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव अभी भी वहां के लोगों का पीछा कर रहा है. परमाणु हथियार के प्रयोग या परीक्षण में सैकड़ों मील दूर तक जलवायु बुरी तरह प्रभावित होता है. पूरा वातावरण परमाणु प्रदूषणयुक्त हो जाता है. नतीजतन बड़े पैमाने पर जानी नुक्सान होता है. जो मरने से बचते हैं वे कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों का शिकार होते हैं. सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि अन्य सभी हथियार वर्गीय लूट को जारी रखने वाले औजार हैं. धरती पर जब तक लूट जारी रहेगी तब तक न सिर्फ लूट करने बल्कि लूट का प्रतिरोध करने हथियारों की आवश्यकता होती है. परिणामक्रम में मानव जाति लूट के साथ–साथ हथियारों का उन्मूलन भी जरूर कर लेती है.

दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का मालिक अमेरिका ही है. उतना ही नहीं अभी तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल (हिरोशिमा और नागासाकी पर) करने वाला एकमात्र देश भी अमेरिका ही है. अमेरिका अपने सामने न झुकने वाले देशों के खिलाफ झूठा, विषैला, मनगढ़ंत प्रचार करता है, उन पर आक्रमण करता है, उन पर युद्ध छेड़ता है, उन देशों में सैनिक विद्रोह करवाता है, उन देशों के शासकों की हत्याएं करता है, करवाता है, वहां सरकार विरोधी आंदोलनों यहां तक कि सशस्त्र आंदोलनों को भी हवा देता है, आतंकी हमलें करवाता है, आतंकी संगठनों को खड़ा करता है, वहां अपनी कठपुतली सरकारों का निर्माण करता है, उन देशों के संसाधनों को हड़पता है, उस लूट के खिलाफ जारी जन आंदोलनों को आतंकवाद करार देकर आतंकवादविरोधी मुहिम के नाम पर उन्हें कुचलता है, दुनिया में शांति व जनवाद कायम करने के नाम पर वह कहीं भी और कभी भी आतंक मचाता है. इस तरह वह दरअसल दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है. ऐसे इतिहास वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एशिया दौरे के समय उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को विश्वसभ्यता और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया. संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तर कोरिया को यह एहसास हो कि निरस्त्रीकरण ही एकमात्र स्वीकार्य भविष्य है. साम्राज्यवादी देश खासकर अमेरिका ढेरों परमाणु हथियार अपने पास रख कर, उन हथियारों के बल बूते दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हुए निरस्त्रीकरण के बारे में अन्यों को 'हितोपदेश' कर रहा है. परमाणु हथियारों के प्रति उत्तर कोरिया का रवैया क्या है? संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण कमेटी के सामने उत्तर कोरिया के राजनयिक किम इन रेओंग द्वारा कही गई बातों से हम इसे समझ सकते हैं. रेओंग ने कहा कि उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा के अधिकार के तहत परमाणु हथियार रखने का हक है. साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का विनाश और विश्व को पूरी तरह से परमाणुमुक्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है.

अपनी सैनिक प्रभुता के सामने उत्तर कोरिया का दब कर न रहना अमेरिका को नहीं पच रहा है. भारत जैसे बड़े देश ने अपने संप्रभुता और आत्मसम्मान को अमेरिका के चरणों पर रख दिया. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर, सिर्फ ढाई करोड़ आबादी वाला और अमेरिका की तुलना में दो फीसदी से कम क्षेत्रफल वाले उत्तर कोरिया द्वारा अपने आत्मसम्मान को प्रदर्शित करना अमेरिका के लिए असहनीय विषय बन गया है. असल में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम से परहेज करने वाले देशों और उत्तर कोरिया की जनता की जनता के पास. न तो अमेरिका और ना ही किसी अन्य साम्राज्यवादी देश को इसकी नैतिक योग्यता है, अधिकार तो बिलकुल ही नहीं.

उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के प्रति अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत ही आक्रामक है. उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के बहाने दक्षिण कोरिया की मिसाइल प्रणाली को विकसित करने के लिए अमेरिका ने सैकड़ों करोड़ डॉलरों के समझौते कर लिए. उत्तर कोरिया की सीमा पर उसने टेर्मिनल हाय आल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स (थाड) मिसाइलों को तैनात किया. ये दुश्मन के मिसाइलों को आकाश में ही रोक कर विस्फोट कर सकते हैं. पहले से वहां काम कर रही दो थाड मिसाइलों के अलावा इनकी तैनाती हुई. संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर और जोर दिया गया. बालिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया.

18 सितंबर को जापान के नजदीक के उत्तर कोरिया के गगनतल में अमेरिका ने आधुनिक व शक्तिशाली फाइटर जेट व बांबरों के साथ अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. दक्षिण कोरिया व जापान की फौजी जहाजों के साथ उसने कवायद की.

24 सितंबर को अमेरिका के गुवाम द्वीप से निकलने वाले बी–1 बी लान्सर बांबर उत्तर कोरिया के पूर्वी तट की ओर कूच किए. जापान के ओकिनोवा से एफ–15 युद्ध जहाजों ने उनके साथ सफर किया. उत्तर कोरिया के तट पर अमेरिका ने अपनी सैनिक संपत्ति को बढ़ा दिया. दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम 'बी 61–12' का परीक्षण अमेरिका ने किया.

अमेरिका की उपरोक्त गतिविधियों द्वारा हम समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया के ऊपर अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए वह अनगिनत कोशिशें कर रहा है. अमेरिका के इस कथन कि 'अपने आपको बचाने के लिए या हमारे मित्र देशों को बचाने के लिए उत्तर कोरिया को पूरी तरह तबाह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है', से अमेरिका के सूपर पुलिस का रवैया हमें समझ में आता है. पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर रखा गया है, अमेरिका ऐसी बात कर रहा है. ट्रंप की इस धमकी की प्रतिक्रिया में किम ने कहा 'ट्रंप की टिप्पणी ने मुझे डराने या रोकने के बजाय इस बात के लिए संतुष्ट किया कि जो रास्ता मैंने चुना है, वही सही है और इस पर मुझे अंत तक चलना है.'

दरअसल अमेरिका 2008 से जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उससे उबरा नहीं. वह दुनया का संकट बन गया है. दुनिया पर अमेरिकी प्रभुता कमजोर हो रही है. चीन और रूस के नेतृत्व वाली ब्रिक्स और शांघाई सहयोग संगठन, एशिया–यूरोप महाद्वीपों को मिलाते हुए चीन द्वारा निर्माणाधीन 'वन बेल्ट–वन रोड'... इत्यादि अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती दे रहे हैं. संकट के चलते अमेरिका में भी कई संघर्ष सामने आ रहे हैं. ट्रंप के नेतृत्व वाली फासीवादी ताकतें अपने देश में तानाशाही अमल करके और अन्य देशों में युद्ध छेड़ कर इस हालत से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं. इस परिप्रेक्ष्य में सत्ता में आते ही ट्रंप ने उत्तर कोरिया के प्रति 'फायर एंड फ्यूरी' (सर्वनाश) की नीति का ऐलान किया था.

ऐसे में तनाव की वर्तमान परिस्थितियों का जिम्मेदार अमेरिका ही है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए. इसलिए दुनिया के हर देश को अमेरिका के युद्धोन्माद की निंदा करनी चाहिए. इधर एक महत्वपूर्ण विषय जो युद्ध और तनावपूर्ण माहौल के दरमियान आशावह भविता का आश्वासन दे रहा है, का उल्लेख करना आवश्यक है. एक ओर अमेरिकी शासक युद्धोन्माद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर इसके खिलाफ अमेरिकी जनता सहित दुनिया भर की उत्पीड़ित जनता आवाज उठा रही है.

चीन और रूस उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा कर रहे हैं, इसके साथ ही अमेरिका के रवैये का भी विरोध कर रहे हैं. संयम बनाए रखने की विज्ञप्ति कर रहे हैं. उत्तर कोरिया के ऊपर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित कठोर पाबंदियों को उन्होंने अपने वीटो अधिकार के साथ कुछ हद तक रोक दिया. उत्तर कोरिया के व्यापार में चीन का 90 फीसदी हिस्सा है. इसलिए ट्रंप का कहना है कि चीन को उत्तर कोरिया पर दबाव डालना चाहिए. लेकिन ट्रंप की इस बात को चीन गलत ठहराता है. चीन ने कह दिया कि चूंकि प्रशांत महासागर में अमेरिका के युद्ध जहाज सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, इसी वजह से उत्तर कोरिया ने बालिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. रूस भी पाबंदियों के पक्ष में नहीं बल्कि कूटनीतिक हल की आवश्वकता की वकालत कर रहा है. जाहिर है कि रूस–चीन और अमेरिका के बीच में जो अंतरविरोध हैं, उनकी वजह से ही रूस और चीन उत्तर कोरिया के प्रति कुछ हद तक अनुकूल रवैया अपना रहे हैं. खासकर एशिया में अमेरिका के दबदबे को रोकने के लिए चीन को उत्तर कोरिया जैसे देश की जरूरत है. उत्तर कोरिया में अकूत संसाधनों का भंडार है. उसके समुंदर के किनारे 12 अरब बैरलों के पेट्रोल का पता चल गया है. इसलिए उत्तर कोरिया पर आधिपत्य चलाने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन व रूस की कोशिशें जारी हैं. इस परिप्रेक्ष्य में ही उत्तर कोरिया के प्रति ये तीनों देशों के रवैया को समझना होगा. वर्तमान में मध्य प्राच्य और कोरियाई प्रायद्वीप इन तीनों देशों के अंतर विरोधों का केंद्र बना हुआ है.

साम्राज्यवाद का मतलब ही युद्ध है. हर साम्राज्यवादी देश पिछड़े हुए देशों के संसाधनों और मार्केट पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता है. अगर कोई देश इसका विरोध करे, तो उस पर कई प्रकार का दबाव डाला जाता है. दुनिया के संसाधनों व बाजारों पर कब्जा जमाने के लिए साम्राज्यवादी देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वह दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं. यह जगजाहिर है कि विगत के दोनों विश्व युद्ध इन्हीं के लिए हुए हैं.

इसलिए अगर युद्धों को खतम करना है, सभी देशों के दरमियान सही मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है, अंतर्राष्ट्रीयता को बनाए रखना है, तो इस धरातल से साम्राज्यवाद का नामोनिशान मिटा देना होगा. इसके लिए दुनिया भर के सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में नव जनवादी या समाजवादी क्रांतियों को सफल करना होगा. उस लक्ष से दुनिया भर के मजदूरों, किसानों के अलावा तमाम क्रांतिकारी व उत्पीड़ित वर्गों की जनता और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को एकजुट होकर अपने–अपने देशों में जनांदोलनों व सशस्त्र संघर्षों को सही तालमेल के साथ आगे ले जाना होगा.

★

जनांदोलन

पुलिस थानों के विरोध में

क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के मकसद से दंडकारण्य में बैठाए जा रहे पुलिस थानों व कैंपों की तादाद दिन–ब–दिन बढ़ रही है. इन कैंपों के लिए जनता की जमीन जबर्दस्ती से छीनी जा रही है. उतना ही नहीं कोई भी गांव या इर्द–गिर्द गांवों में पुलिस कैंप के रहने का मतलब है, वहां की जनता की जिंदगी का तितर–बितर होना, बेचैन होना. इसलिए समूचे दंडकारण्य की ग्रामीण जनता इन कैंपों के विरोध में आवाज उठा रही है. हाल ही में कोंडागांव जिले के कडेनार, हडेली क्षेत्रों की जनता ने भी उसी तरह आवाज उठायी. कडेनार गांव में सरकार द्वारा प्रस्तावित पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के कैंप का पहले से ही जनता विरोध करती आ रही है. इसके विरोध में ग्रामसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया था. इसके बावजूद जब ग्रामवासियों से पूछे बिना पुलिस द्वारा कैंप के लिए जबरदस्ती जमीन पर नाप जोख किया जा रहा था. इसके विरोध में इस क्षेत्र के कई गांवों की जनता एकजुट होकर 17 अक्टूबर को जिला कर्यालय में पहुंच कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि चूंकि उक्त सभी ग्राम नवगठित ब्लॉक मर्दापाल के अंतर्गत आते हैं और भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, इसलिए बिना ग्रामवासियों की अनुमति के कैंप न खोला जाए. फिर भी जनता के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, अपने ही संविधान का मजाक उड़ाते हुए नवंबर महीने में कडेनार में और दिसंबर में हडेली में कैंप बैठाए गए. बावजूद इन कैंपों के विरोध में जनता का संघर्ष जारी है.

डिलमिली थाने के विरोध में कलेक्टोरेट का घेराव

और एक आवाज है, डिलमिली क्षेत्र से – गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को किए गए छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक के डिलमिली क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट(अति वृहद इस्पात संयंत्र) स्थापित करने एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था. कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए उद्देश्यित इस प्लांट के कारण 14 गांव प्रभावित हो जाएंगे. चूंकि इस प्लांट के लिए हजारों एकड़ की जमीन जनता से छीनी जाऐंगी इसलिए जनता इस प्लांट के विरोध में आंदोलनरत है. जनांदोलन को कुचल कर बंदूक की नोक पर जमीन छीनने के मकसद से डिलमिली गांव में पुलिस थाना खोलने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया. इस थाने का भी जनता कड़ा विरोध कर रही है. डिलमिली गांव से तीन किलोमीटर दूर के कोड़ेनार गांव में पुलिस थाना पहले से मौजूद है. दमन को और बढ़ाने के लिए ही और एक थाना खोलने पर सरकार तत्पर है. जब से पुलिस थाना लगाने का निर्णय किया गया तभी से ग्रामीणों द्वारा इसके विरोध में लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस सिलसिले में 26 नवंबर 2017 को अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट से प्रभावित सभी 14 गांवों के ग्रामीणों द्वारा ग्रामसभा का आयोजन हुआ था. इसमें थाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था. इसके तहत अगले दिन यानी 27 नवंबर को सैकड़ों लोगों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया था. पुलिस ने सुरक्षा का बहाना करके जनता को मेनगेट पर ही रोक दिया. कलेक्टर कार्यालय का मुख्यद्वार बंद किया गया. लेकिन जनता ने हार नहीं मानी. 'मावा नाटे मावा अधिकार', 'जल, जंगल व जमीन की रक्षा करो', 'आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करो' आदि नारे लगाते हुए वहीं पर अडिग रही. ऐसे में ज्ञापन लेने डिप्टी कलेक्टर को बाहर भेजा गया. लेकिन ग्रामीण कलेक्टर से मिलकर ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहें. वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि कलेक्टर बाहर नहीं आएंगे. लेकिन आखिरकार कलेक्टर को बाहर आना ही पड़ा. उन्होंने ग्रामीणों से ज्ञापन प्राप्त किया और उनकी बातें सुनी. डिलमिली में थाना खोलने के मुद्दे पर कलेक्टर ने पुनर्विचार करने का आश्वासन तो जरूर दिया. लेकिन डिलमिली में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट को लेकर बात करने को अनुचित बताया. इससे कॉरपोरेट घरानों के प्रति शासन–प्रशासन की गुलामी स्वभाव को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं. अन्य सभी आंदोलनों की तरह इस आंदोलन को भी कुचलने के लिए पहले से ही सरकार कई प्रयास कर रही है. जनसभा के एक दिन पहले ही 25 नवंबर को कोड़ेनार पुलिस थाने से दलबल के साथ डिलमिली पहुंचे सहायक उप निरीक्षक रायकोट और मावलीभाटा ने डिलमिली के सरपंच आयतू राम को धमकी देते हुए डिलमिली कैंप का विरोध नहीं करने की चेतावनी दी. वरना नक्सली प्रकरण बनाकर सरपंच पद से हटाने की बात कह दी गई. एक दैनिक पत्र के मुताबिक सरपंच आयतू राम ने बताया

शिक्षाकर्मी हड़ताल

दमनात्मक हथकंडों को धता बताकर फिर से आंदोलन की तैयारी करनी होगी!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने संविलयन, समान वेतनमान सहित तमाम जायज मांगों के लिए 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का भरपूर समर्थन किया था और सभी मांगों का समाधान होने तक जुझारु ढंग से हड़ताल को जारी रखने का आह्वान किया था.

यह जगजाहिर है कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा की रमण सरकार पिछले 13 सालों से भी ज्यादा समय से शिक्षाकर्मियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है. सन् 2003 और 2008 में चुनावी वादा करते हुए भाजपा ने सत्तारूढ़ होने की सूरत में शिक्षाकर्मियों के संविलयन व समान वेतनमान देने का वादा किया था लेकिन तब से लेकर आज पर्यंत हर साल शिक्षाकर्मियों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आना पड़ रहा है और उन्हें हर बार लाठी, जेल, निलंबन, बर्खास्त एवं आखिर कोरे वादे ही नसीब हो रहे हैं. दमन को धता बताते हुए उग्र आंदोलन करने का लंबा अनुभव हालांकि शिक्षाकर्मियों को प्राप्त है और अपने विगत की अनिश्चितकालीन हड़तालों के अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार भी उन्होंने 15 दिनों तक जुझारु आंदोलन किया था लेकिन आखिरकार सरकार के दमनात्मक हथकंडों की वजह से अपनी लंबित मांगों को हासिल करने में वे विफल रहे. सरकार ने हड़ताल को तोड़ने के लिए साम, दाम, दण्ड व भेद की नीति अपनायी. एक तरफ नेतृत्व को डरा–धमकाने कई दमनात्मक हथकंडे आजमायी और दूसरी ओर नेतृत्व के एक हिस्से को प्रलोभन देकर कमजोर किया.

आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा शिक्षाकर्मियों पर कई बार बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया. महिला शिक्षाकर्मियों तक को जानवरों की तरह पीटा भी गया. उनकी रैलियों, धरना–प्रदर्शनों को विफल करने के लिए रायपुर पहुंचने वाली सड़कों पर गाड़ियों को रोक–रोककर महिला, पुरुष यहां तक कि छोटे–छोटे बच्चों को भी उतारकर हिरासत में लिया गया था. रायपुर के सभी सुलभ शौचालयों में ताले झड़ दिए गए थे. महिला शिक्षाकर्मियों को सड़क पर घसीट–घसीटकर ले जाया गया. धरना–प्रदर्शन के लिए जगह नहीं दी गयी. शिक्षाकर्मी नेताओं को फोन के लोकेशन चिह्नित कर गिरफ्तार किया गया था. 25 उन महिला शिक्षाकर्मी नेताओं को हिरासत में लेकर दबाव डाला गया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर पूछा, 'तुम लोग डिलमिली में पुलिस थाना खोलने का क्यों विरोध कर रहे हो, तुम भी नक्सली हों, तुम्हारे पूरे गांव वाले भी नक्सली हैं. इसलिए विरोध कर रहे हैं. तुमको भी देख लेंगे और तुम्हारे गांव वालों को भी देख लेंगे.' उतना ही नहीं, पंच उपसरपंच समेत थाना कोड़ेनार में अगले दिन शाम को आने का फरमान पुलिस वालों ने सुनाया और ग्राम पंचायत डिलमिली का उप चुनाव करवाने की भी सरपंच को धमकी दी. 27 नवंबर को जब जनता द्वारा कलेक्टोरेट का घेराव किया गया, कोतवाली व बोधघाट थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल को लाकर तैनात किया गया था.

दरअसल पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य करना असंवैधानिक है. संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए शासन–प्रशासन द्वारा आदिवासियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है. इसके विरोध में न सिर्फ आदिवासी जनता बल्कि देश के सभी जनवादी ताकतों को संघर्ष करना चाहिए. ★

जो आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर रही थीं. 3 दिसंबर तक सिर्फ रायपुर जेल में ही 800 शिक्षाकर्मियों को बंद कर दिया गया था. नेतृत्व सहित समरशील शिक्षाकर्मियों का दूरदराज के इलाकों में, अन्य जिलों में तबादला किया गया. तय समय सीमा के पहले ड्यूटी में ज्वाइन न करने वाले शिक्षाकर्मियों को नौकरी से निलंबित किया गया, वेतन कटौती की गयी, आखिर 41 नेताओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया था. हड़ताल के दौरान कुछेक शिक्षकों की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु भी हो गयी. सीनियर–जूनियर के नाम पर अलग–अलग वेतन भत्तों व सुविधाओं के वादे के जरिए उन्हें विभाजित किया गया. मुख्यमंत्री ने यह तानाशाहीपूर्ण बयान जारी किया कि न संविलयन होगा न ही समान वेतनमान दिया जाएगा.

भूमिगत हुए नेताओं को जबरन बुलाकर उन्हें जेल में बंद नेताओं के साथ मिलाकर हड़ताल समाप्त करने मुख्यमंत्री की ओर से एसपी, कलेक्टर द्वारा दबाव डाला गया. सिर्फ आश्वासन मिला कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. इस तरह दमन, दबाव, धौंस के जरिए हड़ताल को तोड़ दिया गया था. रायपुर केंद्रीय कारागार में 4 दिसंबर की आधी रात को शिक्षाकर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर दी.

चूंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए शिक्षाकर्मियों के गुस्से को शांत करने के लिए हड़ताल को खत्म करने के बाद शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए रमण सरकार ने दो कमेटियां बनायी. पहली मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो संविलयन की मांग पर विचार–विमर्श कर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी जबकि दूसरी शिक्षाकर्मियों की अन्य मांगों का अध्ययन करने के लिए पंचायत विभाग के एसीएस और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के साथ. बर्खास्त शिक्षाकर्मियों को बहाल किया गया. हड़ताल के दौरान जिन शिक्षाकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी, उस कार्रवाई को भी निरस्त करने के आदेश दिए गए. इससे जिन्हें हड़ताल के दौरान दूसरे जिलों में तबादला कर दिया गया था, उन्हें वापस उनके जिलों में भेजा जाएगा. शिक्षाकर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने का आदेश भी दिया गया था. सरकार के कोरे आश्वासनों से शिक्षाकर्मियों की समस्याएं हल नहीं होंगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओ के करीबन 90 हजार शिक्षाकर्मियों को अक्टूबर–नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक का भी वेतन नही मिला. उन्हें आगे की हड़ताल के लिए और जोर–शोर से तैयारी करनी होगी. 'सरकार से हम जीत नहीं सकते', शिक्षाकर्मियों को इस सोच से बाहर आना होगा.

शिक्षाकर्मियों की हड़ताल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षाकर्मियों को स्थायी शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, विभिन्न शिक्षा परियोजनाओं में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों, प्रेरकों, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु शिक्षकों, छात्रों, पालकों, तमाम सरकारी कर्मचारियों का समर्थन जुटाना होगा. विशेषकर किसान जनता के साथ एकताबद्ध होकर उनका मजबूत समर्थन हासिल करना होगा. साथ ही तमाम शिक्षाकर्मियों को एकजुट होना होगा. अभी ये 13 अलग–अलग रजिस्टर्ड संगठनों में संगठित हैं. इन संगठनों के नेता अलग–अलग विचारधारा के हैं. हड़ताल की समाप्ति के बाद आरएसएस ने संघीय विचार वाले शिक्षाकर्मियों व नेताओं को आगे कर एक शिक्षाकर्मी सम्मेलन बुलाकर नया संगठन खड़ा करने की नाकाम कोशिश की. ज्यादातर शिक्षाकर्मियों ने इसका विरोध किया जोकि अच्छी बात है. संघ परिवार बार–बार ऐसी कोशिशें करेगा जिनके प्रति शिक्षाकर्मियों को हमेशा सावधान रहना होगा. इन्हें और विभाजित करने की साजिशों को विफल करना होगा.

यहां यह कहना वाजिब होगा कि देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान हो या छत्तीसगढ़ में उनके चेले रमण सिंह के 'बच्चों, पढ़ो–बढ़ो' अभियान हो मात्र कोरी लफ्फाजी के सिवाय और कुछ नहीं है. विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपमानजनक शर्तों का पालन करते हुए स्थापना व्यय को कम करने के नाम पर केंद्र, राज्य सरकारें तमाम सरकारी विभागों में स्थायी नौकरियों पर पाबंदी लगा रखी हैं और अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कम से कम मानदेय पर नियुक्त कर रही हैं. दूसरी ओर कर्मचारियों के वेतन–भत्तों में भारी कटौती कर रही हैं. साथ ही शिक्षा के निजीकरण (कॉरपोरेटीकरण) व भगवाकरण को बढ़ावा देते हुए युक्तियुक्तकरण के नाम पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी व पिछड़े इलाकों के तीन हजार शालाओं व आश्रमों को बंद कर दिया गया है. इससे अधिकांश आदिवासी, दलित व पिछड़े वर्गों के बालक–बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित कर दिए गए हैं जोकि ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी साजिश है. इससे शिक्षकों के हजारों पदों को हमेशा के लिए बंद करना आसान हो गया है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में इस तरह करीबन एक लाख शालाओं व आश्रमों–छात्रावासों को बंद कर दिया गया है. इसी तरह मदरसों को अनुदान बंद करके गरीब मुसलमान बच्चों को भी बड़े पैमाने पर शिक्षा से वंचित कर दिया गया है.

शिक्षाकर्मियों सहित तमाम लोगों को रमण सरकार की जनविरोधी व कॉरपोरेटपरस्त शिक्षा नीति सहित तमाम नीतियों के खिलाफ व्यापक संयुक्त मोर्चे के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. ★

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–02 दिसंबर, 2017

रबी फसल उगाने पर प्रतिबंध लगाने वाली छग सरकार की किसान विरोधी व पूंजीपतिपरस्त नीति के खिलाफ उग्र आन्दोलन का रास्ता अपनाने का आह्वान!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ के किसानों का आह्वान करती है कि वे छग सरकार द्वारा धान की रबी खेती पर पाबंदी लगाने की हालिया किसान विरोधी व पूंजीपतिपरस्त नीति के खिलाफ उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएं.

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा की रमण सरकार पिछले 13 सालों से भी ज्यादा समय से राज्य में लगातार जन विरोधी नीतियों पर अमल करती आ रही है जिससे उत्पीड़ित वर्गों की जनता की जीवन दूभर होती जा रही है.

दिसंबर, 2013 में तीसरी बार सत्तारूढ़ होने के पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में एवं प्रचार सभाओं के दौरान रमण सिंह एवं उनके अनुयायियों ने यह वादा किया कि सत्ता में आते ही धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल एवं 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा. लेकिन चार साल पूरे हो गए धान का समर्थन मूल्य अब भी 1700 पार नहीं हुआ. इतना ही नहीं किसानों की फसल का दाना–दाना खरीदने की बात करने वाले रमण सिंह पिछले साल प्रति एकड़ 10 क्विंटल ही खरीदने की घोषणा कर चुके थे जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर आए थे. आखिर प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदने राजी हो गए. कर्ज माफी के लिए किसान आंदोलित हुए तो सही समय पर कर्ज पटाने वाले किसानों के ब्याज माफ करने की घोषणा करके रमण सरकार ने किसानों के आंदोलन का मजाक उड़ाया था. राज्य में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला पिछले 13 सालों से बेरोकटोक जारी है. अब भूजल स्तर के घट जाने का बहाना करते हुए छग सरकार पूंजीपतियों के कारखानों की धमनभट्टियों का प्यास बुझाने सरकारी जलाशयों का पानी उपयोग करने पर तुली हुई है. इतना ही नहीं अपने तलाबों, डबरों, कुओं का पानी मोटर पंपों के माध्यम से सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने पर बिजली काटने की धमकी तक दे डाली जोकि हिट्लरशाही के सिवाय और कुछ नहीं है. यह धान के कटोरे को भीख का कटोरा बनाकर साम्राज्यवादी देशों के सामने अनाज के लिए हाथ फैलाने पर राज्य की जनता खासकर किसानों को मजबूर करने की साजिशपूर्ण कुचेष्टा है. यह कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देते हुए देशी, विदेशी, कॉरपोरट घरानों की सेवा व गुलामी करने के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के 43 लाख किसान परिवारों का आह्वान करती है कि वे रमण सरकार के इस किसान विरोधी साजिश के खिलाफ उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएं. इस संदर्भ में हमारी पार्टी एक बार और ऐलान करती है कि हमारे देश में कृषि संकट का असली समाधान सशस्त्र कृषि क्रांति ही है. अतः छग सहित देश भर के किसानों को आत्महत्या नहीं हथियारबंद लड़ाई के रास्ते में आगे बढ़ने की अपील करती है.

न सिर्फ कृषि नीति बल्कि औद्योगिक नीति हो या खनन नीति, मजदूर नीति हो या आदिवासी नीति, दलित नीति हो या धार्मिक अल्पसंख्यक नीति, शिक्षक हो कर्मचारी नीति सभी जन विरोधी और सामंती, हिन्दुत्व फासीवादी, जातिवादी, देशी–विदेशी कॉरपोरेटपरस्त नीतियां ही हैं. इसलिए हमारी पार्टी अपील करती है कि राज्य व देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, ईसाई, किसान, मजदूर, शिक्षक व कर्मचारी सभी उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता को एकजुट होकर व्यापक संयुक्त मोर्चा गठित करके मजबूत, संगठित व जुझारु जन आंदोलन का निर्माण करने की ओर कदम बढ़ाएं. हमारी स्पेशल जोनल कमेटी तमाम आदिवासी व गैर आदिवासी सामाजिक संगठनों, जनवादी–प्रगतिशील जन संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, वामपंथी संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यक संगठनों से अपील करती है कि वे एक साथ ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें.

विकल्प
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

महान रूसी समाजवादी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ

7 नवंबर को रूसी समाजवादी क्रांति की सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर बस्तर डिविजन के गांव–गांव में जन सभाएं आयोजित कर बोल्शिविक स्फूर्ति से जनयुद्ध को आगे बढ़ाने हेतु जनता तक क्रांतिकारी संदेश पहुंचाया गया. इस अवसर पर डिविजन के किसकोड़ो, कुब्बे, रावघाट और प्रतापुर एरियाओं में पोस्टर, बैनर के साथ प्रसार व प्रचार किया गया.

प्रेस वक्तव्य

दिनांकः 2 दिसंबर, 2017

पत्रकारों को दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी, भाकपा (माओवादी) की ओर से स्पष्टीकरण

पत्रकार संगठन की ओर से हमारी पार्टी को भेजा गया संदेश हमें मिला. 13 नवंबर को आवापल्ली क्षेत्र में तथाकथित माओवादी संगठन के नाम पर जारी पर्चा और बैनर जिसमें पत्रकारों को धमकी दी गयी है और उनका गला घोटने की बात कही गयी है, उससे दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी सहित भाकपा (माओवादी) की किसी भी इकाई का कोई संबंध नहीं है. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने ये पर्चा या बैनर जारी नहीं किया है और हमारी पार्टी पत्रकारों को डराने–धमकाने की राजनीति नहीं करती है.

केन्द्र और राज्य की हिन्दू फासीवादी भाजपा सरकारें, उनके पुलिस बलों और अग्नि जैसे प्रतिक्रांतिकारी गिरोहों ने मिलीभगत से हमारी पार्टी को बदनाम करने व पत्रकारों की जनपक्षधर आवाज को दबाने की एक सोची–समझी साजिश के तहत हमारे नाम से ये पर्चे और बैनर जारी किये हैं. यह करतूत हमारी पार्टी के नेतृत्व में चल रहे क्रांतिकारी आन्दोलन और जनता के जनवादी आन्दोलनों को कुचलने की फासीवादी मुहिम का ही हिस्सा है और साथ–साथ मीडिया की अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी एक कायराना हमला है. हमारी पार्टी उनकी इस करतूत की कड़े शब्दों में निन्दा और विरोध करती है.

हमारी पार्टी हमेशा प्रेस की आजादी और पत्रकारों की अभिव्यक्ति के अधिकार का समर्थक रही है. हाल ही में कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हिन्दू फासीवादियों द्वारा की गई हत्या और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी का हमारी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है. उसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकियों व झूठे मामलें दर्ज कर जेल में डालने का भी विरोध किया है.

हिन्दुत्ववादी भाजपा सरकार–संघ परिवार देशभर में सच्चाई, न्याय, जनवादी अधिकारों और उत्पीड़ित जनता के पक्ष लेनेवाले जनवादियों, मानवाधिकार कर्मियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों पर फासीवादी दमन व हिंसा चला रही हैं। तानाशाही तरीके अपना रही हैं. हमारी पार्टी के नाम से जारी किये गये फर्जी पर्चा–बैनर भी इसी का हिस्सा है. सभी पत्रकारों से हमारा विनम्र अनुरोध और अपील है कि इन झूठे प्रचारों से प्रभावित व गुमराह न होकर पहले तह तक जाकर सच्चाई की जांच–पड़ताल करें, कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत हों तो हम से सम्पर्क करें और सभी पक्षों से जानकारी लेकर ही इस पर विश्वास करें या समाचार छापें. सरकार की जनविरोधी, पत्रकार–विरोधी साजिशों व झूठे प्रचारों से बचें, उनका भण्डाफोड़ करें.

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी

भाकपा (माओवादी)

क्रांतिकारी दिवस

पार्टी स्थापना दिवस

माड़ डिविजन

21 से 27 सितंबर तक पार्टी की 13 वीं वर्षगांठ माड़ डिविजन के कुतुल एरिया में जोर–शोर से मनाया गया. इस मौके पर सभी पार्टी निर्माणों द्वारा पोस्टर, बैनरों के साथ एक महीने पहले से विस्तृत रूप में प्रचार किया गया. पंचायत स्तर की कई सभाओं का संचालन हुआ. तीन जगहों पर बड़ी सभाएं आयोजित की गई. इस अवसर पर तीनों जगहों में जुलूस निकाले गए. झंडे फहराये गए. स्मारकों का निर्माण करके अनावरण किया गया. पार्टी संस्थापक नेता द्वय कामरेड्स चारु मजुमदार और कन्हाई चटर्जी सहित तमाम अमर शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित की गई. इस मौके पर वक्ताओं ने इस साल भर में पार्टी द्वारा हासिल सफलताओं, पार्टी के सामने मौजूद समस्याओं और इन समस्याओं से बाहर निकल कर क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के बोल्शेवीकरण की आवश्वकता के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया. जल, जंगल, जमीन, अस्तित्व और अस्मिता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में बड़े पैमाने पर एकजुट होकर शामिल होने जनता का आह्वान किया गया. सीएनएम कलाकारों द्वारा पस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जनता में और जोश बढ़ा दिया.

इन सभाओं में करीबन 1900 लोगों, जिनमें महिलाओं की तादाद 700 थी, ने शिरकत की.

उत्तर बस्तर

इस मौके पर उत्तर बस्तर डिविजन के प्रतापुर एरिया में विस्तृत रूप से प्रचार किया गया. 25 ग्राम स्तर की और 5 पंचायत स्तर की सभाओं का आयोजन हुआ. इन सभी सभाओं में लगभग दो हजार की तादाद में जनता शामिल हुई.

रावघाट एरिया में गंभीर दमन के बीच में ही गांव–गांव में सभाएं संचालित की गईं. सड़क के आस–पास व नजदीकी साप्ताहिक बाजारों में बैनर बांधे गए. दीवाल लेखन भी किया गया. दो–तीन गांवों को मिलाकर सभाएं आयोजित की गईं. कुव्वे और किसकोडो एरियों में भी बैनर पोस्टर और जन सभाएं कर पार्टी स्थापना दिवस के संदेश को जनता तक पहुंचाया गया. ★

दमन और जन प्रतिरोध

मिशन–2016 के नाम पर विगत वर्ष सरकार द्वारा संचालित दमन अभियान के विफल होने के बाद इस वर्ष मिशन–2017 के नाम पर और एक अभियान को सरकार सामने लायी. लेकिन कोत्ताचेरुवु, बुर्कापाल जैसे हमलों द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन ने मिशन–2017 को कड़ी टक्कर दी, तो लुटेरे शासक वर्गों में खलबली मच गयी. बहुत ही उठा–पटक व समालोचना के बाद प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना 'समाधान' बनायी गयी. इसके तहत क्रांतिकारी आंदोलन व जनता पर दमन और बढ़ गया. लेकिन बढ़ता दमन और भी कई जन संघर्षों को पैदा कर रहा है. कल तक आंदोलन से जो थोड़े से ही सही अछूत रहे थे, उन्हें भी आज दमन आंदोलन में खींच कर ला रहा है. अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो प्रतिरोध में शामिल न होता हों, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है. चूंकि जनता को यह अच्छी तरह समझ में आया कि संघर्ष, सिर्फ संघर्ष ही अपने जल, जंगल, जमीन, अस्तित्व व आत्मसम्मान को बचा सकता है, इसलिए संघर्ष को बनाए रखने के लिए वह दमन के खिलाफ जुझारू आंदोलन कर रही है. इसलिए परिस्थिति ऐसी बन गई कि अगर हमें दमन के बारे में बताना है, तो प्रतिरोध के बारे में भी बताना अपरिहार्य है. इस तरह दमन व प्रतिरोध जुड़ गए हैं. इस प्रतिरोध में महिलाएं अग्रिम पंक्ति में हैं. हालांकि दंडकारण्य भर में अनेक दमन–जन प्रतिरोध की घटनाएं घट रही हैं. लेकिन हम उन कुछ ही घटनाओं, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त है, को इधर छाप रहे हैं.

24 जून 2017 को पश्चिम बस्तर डिविजन के पिडिया गांव पर हमला करने वाले सरकारी सशस्त्र बलों ने हपका गुज्जाल नामक मिलिशिया सदस्य की गोली मार कर हत्या की. बाद में जब हत्यारे पुलिस बल दक्षिण बस्तर डिविजन के मिरगनगोटोड़ गांव से होते हुए वापस जा रहे थे, उसी गांव के लगभग 70 वर्ष के बुजुर्ग ओयम भीमाल रास्ते में उनके हाथ लग गए थे. पुलिस ने उन्हें सार्केनगुड़ा के पास ले जाकर बेरहमी से गोली मार कर उनकी हत्या की थी. इस तरह पुलिस बलों ने एक दिन में दोनों की हत्या की थी. बाद में पुलिस ने बेशर्मी से दो अलग–अलग जगहों में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ों में दो माओवादियों को मार गिराने का दावा किया.

ओयम भीमाल की लाश लाने के लिए बड़ी तादाद में गई महिलाओं को पुलिस ने सामान बांटने की कोशिश की जिसका महिलाओं ने कड़ा विरोध किया.

माड़ डिविजन के कुतुल एरिया, नैबेरेड एलओएस के दायरे के जड्डा गांव में 23 जुलाई, 2017 को स्थानीय गुरिल्ला दस्ते पर पुलिस द्वारा फाइरिंग की गई. हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ. बाद में पुलिस बलों ने 3 ग्रामीणों को पकड़ कर उनके साथ बेदम मारपीट की. उसके बाद उन्हें नारायणपुर ले गए. बहुत ही छोटा गांव होने के बावजूद उस गांव की 15–20 महिलाएं उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस बलों के साथ झगड़ा करते हुए उनके पीछ–पीछे नारायणपुर पुलिस हेडक्वार्टर तक गयी थीं. वहां पुलिस से लड़–भिड़ कर पुलिस की गिरफ्त से अपने सभी ग्रामीणों को छुड़ा लायीं.

उसी दिन जब वेचा गांव से होते हुए उस गांव के तीन जन के साथ पुलिस बल मारपीट करने लगे, तो महिलाओं ने हिम्मत करके पुलिस के हाथों से खींच कर उन्हें बचा लिया.

13 अगस्त को दक्षिण बस्तर डिविजन इत्तमपाड पर पुलिस द्वारा किए गए हमले में डीएकेएमएस सदस्य पोडियम सन्नू और मिलिशिया सदस्य वंजाम उंगाल पुलिस के हाथ लग गए थे. गाजुलागट्टा के पास गोली मार कर दोनों की जघन्य हत्या की थी.

नारायणपुर जिला, ओरछा ब्लॉक, कोंगे ग्राम पंचायत, आचेकोट गांव के निवासी बेकसूर आदिवासी युवक मन्नी नुरेटी (24) पिता किहकाड़ को 24 अगस्त को बेटिया बाजार से पकड़ कर लापता किया गया. इसके विरोध में 10 गांवों की जनता ने छोटे बेटिया थाना जाकर मन्नी नुरेटी को रिहा करने की गुहार लगायी और कांकेर जिलाधीश के कार्यालय में शिकायत की. इसके बावजूद मन्नी का पता नहीं चला. कुछ दिन के बाद 15 सितंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में फर्जी मुठभेड में मारकर मुठभेड़ में माओवादी को मारने का दावा किया गया. इस घटना से आक्रोशित ग्रामवासी जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं.

2 सितंबर को माड़ डिविजन, कुतुल एरिया, कोहकामेट्टा एलओएस दायरे के कच्चापाल गांव के पास स्थानीय दस्ते पर पुलिस ने हमला किया. हालांकि इस हमले से सभी कामरेड्स सुरक्षित निकल पाये. बाद में पुलिस बलों ने गांव पर हमला करके ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट की. कई महिलाएं भी इस मारपीट का शिकार हुईं. बाद में पुलिस बल कई युवतियों और पुरुषों को पकड़ कर अपने साथ नारायणपुर ले गए. पुलिस की मारपीट के बावजूद लगभग 40–50 महिलाएं नारायणपुर जाकर पुलिस के साथ लड़कर सभी को छुड़ा लायीं.

माड़ डिविजन, इंद्रावती एरिया के ताड़िबल्ला गांव के 23 वर्षीय एक भोले–भाले युवक परसा कोसल की सितंबर के दूसरे हफ्ते में पुलिस ने गोली मार कर हत्या की.

परसा कोसल जब इंद्रावती नदी पार करके अपने रिश्तेदारों के गांव आदवाडा जा रहे थे, नदी किनारे में

उन्होंने पुलिस बल को देखा. चूंकि सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा आम जनता को भी प्रताड़ित किया जाना एक साधारण बात बन गई है, इसलिए पुलिस को देख कर कोसल ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया. वापस जाने के मकसद से जब फिर नदी पार करने के लिए वह तैरने लगे थे, पुलिस बलों ने गोली दाग कर उन्हें मार दिया. बाद में वे उनके शव भैरमगढ़ ले गए. एक साधारण युवक जिनका किसी संगठन से कोई वास्ता भी नहीं था, की हत्या करके हमेशा की तरह पुलिस ने बेशर्मी से यह दावा किया कि मुठभेड़ में एक माओवादी को मार दिया गया. पुलिस की इस क्रूर हरकत का पता चलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने भैरमगढ़ जाकर पुलिस से खूब झगड़ा किया और पुलिस से संघर्ष करके लाश ले आये. बाद में मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया. हालांकि इस जनांदोलन के चलते पत्रकारों को पता चला कि पुलिस ने एक साधारण युवक की हत्या की. कुछ लोगों ने भैरमगढ़ जाकर घटना का तथ्यान्वेषण करने की कोशिश की. उन्होंने ताडीबल्ला गांव में खबर भेजी, तो दफनाई गई लाश को कब्र से निकाल कर जनता फिर भैरमगढ़ ले गयी. पत्रकारों के सामने लाश रख कर जनता ने अपना क्रोध व दुख व्यक्त किया. इससे पुलिस की घृणित करतूत का पर्दाफश हो गया.

18 सितंबर को किष्टारम एरिया रासंतोग गांव के पास ठहरे गुरिल्ला दस्ते पर पुलिस बलों द्वारा किए गए हमले में सोढ़ी दीपक नामक गोल्लापाड एलओएस सदस्य शहीद हो गए. हमले के दौरान कामरेड दीपक अस्वस्थ्य थे. टेंट में सो रहे दीपक पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां दाग कर उनकी हत्या की. इस हमले के कुछ ही देर पहले गोल्लापाड एलओएस के ही और एक सदस्य मुचाकी पोज्जाल को गांव में ही पुलिस ने पकड़ा था. पुलिस ने उन्हें अपने साथ में ले जाकर इसी जगह में गोली मार कर उनकी हत्या की. बाद में मुठभेड़ में दो माओवादियों को मारने का दावा किया.

दीपक के शव के लिए महिलाएं पहले किष्टारम गईं, वहां से सुकमा गईं. दोनों जगहों में लड़ने के बाद मिली लाश को महिलाएं ढोकर अपना गांव लाईं.

20 सितंबर की रात को पालेमडगु गांव पर पुलिस ने हमला किया. इस दौरान घर में सो रहे कमेटी सदस्य पोडियम भीमाल पुलिस के हाथ लग गए थे. पुलिस ने बेरहमी से यातनाएं देकर उनकी हत्या की. इस हत्या के खिलाफ भीमाल की दीदी कन्नी अदालत में लड़ रही हैं.

28 सितंबर 2017 को दक्षिण बस्तर डिविजन, केरलापाल एरिया के गांदार गांव पर हमला करने वाली पुलिस ने 6 लोगों, जिनमें एक महिला थीं, को अपनी गिरफ्त में लिया. जब उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे, गांव के लोगों, जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, ने उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयास किया. पुलिस ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की. इस मारपीट में 9 महिलाएं और 4 पुरुष घायल हो गए. इसके बावजूद लगभग 50 महिलाएं पुलिस का पीछा करते हुए रास्ते से ही पकड़े गए लोगों को छुड़ा लाईं.

3 अक्तूबर को नारायणपुर से निकले पुलिस बलों ने माड़ डिविजन के परालकोट एलओएस दायरे के कद्देर, बेरहवेडा, ओरादी, मसपुर, मेट्टानार, गारपा और ओडछापारा गांवों पर हमला करके आतंक मचाया. जनता के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि विभिन्न गांवों के 21 ग्रामीणों को पकड़ कर नारायणपुर ले गये. इन सभी गांवों के लगभग 120 लोग, जिनमें महिलाओं की तादाद आधी से ज्यादा थी, नारायणपुर जाकर पुलिस से भिड़ गये. जिसके फलस्वरूप 12 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया. जबकि 7 जन को जेल भेज दिया.

उसी समय पुलिस बल सितरम गांव पर हमला करके कुछ ग्रामीणों को पकड़ कर बांदे थाने ले गये. गांव की लगभग 25 महिलाएं जाकर आंदोलन करके उन्हें छुड़ा लायीं.

पूर्व बस्तर डिविजन, कोंडागांव जिले के एहरा गांव में 5 अक्टूबर की रात 9 बजे को 8 मोटार साइकलों में सवार होकर डीआरजी गुंडे आए थे. जब ये लोग गांव में पहुंचे थे, गांव के गरीब आदिवासी किसान आडीराम वट्टी उस समय अपने घर में परिवार के साथ खाना खा रहे थे. अचानक घर में घुसने वाले डीआरजी गुंडों ने आडीराम को जबरदस्ती उठा कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की. मगर न केवल उनके परिजन बल्कि गांव के अन्य लोग तुरंत इकट्टे होकर पुलिस बलों से भिड़ गए. आडीराम वट्टी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में जनता और पुलिस के बीच में खूब झूमाझटकी हुई. जनता ने पुलिस गुंडों को खूब खरी–खोटी सुनाई. जब गुंडों ने आडीराम वट्टी को जबरदस्ती उठा कर मोटार साइकल पर बिठाने की कोशिश की, एक ग्रामीण ने मोटार साइकल सवार पुलिस वाले के पैरों को जकड़कर उसे गिरा दिया. पुलिस वाले का हथियार भी छीन लिया गया. एक घंटे तक जनता ने इस तरह लड़ कर आडीराम को बचा लिया. जनता के आक्रोश व प्रतिरोध के सामने घुटने टेककर डीआरजी वाले अपनी चमड़ी व जान बचाकर भाग निकले.

पश्चिम बस्तर डिविजन में पुलिस व सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा अक्टूबर के दूसरे व तीसरे हफ्तों में दो अभियान चलाए गए. इस दौरान हमेशा की तरह बड़े पैमाने पर आतंक मचाया गया. 10 और 13 के बीच में नेंड्रा, कोरचेली, अवनार, पेदाकोरमा, पदेड़ा, पालनार गांवों के खेत–खलिहानों में काम कर रहे किसानों को घेर कर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की. घरों में घुस कर जनता की संपत्ति को लूटा. दो दिन के बाद और एक बार आतंक माचाया गया. 15–18 के बीच में बीजापुर और दंतेवाड़ा के संयुक्त पुलिस बल

द्वारा गंपुर, पिड़िया, तामोड़ी, हंड्री, इतवार, नेंड्रा और कोरचेली गांवों पर हमलें किए गए. इस दौरान बूढ़े–बच्चे, महिला सहित जो भी दिखे, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गयी. जनता की सिलाई मिशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया.

नवंबर 1 से 5 तक संचालित किए गए अभियान में उत्तर बस्तर डिविजन, ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत बीनागुंडा गांव के हापा टोला के पास तीन ग्रामीणों को पकड़ कर झूठे केसों में फंसाकर जेल भेज दिया गया. इन तीनों में से दो जन हापा टोला के आम नागरिक हैं और वे दोनों ही बचपन से बीमार हैं. तीसरे व्यक्ति गोपी जो छिनपुर के निवासी हैं. अपनी तीन साल की बीमार बेटी के इलाज कराने के लिए हापा टोला के पुजारी को बुला ले जाने आये थे. उन्हें भी पकड़ कर जेल भेज दिये. बाद में तबियत बिगड़ने से 5 दिन के बाद उनकी बेटी चल बसी. आखिर गोपी को अपनी बेटी का मुंह तक देखना भी नसीब नहीं हुआ. उसी दिन पुलिस ने कोड़ेनार गांव से दो बुजुर्गों को पकड़ कर कैंप तक ले जाकर बाद में छोड़ दिया.

नारायणपुर से निकले सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी बलों ने 2 और 3 नवंबर को माड़ डिविजन के नेलनार एरिया के नेलनार, बटवेड़ा, आसनार गांवों पर हमला किया. इस दौरान 4 ग्रामीणों को पकड़ कर धनोरा ले गए थे. 30 महिलाएं और 15 पुरुष धनोरा जाकर 3–4 दिन लगातार पुलिस के साथ संघर्ष करके पकड़े गए सभी लोगों को छुड़ा लाए.

3 नवंबर को सैकड़ों पुलिस बलों ने पूर्व बस्तर डिविजन के आदेरबेड़ा और इरपानार गांवों का घेराव किया. उस समय अपने खेत में धान कटाई कर रहे भारत कश्यप पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसायी. हालांकि किसी तरह उन गोलियों से अपने आप को बचा कर वहां से भागने में वे सफल हो गए.

बस्तर संभाग में 6–13 नवंबर के बीच में ऑपरेशन प्रहार–2 नामक एक बड़ा आतंकी अभियान चलाया गया. इस दौरान 7 नवंबर को माड़ डिविजन कुतुल एरिया के इरपानार गांव के पास ठहरे गुरिल्ला कामरेडों पर हमला किया गया जिसमें पांच कामरेड शहीद हो गए. शहीदों में कामरेड्स रैनी, ज्योती, सुंदरी, संतीला और वाला गांव के जन संगठन के नेता कामरेड फगनू शामिल थे. निहत्थे होने के बावजूद उनकी गोली मार कर हत्या की गई.

इसके बाद लाश के साथ–साथ 49 साधारण ग्रमीणों को पकड़ कर नारायणपुर ले जाया गया. लगभग 50 लोग जिनमें 30 महिलाएं थीं, नारायणपुर जाकर दो दिन लड़ कर पकड़े गए लोगों को छुड़ा लायी. फगनू सहित और कुछ कामरेड़ों की लाशें भी संघर्ष करके लाई गईं.

इसी दिन दुरवेडा गांव के गोटुल में मौजूद कुछ गुरिल्ला कामरेडों को घेर कर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की. इसमें अनिता नामक गुरिल्ला की मौत हुई. बाद में पुलिस बलों ने पूरे गांव की जनता को जमा करके उनके साथ बुरी तरह मारपीट की. उनमें से कुछ महिलाओं और बुजुर्गों को छोड़ कर सभी लोगों को नारायणपुर ले गये. ले जाते समय उन्हें पुलिस के हाथों से छुड़ाने के लिए महिलाएं जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं, कोशिश करते हुए पुलिस के पीछे–पीछे नारायणपुर गयीं. गुम्मरका गांव की महिलाएं भी उनके साथ गयीं. कुल 40–50 महिलाएं बहुत ही संघर्ष करके पुलिस के हाथों से अपनों को छुड़ा लायीं. जबकि 3 लोगों को जेल भेज दिया गया. शहीद अनिता की लाश भी उनके परिजन व ग्रामीण संघर्ष करके लाए.

7 नवंबर को पामेड एरिया के गोम्मगूडेम और मीनागट्टा गांवों पर पुलिस ने हमला किया था. पुलिस ने जब घरों को जलाना, सामान को चोरी करना शुरू किया, तो महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया. पुलिस ने बंदूकों और लाठियों से महिलाओं को बेरहमी से पीटा. कुछ ग्रामीणों को पुलिस जगरगुंडा ले गई. उन्हें छुड़ाने के लिए गईं महिलाओं को अलग–अलग करके पार्टी व संगठनों के बारे में पूछा गया. उन पर मानोवैज्ञानिक रूप से दबाव डाला गया. इसके बावजूद महिलाएं दो दिन तक लड़ती रहीं. लेकिन पुलिस ने अपने चंगुल में रहने वालों को नहीं छोड़ा.

11–13 नवंबर को 400 पुलिस जवानों द्वारा पश्चिम बस्तर डिविजन के पुसनार, मनकेली, पेदाकोरमा, काकेकोरमा और पदेड़ा गांवों पर हमलें किए गए. पेदाकोरमा के पास 12 नवंबर को की गई एक अंधाधुंध गोलीबारी में मिलिशिया कामरेड्स मोड़ियाम मनकु (23), कोरसा सोनू (32) एवं ताती गुड्डू (25) की मौत हुई. इस निर्मम हत्याकांड को पुलिस ने हमेशा की तरह मुठभेड का नाम दिया.

12–16 नवंबर के बीच और एक बार उत्तर बस्तर डिविजन, ओरछा ब्लॉक में अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस बलों ने कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कांदाड़ी ग्राम पंचायत, कलपर गांव के दो ग्रामीणों को पकड़ कर उनके साथ मार–पीट करते हुए छोटे बेठिया थाना तक ले जाकर एक जन को छोड़ दिया. जबकि और एक साधारण आदिवासी सागर पद्दा को ईदूर गांव का क्रांतिकारी जनताना सरकार अध्यक्ष बताते हुए, फर्जी केस दर्ज कर जेल में ठूंस दिया. उसी दिन इदूर गांव का एक आदिवासी किसान और झारावर गांव में खेत में धान कटाई करने वालों को पकड़कर नक्सली होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ बेरहमी से मार–पीट की. जब उन्हें बचाने उनके मां–बाप और ग्रामीण आगे आए, तब उनके साथ भी इतनी मार–पीट की गई कि उनकी नाक और कान से खून बहने लगा.

14 नवंबर को बीराबट्टी गांव के मिलिशिया सदस्य दूला जब अपने खेत में काम निपटा कर घर जा रहे थे,

तभी उन्होंने पुलिस बलों को देखा. अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे दूला के ऊपर पुलिस ने गोलियां दागी. बाद में घायल अवस्था में पुलिस ने उन्हें पकड़ कर कई यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की.

बटालियन–1 के सदस्य कामरेड सोड़ी सीता और कामरेड सोड़ी लखमा को कन्नाईपाड़ गांव से पुलिस ने पकड़ लिया. दोनों के हाथ बांध कर निर्मम यातनाएं देने के बाद अगले दिन, 17 नवंबर, 2017 की सुबह को सुन्नमगुड़ा गांव की मोल्लोलबंडा टोला के पास गोली मार कर उनकी हत्या की. बाद में हमेशा की तरह पुलिस द्वारा यह दावा किया गया कि दोरनापाल क्षेत्र में नक्सलियों के साथ एक घंटे तक हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार दिया गया.

19 नवंबर को माड़ डिविजन के इंद्रावती क्षेत्र में पुलिस व अर्ध सैनिक बलों द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया. इस दौरान कई गांवों में पुलिस ने आतंक मचाया. जनता के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी. बड़े पैमाने पर जनता के मुर्गों व सुव्वरों को मारकर खाया गया. अलग–अलग गांवों से कुल 11 ग्रामीणों जिनमें एक महिला और एक नाबालिग लड़की भी शामिल थी, को पुलिस बल पकड़ कर अपने साथ ओरछा ले गए. जनता के कई भरमारों को भी पुलिस ले गई. पुलिस की गिरफ्त से अपनों को छुड़ाकर लाने के लिए लगभग दस गांवों से बड़ी तादाद में महिलाएं एकजुट होकर ओरछा गयी थीं. महिलाओं द्वारा उन्हें छुड़ाने की मांग को पुलिस ने इनकार कर दिया तो, महिलाओं ने पुलिस कैंप के सामने ही 5 दिन तक दिन रात लगातार धरना देती रहीं, लड़ती रहीं. भीषण ठंड की परवाह किए बगैर महिलाओं ने वहीं पर चूल्हे जलाए, खाना पकाए. इस तरह संघर्ष को जारी रखा. उन्होंने कैंप में घुस कर पुलिस की गिरफ्त से अपनों को खींच कर लाने के भी प्रयास किए. इस तरह चार लोगों को खींच कर लाने में वे सफल हो गयीं. बचे सात में से छह लोगों को जेल भेज दिया गया. इनमें मुन्नाई नाम की एक महिला भी शामिल थीं. पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी नहीं छोड़ा. उस पर कपट प्यार दिखाते हुए उसे स्कूल में दाखिल कराया.

इसी अभियान के दौरान महिलाओं के प्रतिरोध की और दो घटनाएं भी सामने आईं.

काकावेडा गांव के नजदीक के मोडमवेडा गांव के बुधराम नाम का एक शादीशुदा युवक 2016 में पुलिस में भर्ती हो गया. चूंकि इस नौकरी के प्रति उसके परिजन सहमत नहीं थे, इसलिए वे गांव में ही रह गए. जब से बुधराम पुलिस में भर्ती हो गया, तब से परिवार से उसका संपर्क नहीं हुआ था. इस अभियान में शामिल पुलिस बलों में बुधराम भी था. जब वह अपने गांव में कदम रखा, तो उसे महिलाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. महिलाओं ने उसके साथ मारपीट करके पुलिस व सरकारी सशस्त्र बलों के प्रति अपनी नफरत प्रदर्शित की. विशेष बात यह है कि ऐसी मारपीट करने वालों में बुधराम की पत्नी भी थीं.

उपरोक्त दो घटनाएं इंद्रावती नदी की एक ओर की हैं. अब दूसरी ओर झांकेंगे. वहां हर हफ्ते उसपर गांव में साप्ताहिक बाजार का संचालन होता है. इस अभियान के दौरान इस बाजार को भी पुलिस बलों ने घेर लिया. बाजार करने आये लोगों को जब यह भनक लगी कि पुलिस बल उन्हें घेर रहे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने एक बैठक की. उस बैठक में यह फैसला किया कि कोई भी पुलिस का साथ नहीं देंगे. बाजार करने आए लोगों में कौन–कौन संगठन के लोग हैं, इसका पता पुलिस को नहीं देंगे. हालांकि सभी लोग उस निर्णय पर खड़े हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति पुलिस का साथ दिया. नतीजतन पुलिस कई लोगों को पकड़ कर भैरमगढ़ पुलिस कैंप में ले गयी. लेकिन कई महिलाओं ने सूझबूझ, हिम्मत व साहस के साथ कुछ लोगों को पुलिस के हाथों में पड़ने से बचाया. घटनास्थल में जिन लोगों को नहीं बचा पायीं उन्हें बचाने के लिए वे तुरंत ही भैरमगढ़ गयीं. वहां 3, 4 दिन लगातार लड़ती रहीं. इस लड़ाई के फलस्वरूप पुलिस ने सात लोगों को जेल भेज दिया. बाकी लोगों को छोड़ दिया.

27 नवंबर की रात को दक्षिण बस्तर डिविजन, किष्टारम एरिया के गट्टापाड गांव पर पुलिस हमला करके 8 लोगों को पकड़ कर इत्तागुप्पा थाना ले गई. गांव की कई महिलाएं इत्तागुप्पा जाकर पांच दिन संघर्ष करके 5 लोगों को छुड़ा लाईं. बाकी तीन लोगों को पुलिस सुकमा ले गई. 30 लोग जिनमें 9 पुरुष भी शामिल थे, सुकमा जाकर वहां तीन दिन तक लगातार लड़ कर सभी तीन लोगों को छुड़ा लाए.

5 दिसंबर को पुलिस बल किष्टारम एरिया के मेट्टागूडा गांव के पास एंबुश बैठे थे. ठीक उसी वक्त दूलोड गांव के साधारण गरीब आदिवासी माडवी सोमडाल वहां पहुंचे थे. पुलिस ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करके उनकी जघन्य हत्या की.

15 दिसंबर को केरलापाल एरिया के मूलेर गांव पर पुलिस ने हमला किया. पुलिस बलों को देख कर अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे पोडियम सन्नाल को पीछे से गोली मार कर पुलिस ने उनकी हत्या की. सन्नाल सीएनएम के सदस्य थे.

18 दिसंबर को बड़े पौमाने पर पुलिस बल एरिया में घुस गए थे. इस दौरान जारापल्ली के पास मिलिशिया पलटन के ऊपर पुलिस ने पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसाई. मिलिशिया सदस्या पोडियम जोगी ने जो उस वक्त निहत्थे थीं, इस गोलीबारी से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया. वेंपुरम तक भागने के बाद गोली लगने से घायल होकर वह पुलिस के चंगुल में फंस गई थीं. पुलिस ने न सिर्फ निर्मम

क्रांतिकारी दिवस

पीएलजीए सप्ताह

माड़ डिविजन

माड़ डिविजन के कुतुल एरिया में 2–8 दिसंबर तक पीएलजीए की 17 वीं वर्षगांठ जोर–शोर से मनायी गयी. पीएलजीए के संदेश को जनता में गहराई से पहुंचाने के मकसद से इस सप्ताह के पहले तीनों जन संगठन कमेटियों के सदस्यों को क्लास बताया गया. इसके बाद तीनों जन संगठनों द्वारा समन्वय रूप से प्रचार किया गया. बाद में पूरे इलाके में सभी पंचायतों में पंचायत स्तर की सभाओं का संचालन हुआ. एक जगह में बड़ी सभा का आयोजन हुआ. इस मौके पर 70 महिलाओं सहित करीबन 200 लोग जमा हो गए. पहले नारा लगाते हुए, गाना गाते हुए जुलूस निकाला गया. बाद में पार्टी और पीएलजीए के झंडें फहराए गए. शहीदों के स्मरण में दो मिनट मौन धारण करने के बाद क्रांतिकारी नाच–गानों के साथ सभा का प्रारंभ हुआ. सभाध्यक्ष के आमंत्रण पर वक्ताओं ने एक के बाद एक मंच पर आकर भाषण दिया. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनयुद्ध और जन सेना की आवश्यकता, इस साल भर में पीएलजीए द्वारा हासिल उपलब्धियों, पीएलजीए के सामने मौजूद अड़चनों और दिन ब दिन बदल रहे दुश्मन के दांव–पेंचों और दुश्मन की 'समाधान' योजना के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया. आक्रामक रूप से आनेवाले दुश्मन पर लगाम कसने के लिए प्रतिरोध को और मजबूत से आगे बढ़ाने, इसके लिए बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती होने का आह्वान किया गया. भाषणों के बीच में सीएनएम द्वारा पस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा जनता का उत्साह और बढ़ाया गया.

नेलनार एरिया में इस मौके पर सीएमसी द्वारा जारी संदेश को गांव–गांव तक पहुंचा दिया गया. पर्चों, पोस्टरों व बैनरों के साथ प्रचार किया गया. दो जगहों में जन सभाओं का आयोजन हुआ. इन सभाओं में वक्ताओं ने फासीवादी 'समाधान' हमले की योजना को मात देने, बड़े पैमाने पर युवाओं को पीएलजीए में भर्ती होने का आह्वान किया.

उत्तर बस्तर डिविजन

उत्तर बस्तर डिविजन के रावघाट एरिया में इस मौके पर गांव–गांव में क्रांतिकारी जोश के साथ जन सभाएं आयोजित की गयीं. इस दौरान पीएलजीए द्वारा हासिल की गई सफलताओं को जनता तक पहुंचाया गया. इस मौके पर गांव, साप्ताहिक बजारों और रोड किनारे पोस्टर एवं बैनर लगाए गए. और शहीदों के दो स्मारक बनाए गए.

प्रतापुर एरिया के मेंढकी, काकनार एलजीएस क्षेत्रों में गांव और पंचायत स्तर की जन सभाओं का आयोजन किया गया. इस दौरान दुश्मन के हमले की नई योजना ''समाधान'' के अंतर्गत प्रहार–2 अभियान के बीच में जनसंगठन सदस्य एवं क्रांतिकारी जनता जोश–खरोश के साथ सभाओं में शामिल हुई. इन सभाओं में पीएलजीए में युवती–युवकों को भर्ती कर फासीवादी रणनीतिक दमन योजना ''समाधान'' को हराने का संकल्प लिया गया. ★

यातनाएं दी बल्कि जोगी के साथ बलात्कार भी किया. बाद में उनकी हत्या की. शव को पुलिस पहले पामेड उसके बाद बीजापुर ले गई. लाश लाने परिजन व अन्य ग्रामीण जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, पहले पामेड, फिर वहां से बीजापुर गए. वहां से जनता ने लाश को पामेड ले जाकर पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग करते हुए आंदोलन किया. लेकिन वहां की पुलिस ने केस दर्ज करने से इंकार कर दिया, तो जनता ने जनवादियों की मदद पाने के लिए प्रयास किया. लेकिन उसे किसी से कोई मदद नहीं मिली. तब तक चार दिन बीत गए, तो लाश सड़ने लगी. इससे लाश को अपने गांव में ले जाकर दफनाने जनता मजबूर हो गई. जनता खासकर महिलाओं द्वारा किया गया यह संघर्ष एक मिसाल बन गया.

20 दिसंबर की रात को कोंटा क्षेत्र के गोंपाड पर हमला करने वाले पुलिस बलों ने मिलिशिया सदस्य सोयम चेंचाल को पकड़ा था. पुलिस ने उन्हें पेड़ से बांध कर बेरहमी से यातनाएं दी. उन्हें आत्मसमर्पण कराने और उनसे गांव के संगठन के गुप्त समाचार पाने की कोशिश में पुलिस बलों ने उन्हें अत्यंत अमानवीय तरीके से चाकू से गोदा. आखिर उनकी जान ली. बाद में मछली पकड़ रही महिलाओं पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलायी, जिसमें सोयम रामे नामक साधारण ग्रामीण युवती घायल हुई थीं. लेकिन पुलिस के डर से कई दिन तक रामे को इलाज के लिए नहीं ले जा सके. कुछ दिन के बाद तेलंगाना राज्य के भद्राचलम ले जाया गया. इसका पता चला, तो पुलिस टीम भद्राचलम गई. एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि चूंकि रामे केएएमएस की सदस्या है, इसलिए दवाखाना से डिस्चार्ज होते ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. दरअसल रामे किसी संगठन की सदस्या नहीं है. चेंचाल की लाश लेने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं एर्राबोर गई थीं.

21 दिसंबर को डब्बाकुंटा गांव पर हमला करने वाली पुलिस ने कमेटी सदस्य माडवी बंडी को पकड़ कर कई यातनाएं देकर उनकी हत्या की.

खूब संघर्ष करने के बावजूद कई घटनाओं में सभी लोगों को छुड़ाने में महिलाएं भले ही सफल नहीं हो पायीं हो, लेकिन उनका संघर्ष विजय के प्रति लोगों में जबर्दस्त उम्मीद जगाता है. और संघर्ष के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है. इस मायने में वे सफल संघर्ष ही माने जाएंगे. ★

अमर शहीदों की जीवनियां

कामरेड मड़कम गंगा (किशोर)

सांप के डंसने से दक्षिण बस्तर डिविजन में कार्यरत मिलिशिया कंपनी के कमांडर कामरेड किशोर की दुखद मौत हुई. 2 सितंबर, 2016 की आधी रात को जब वे नींद में थे सांप ने डंस लिया. उन्हें बचाने के लिए उनके साथी कामरेड्स द्वारा की गई कोशिशें विफल होने की वजह से 3 तारीख की सुबह उन्होंने दम तोड़ा.

दक्षिण बस्तर डिविजन के जगरगुंडा एरिया में ताड़मेटला गांव के एक गरीब परिवार में कामरेड किशोर का जन्म हुआ था. वे मां देवे व बाप हुंगाल की तीसरी संतान थे. उनके दो भाई और एक बहन हैं.

कामरेड किशोर ने पहले बाल संगठन में काम किया था. जब वे 16 वर्ष के हो गये स्थानीय कमेटी ने उनकी भर्ती मिलिशिया पलटन में करायी.

जनवरी, 2004 में वे पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने. जून 2004 से जून 2005 तक वे दक्षिण बस्तर की चौथी पलटन में कार्यरत थे. अनुशासन के साथ काम करते हुए उन्होंने पलटन का विश्वास जीता. कोंटा एरिया में विंजरम–बेज्जि रोड़ पर असिरिगुड़ा के पास एसटीएफ पर किए गए हमले में उन्होंने भाग लिया.

वे पीएलजीए व पार्टी के सभी कामरेडों के साथ घुल–मिल कर रहते थे. सभी कामों में पहलकदमी दिखाते थे. घर में पढ़ाई नसीब नहीं होने की वजह से उन्होंने लड़ाई के साथ ही पढ़ाई भी सीख ली. राजनीतिक व सैनिक मामलों पर पकड़ हासिल करने की लगातार वे कोशिश करते थे.

उनके अनुशासन, सैनिक क्षमता व सेवा भावना को नजर में रख कर जुलाई, 2005 में उन्हें एक एसजेडसी सदस्य के गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. वे तीन वर्ष तक इस जिम्मेदारी में थे. सलवा जुडुम के भीषण दमन में न सिर्फ उन्होंने अपने कमांडर की आंख की पुतली के समान रक्षा की बल्कि सलवा जुडुम को हराने के मकसद से की गई कई प्रतिरोध कार्रवाईयों में भाग लिया. एनएमडीसी पर किए गए हमले में उनकी भागीदारी थी.

अक्तूबर, 2006 में नेशनल पार्क के मुरकुड गांव के पास गश्त पर निकले पुलिस बलों के साथ अचानक हुई मुठभेड में अपने कमांडर को बचाने के लिए कामरेड किशोर ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया. इस प्रकार कामरेड किशोर ने अपने आप को एक आदर्श गार्ड के तौर पर साबित किया.

उनकी राजनीतिक चेतना व सैनिक क्षमता के मुताबिक 2008 में उन्हें एसी पदोन्नति के साथ–साथ रीजियन एक्शन टीम कमांडर की जिम्मेदारी दी गई. 2012 में उनकी शादी हुई. 2012 में रेक्की के लिए जगदलपुर गए कामरेड किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस की अमानवीय यातनाओं को सहन न कर पाने की स्थिति में कामरेड किशोर ने आत्मसमर्पण करने की सहमति जताई. लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाने में पुलिस का साथ नहीं दिया. छह महीने के बाद दुश्मन की आंखों में धूल झोंकते हुए वे भाग कर आए और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई.

चूंकि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया, इसलिए उनकी पार्टी सदस्यता की बर्खास्तगी हुई थी. हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन में फिर शामिल होने की उनकी अपील के तहत पार्टी ने उन्हें मौका देते हुए मिलिशिया में रखा था. पार्टी के निर्णय को स्वीकारते हुए उन्होंने मिलिशिया में काम करते हुए फिर पार्टी व जनता का विश्वास जीता. दो साल गोल्लापल्ली एलओएस में साधारण सदस्य रहे. एक साल उस दस्ते के डिप्युटी कमांडर की जिम्मेदारी निभाई. उनके व्यवहार एवं सक्रिय क्रियाकलापों की समीक्षा करने वाली पार्टी ने दो साल के बाद उन्हें पार्टी सदस्यता दी. और एक वर्ष के बाद 2016 में उन्हें एसी सदस्यता दी गई. शहादत के तीन महीने के पहले उन्हें किस्टारम एरिया मिलिशिया कंपनी के कमांडर की जिम्मेदारी दी गई. इसी दौरान उनकी शहादत हुई.

पीएलजीए ने एक अनुशासित, समर्पित व साहसिक योद्धा को खोया.

कामरेड किशोर अमर रहें!

बड़ेसेट्टी शहीदों को लाल–लाल सलाम!

28 सितंबर, 2016 को बड़ेसेट्टी गांव में मीटिंग करने गईं तीन महिला गुरिल्ला सदस्यों – बड़ेसेट्टी एलओएस की कमांडर कामरेड अंजू, उसी दस्ते की सदस्याएं कामरेड्स सुक्की व गुड्डी को पुलिस ने गांव में ही पकड़ा था. जनता की आंखों के सामने ही तीनों कामरेडों को बेरहमी से यातनाएं देकर उनकी हत्या की गई. इस निर्मम हत्या को पुलिस ने बेशर्मी से मुठभेड़ का नाम दिया.

दुश्मन द्वारा दी गई असहनीय यातनाओं को दृढ़संकल्प के साथ झेलते हुए आखिरी सांस तक जनता के पक्ष में अडिग रह कर अपनी अनमोल जान कुरबान करने वाली ये तीनों युवा कामरेड़ों को याद करेंगे.

कामरेड हेमला बुज्जि (अंजू)

दक्षिण बस्तर डिविजन, पामेड़ एरिया के गोरगनगूडेम के एक गरीब परिवार में कामरेड बुज्जि (27) का जन्म हुआ. वह मां–मुत्ति व बाप–सोमाल की दूसरी संतान थीं. उनकी तीन बहनें और तीन भाई हैं. कामरेड बुज्जि ने 8वीं तक पढ़ाई की. पढ़ाई करते हुए उन्होंने बाल संगठन में काम किया. 2007 में पढ़ाई छोड़ कर वह 21 अप्रैल, 2007 को पीएलजीए में भर्ती हुईं.

भर्ती से लेकर 2011 तक वह डिविजन मास (मोबाइल एकडेमिक स्कूल) टीम में कार्यरत थीं. साथी पीएलजीए कामरेडों को बुनियादी राजनीतिक विषय सिखाने में उनका अहम योगदान था. मार्च, 2011 में उनका तबादला केरलापाल एरिया में हुआ था. वहां उन्हें बड़ेसेट्टी एलओएस डिप्टी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई. 2012 में उनका तबादला एरिया डॉक्टर टीम में हुई. उस टीम का उन्होंने ही नेतृत्व किया. उस जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने सैकड़ों पीएलजीए सदस्य और जनता का इलाज किया. इलाज में वह न सिर्फ अंग्रेजी दवाई बल्कि जड़ी–बूटी का इस्तेमाल किया करती थीं. कामरेड अंजू का योगदान व क्षमता के मुताबिक 2014 में उन्हें एसी सदस्यता दी गई. उसके बाद उन्होंने डॉक्टर जिम्मेदारी के अलावा एरिया मोपोस की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई. गांव के जन संगठन के कार्यकर्ता और स्कूल–आश्रम छात्रों को क्रांतिकारी राजनीति से लैस करने के लिए वह प्रयास करती थीं.

जनवरी, 2016 में उन्हें बड़ेसेट्टी एलओएस कमांडर की जिम्मेदारी दी गई. कमांडर की हैसियत से उन्होंने गांव–गांव में पार्टी, क्रांतिकारी जन संगठन और जनताना सरकारों को मजबूत करने में अपना योगदान दिया. जन विरोधी मुखियाओं के विरोध में जनता को एकजुट करती थीं. लुटेरी सरकारी झूठे सुधार कार्यक्रम को जनता में भंडाफोड़ करती थीं. दुश्मन के बारे में पता चलते ही सैनिक कार्रवाई के लिए सभी कामरेडों के साथ तैयार होती थीं. अपने दस्ते के सदस्यों को राजनीति व सैनिक विषय अवगत करने की कोशिश करती थीं.

इस प्रकार कामरेड अंजू अपने क्रांतिकारी सफर में पार्टी द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को न सिर्फ बेहिचक उठाया बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक निभाने के लिए कड़ी मेहनत की. ऐसे में दक्षिण बस्तर डिविजन ने एक सक्षम युवा महिला कमांडर को खो दिया.

कामरेड अंजू अमर रहें!

कामरेड पोडियम सुक्की

दक्षिण बस्तर डिविजन, केरलापाल एरिया, कोंड्रे गांव में एक गरीब परिवार में कामरेड सुक्की (25) पैदा हुई थी. अपनी मां–बाप की पांच संतानों में वह बड़ी थीं. उनकी दो बहन व दो भाई हैं. कामरेड सुक्की ने तीसरी तक पढ़ाई की थी. बाल संगठन के जरिए उनका क्रांतिकारी सफर शुरू हुआ. नाच–गाने के प्रति उनकी दिलचस्पी को देख कर 2013 में उन्हें सीएनएम में भर्ती कर दिया गया. उसमें काम करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जनता की राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया.

2013 में उन्होंने पेशेवर क्रांतिकारी के तौर पर पीएलजीए में भर्ती होने की अपनी इच्छा जताई. कुछ अनुभव हासिल करने के लिए सीएनएम में ही काम करने के लिए उन्हें समझाया गया.

2015 में वह पीएलजीए में भर्ती होकर बड़ेसेट्टी एलओएस की सदस्या बनीं. उसमें काम करते हुए अपनी राजनीतिक व सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोशिश करती थीं. साथी कामरेडों के साथ मिल–जुल कर रहती थीं. अपने दस्ते द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहती थीं.

कामरेड सुक्की की शहादत की खबर सुनते ही न सिर्फ उनके परिजन बल्कि इर्द–गिर्द के गांवों के लोग इकट्टा होकर सुकमा जाकर उनकी लाश लाये. 29 सितंबर को क्रांतिकारी रीति–रिवाजों के अनुसार कामरेड सुक्की का अंतिम संस्कार किया गया.

कामरेड सुक्की अमर रहें!

कामरेड दूदी गुड्डी

दक्षिण बस्तर डिविजन, केरलापाल एरिया, मूलेर गांव के एक मध्यम किसान परिवार में कामरेड दूदी (18) का जन्म हुआ था. वह मां–जोगी व बाप देवाल की प्यारी संतान थीं. कामरेड दूदी के पिता गांव की कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए 2012 में अस्वस्थता के चलते शहीद हो गए. न सिर्फ क्रांतिकारी परिवार बल्कि क्रांतिकारी माहौल में पलने–बढ़ने की वजह से बचपन में ही कामरेड दूदी की जिंदगी क्रांति के साथ जुड़ गई. बाल संगठन में उनका योगदान था. 2014 में डीएकेएमएस में भर्ती होकर जीआरडी में भी अपने योगदान देने लगी. पंचायत मिलिशिया पीएल के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई. भूमि समतलीकरण आदि समष्टि क्रियाकलापों में वह शामिल होती थीं.

बचपन से ही पेशेवर क्रांतिकारी होने की आकांक्षा रखने वाली कामरेड गुड्डी ने जून, 2016 में गुरिल्ला जिंदगी में कदम रखा. बड़ेसेट्टी दस्ते में अपने योगदान देते हुए कुछ ही दिनों में उन्होंने शहादत को पाया.

कामरेड गुड्डी की शहादत की खबर सुनते ही उनके गांव की जनता एकजुट होकर सुकमा जाकर उनकी लाश लायी. क्रांतिकारी रीति–रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. 30 सितंबर को उनकी स्मारक सभा का आयोजन हुआ.

कामरेड गुड्डी अमर रहें!

कामरेड कारम नंदाल

दक्षिण बस्तर डिविजन के जगरगुंडा एरिया में एक पुलिस अभियान के दौरान रेक्की के लिए गए कामरेड नंदाल पुलिस बलों के हाथ लग गए थे. बुरी तरह यातनाएं देने के बाद अगले दिन यानी 12 दिसंबर, 2016 को तर्रेम और बुडगिन गांवों के बीच पुलिस ने गोली मार कर उनकी हत्या की. पुलिस ने हमेशा की तरह मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराने का झूठा दावा किया.

कामरेड कारम नंदाल 21 वर्ष पहले दक्षिण बस्तर डिविजन जगरगुंडा के उरसाम गांव के एक गरीब परिवार में सुक्की–जोगाल दंपति की चौथीं संतान के रूप में पैदा हुए थे. उनकी चार बहनें और एक भाई हैं. कामरेड नंदाल के परिवार गरीबी के चलते अपने पूर्वजों के गांव एडसुम को छोड़ कर उरसाम जाकर बस गए थे. मां–बाप ने कामरेड नंदाल की दुगाईगुड़ा गांव की स्कूल में भर्ती की. लेकिन गरीबी ने उन्हें दूसरी कक्षा तक ही पढ़ने की इजाजत दी. उसके बाद वे पढ़ाई छोड़ कर घरेलू व खेती कामों में मां–बाप का हाथ बंटाने लगे थे. साथ ही बाल संगठन में शरीक होकर जनता की सेवा करने लगे. बाद में उन्होंने जीआरडी में काम किया. उसमें काम करते हुए अपनी राजनीतिक व सैनिक क्षमता को बढ़ा कर जुलाई, 2014 में वे पेशेवर क्रांतिकारी बने थे. 2015 में उन्हें पलटन–30 में स्थानांतरित किया गया. वहां काम करते हुए वह प्राथमिक पढ़ाई और सैनिक प्रशिक्षण पर ध्यान देते थे. वे अनुशासन के साथ सामूहिक कामों में शामिल होते थे. साथी कामरेडों व जनता के साथ घुल–मिलकर रहते थे. बढ़ती अपनी राजनीतिक क्षमता के मुताबिक उन्होंने पार्टी सदस्यता हासिल की. बाद में उन्हें गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. कुछ वक्त गुजरने के बाद उनका तबादला जगरगुंडा एरिया में हुआ था. वहां काम करते समय वे पुलिस के हाथ लग गए थे. पुलिस द्वारा दी गई कई यातनाएं झेलने के बावजूद पार्टी की गोपनीयता को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान को कुरबान किया.

कामरेड नंदाल अमर रहें!

कामरेड ओयम हडमे

19 फरवरी, 2017 को दक्षिण बस्तर डिविजन, पामेड एरिया के मुंतम गांव के पास हुई मुठभेड़ के दौरान कामरेड हडमे दुश्मन के हाथ लग गई थीं. बहुत यातनाएं देने के बाद दुश्मन ने कामरेड हडमे की निर्मम हत्या की.

दक्षिण बस्तर डिविजन, पामेड़ एरिया, ऊसुर एलओएस, पोलमपल्ली पंचायत के टेकुलागुड़ेम गांव के एक गरीब किसान परिवार में 18 वर्ष पहले कामरेड हडमे का जन्म हुआ था. वह मां–सुक्की और पिता बिच्चेम की छठी संतान थीं. पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण 40 वर्ष पहले उनका परिवार पश्चिम बस्तर डिविजन के पिडिया गांव से पलायन करके इधर आया हुआ था.

कामरेड हडमे छोटी उम्र में ही क्रांति के प्रति आकर्षित हुई थीं. बाल संगठन के जरिए जन संघर्षों में शामिल हुई थीं. उनकी चेतना व क्षमता को देख कर ग्राम पार्टी कमेटी ने 2014 में उनकी पंचायत सीएनएम में भर्ती करायी. नाच, गाना, नाटक आदि कला रूपों के जरिए उन्होंने जनता में क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार किया. साथ ही खुद की चेतना व क्रांति के प्रति समर्पित भावना को बढ़ा कर अक्तूबर, 2015 में पेशेवर क्रांतिकारी बनीं. पहले उनकी नियुक्ति कृषि विभाग में हुई थी. प्राथमिक पढ़ाई सीखते हुए अपनी राजनीतिक व सैनिक क्षमता को विकसित करते हुए वह उत्पादन काम में शामिल हो गई थीं. एक साल काम करने के बाद एक ट्रैक्टर दर्घटना में वह घायल हुई थीं. जड़ी–बूटी दवाई का सेवन करके वह जल्द ही ठीक होकर अपनी जिम्मेदारी में आगे बढ़ी. उसी दौरान उनकी शहादत हुई.

जनता भद्राचलम जाकर तीन दिन लड़कर अपनी लाड़ली बेटी की लाश लायी. उनके आशयों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए क्रांतिकारी रीति–रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया.

कामरेड हडमे अमर रहें!

रानवाई शहीदों को लाल सलाम!

उत्तर गड़चिरोली डिविजन, चातगांव एरिया के रानवाई गांव के नजदीक 10 जुलाई, 2017 को जब गुरिल्ला दस्ते ने पनाह ली थी, इसकी खबर पाकर पुलिस बलों ने दस्ते को घेर लिया. उस वक्त संतरी में कामरेड ललिता और कामरेड जोगी तैनात थीं. दोनों कामरेडों ने पुलिस बलों को देखते ही अपनी बंदूक उठा कर दुश्मन पर गोलियां दागी. इससे न सिर्फ सभी कामरेड्स अलर्ट हो गए बल्कि दुश्मन

की घेराबंदी को तोड़ कर सुरक्षित निकलने में सफल हो गए. लेकिन कामरेड जोगी गोली लगने के कारण संतरी जगह पर ही शहीद हो गईं. जबकि कामरेड ललिता वहां से सुरक्षित निकल पायीं. हालांकि अगले दिन मुगनेर–एंदगांव के पास दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ में कामरेड ललिता और कामरेड सुक्की शहीद हुईं.

कामरेड शंतो मडावी (ललिता)

22 वर्षीय कामरेड ललिता कंपनी–4 की सदस्या थीं. वह गडचिरोली जिला, धनोरा तहसील, टिप्रागढ़ एरिया के वडगांव के सिरोंदा और निरंगसाय मडावी दंपत्ति की पांच संतानों में सबसे छोटी थीं. मां–बाप ने अपनी लाड़ली का नाम शंतो रखा था. कामरेड शंतो ने बचपन में ही अपने पिता को खोया.

कामरेड शंतो चौथी तक पढ़ाई की. एक साल केएएमएस में काम करने के बाद वह पेशेवार क्रांतिकारी बन कर पीएलजीए में भर्ती हुई थीं. तीन महीने तक उन्होंने स्थानीय गुरिल्ला दस्ते में अपना योगदान दिया. उसके बाद उन्हें कंपनी–4 में स्थानांतरित किया गया था. कंपनी में उन्होंने सीएनएम जिम्मेदारी निभाई. वह पत्रिकाएं और पार्टी साहित्य ध्यान से पढ़ती थीं. अन्य कामरेडों से राजनीतिक विषय सीखने के लिए कोशिश करती थीं. वह कई सैनिक कार्यवाहियों में शामिल थीं. सैनिक कार्यवाहियों में वह कभी पीछे नहीं हटी. कमांडर के आदेशों का बराबर पालन करते हुए दृढ़संकल्प के साथ लड़ने के लिए कोशिश करती थीं. 2011 में किए गए खोब्रामेंडा और 2012 में किए गए निहायकल नाईट एंबुश में वह शामिल थीं. एंबुश और डेरा पर पुलिस द्वारा किए गए हमलों में वह हिम्मत के साथ दुश्मन से लोहा लेती थीं.

कामरेड ललिता अमर रहें!

कामरेड माडवी सुक्की

कामरेड माडवी सुक्की दक्षिण बस्तर डिविजन जगरगुंडा एरिया के सुरपन गांव के एक मध्यम किसान परिवार में 19 वर्ष पहले पैदा हुई थीं. उनकी मां बुदरी और बाप हडमा. कामरेड सुक्की के पूर्वज अरनपुर से आजीविका तलाशते हुए इस गांव में जाकर बस गए थे. गांव में रहते समय कामरेड सुक्की सीएनएम में काम किया था. उस कमेटी की सदस्या भी थीं. जनवरी, 2017 में ही वह पेशेवर क्रांतिकारी बनी थीं. जन युद्ध को देश के कोने–कोने में फैलाने के मकसद से उच्च चेतना को दर्शाते हुए उन्होंने गडचिरोली में कदम रखा था. मगर कुछ ही दिनों में उनकी शहादत हुई.

कामरेड सुक्की अमर रहें!

कामरेड माडवी जोगी

माडवी जोगी 18 वर्ष पहले दक्षिण बस्तर डिविजन पामेड एरिया के मडपे दूलोड गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थीं. वह देवे और माडवी सोमडा की बेटी थीं. उनके पूर्वजों का गांव बुडूम है. गांव में रहते समय उन्होंने सीएनएम में अपना योगदान दिया था. दिसंबर 2016 को वह पेशेवर क्रांतिकारी के तौर पर पीएलजीए में भर्ती हुई थीं. कुछ ही दिनों में उनका तबादला किया गया था. क्रांतिकारी जरूरतों के अनुसार कहीं भी जाने की इच्छा जताते हुए उन्होंने हंसी–कुशी से गडचिरोली डिविजन में कदम रखा था.

कामरेड जोगी के पिता डीएकेएमएस के साधारण सदस्य थे. बेटी की शहादत की खबर उन्हें नवंबर में मिली थी. इस दुख से वे उबरे नहीं थे. 5 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें पकड़ कर झूठी मुठभेड़ में उनकी निर्मम हत्या की. इसी अंक में उनकी हत्या की खबर भी छपी गई.

कामरेड जोगी अमर रहें!

कामरेड रामय्या पोट (मंगरू)

23 जुलाई, 2017 को दक्षिण गडचिरोली डिविजन, अहेरी एरिया कौटारम गांव के पास ठहरे गुरिल्ला दस्ते को घेर कर पुलिस बलों द्वारा किए गए धोखेबाजीपूर्ण हमले में वरिष्ठ कामरेड रामय्या पोरतेट की शहादत हुई. पार्टी में कामरेड रामय्या पोरतेट का नाम मंगरू था. जबकि सभी लोग उन्हें प्यार और सम्मान से मंगरू दादा कह कर पुकारते थे.

दक्षिण गडचिरोली डिविजन, अहेरी एरिया के मरपल्ली गांव में करीबन 50 वर्ष पहले कामरेड रामय्या का जन्म हुआ था. उनके मां–बाप आजीविका तलाशते हुए झंडा गांव से उस गांव में जाकर बस गए थे. रामय्या मां–बाप के बड़े बेटे थे. उनकी दो बहनें और दो भाई हैं. चूंकि बचपन में ही उन लोगों के सिर से मां–बाप का साया उठ गया था इसलिए अपने चाची–चाचा के घर में उनकी परवरिश हुई थी. कामरेड रामय्या शादी–शुदा थे. पत्नी और छह बच्चों को वे अपने पीछे छोड़ गए थे.

गडचिरोली जिले में जब क्रांतिकारी आंदोलन ने दस्तक

दी थी, तभी कामरेड मंगरू की जिंदगी उस से जुड़ गई थी. क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय रूप से काम करते हुए वन विभाग, साहूकार और गांव के मुखियाओं के जुल्म व लूट के खिलाफ संचालित संघर्षों में वे शामिल हुए थे. 1984 में कमलापूर अधिवेशन में वे शामिल हुए थे. अकाल व शराब के विरोध में, बांस कटाई मजदूरी बढ़ाने के लिए लोगों को गोलबंद करने में और उन्हें संघर्ष की राह में आगे बढ़ाने में कामरेड मंगरू का योगदान रहा. बढ़ते जन संघर्ष और हिलते लुटेरे किलों को देख कर बौखलाए दुश्मन ने डिविजन के आंदोलन को कुचलन के लिए बड़े पैमाने पर दमन जारी रखा. कामरेड्स रेगुलवाया लक्ष्मण, आत्रम शंकर और पोरतेट लिंगन्ना जो कामरेड मंगरू के हमराह थे, की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या की गई थी. 1990–91 तक 74 लोगों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या की गई. इस तरह पूरे डिविजन में दहशत का माहौल फैलाया गया. ऐसी परिस्थिति में कामरेड मंगरू पुलिस से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे. हालांकि कुछ दिन के बाद, इस दमन को सही हिसाब से न समझने की वजह से उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. लेकिन बाद में भी वे आंदोलन की गतिविधियों में शामिल होते रहे. फिर संगठन में सक्रिय हो गए. 1988 में जीआरडी कमांडर का दायित्व निभाया. उनकी सक्रियता को देख कर पुलिस बल फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश में लग गए थे. कामरेड मंगरू इस जिद्द कि पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, के साथ 2000 में पेशेवर क्रांतिकारी बन कर भूमिगत हो गए थे.

2001 में तत्कालीन अहेरी डिप्यूटी कमांडर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करके गद्दार बन गया. चूंकि उसने एरिया के सभी निर्माणों की सूचना पुलिस को दी थी, इसलिए जनता पर पुलिस जुल्म बढ़ गया. इसका प्रभाव पार्टी पर बेहद नकारात्मक रहा. दस्ते के लोग गांव में जाने पर जनता बहुत झगड़ा करती थी. दस्ते का खान–पान तक भी मुश्किल होता था. इस कठिन परिस्थिति में कामरेड मंगरू ने समझा–बुझा कर फिर जनता में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की. परिस्थिति थोड़ी सुधरने लगी, तो दस्ते के कमांडर और डिप्यूटी कमांडर सरेंडर हो गए. उस वक्त कामरेड मंगरू ने डिप्युटी कमांडर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा कर जनता और कामरेड्स में हिम्मत बढ़ाने और उन्हें संघर्ष की राह पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई.

दक्षिण गडचिरोली डिविजन के सिरोंचा, अहेरी, पेरिमिलि और भामरागढ़ क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया. पीएलजीए में भर्ती होने के लिए वे युवाओं को प्रोत्साहन देते थे. पीएलजीए के नए सदस्यों की बेहद मदद करते थे. टेर्रेन के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी.

आंदोलन के सभी उतार–चढ़ावों में उन्होंन आंदोलन व जनता के पक्ष में अडिग रहे थे. उन्हें आत्मसमर्पण कराने दुश्मन द्वारा की गयी सभी कोशिशें नाकाम रहीं. कामरेड मंगरू को खोना अहेरी एरिया के लिए बड़ा नुक्सान है.

कामरेड मंगरू अमर रहें!

कामरेड मंगली

उत्तर गडचिरोली डिविजन, चातगांव एरिया के भेंडी कन्हार गांव के पास 15 सितंबर, 2017 को हुई मुठभेड़ में चातगांव एरिया के स्थानीय दस्ते की सदस्या कामरेड मंगली की शहादत हुई. मुठभेड़ के वक्त कामरेड मंगली संतरी पर थीं. उन्होंने अपनी जान कुरबान करके अपने दस्ते को बचा लिया.

कामरेड मंगली पश्चिम बस्तर डिविजन के पिडिया गांव में पैदा हुई थीं. पेशेवर क्रांतिकारी बनने के तुरंत बाद यानी अक्तूबर, 2015 में उनका तबादला चातगांव दस्ते में हुआ था. उसी समय उन्हें पार्टी सदस्यता दी गई. चातगांव एरिया में पुलिस दमन तीव्र रूप से जारी है. इस दमन का सामने करते हुए एक–दो साल में 4–5 कामरेडों ने शहादत को पाया जिनमें एरिया की जिम्मेदार रही डीवीसीएम कामरेड सम्मा उसेंडी भी शामिल थीं. बहुत कम समय में ही कामरेड मंगली ने 7–8 मुठभेड़ों का सामना किया. इसके बावजूद संघर्ष की जरूरतों को सटीक समझने वाली कामरेड मंगली इस एरिया में डटी रहीं.

नए एरिया में नए कामरेड्स और नयी जनता से घुलमिल जाते हुए नयी भाषा सीखते हुए वह आगे बढ़ती रहीं. किसी भी तरह के काम करने के लिए वह हर पल तैयार रहती थीं. इस क्रम में ही उन्होंने शहादत को पाया.

कामरेड मंगली अमर रहें!

कामरेड राजे मडकाम (सोनी)

14 अक्तूबर, 2017 को उत्तर गडचिरोली डिविजन, टिप्रागढ़ एरिया, टव्वेकस्सा गांव के पास गुरिल्ला दस्ते के मुकाम पर दुश्मन द्वारा किए गए हमले में टिप्रागढ़ एरिया कमेटी सदस्या कामरेड सोनी की शहादत हुई.

कामरेड सोनी 36 वर्ष पहले दक्षिण बस्तर डिविजन, कोंटा एरिया, टेट्राई गांव के एक मध्यम वर्गीय दोरला समुदाय के परिवार में पैदा हुई थीं. वह मां दूले और पिता मडकम कन्ना की पांच संतानों में दूसरी थीं. उनकी तीन बहनें और एक भाई हैं. मां–बाप ने अपनी लाड़ली बेटी का नाम राजे रखा था. क्रांतिकारी माहौल में पलने–बढ़ने की वजह से बचपन में ही कामरेड राजे ने क्रांति की राह अपना ली.

कामरेड सोनी 1998 में पेशेवर क्रांतिकारी बन कर पीएलजीए में भर्ती हुई थीं. 1999 में उनका तबादला गडचिरोली जिले में हुआ था. तब से लेकर शहादत तक उसी जिले में वह उपना योगदान देते रहीं.

गडचिरोली डिविजन में कदम रखने के बाद जल्द ही कामरेड सोनी जनता के रीति–रिवाज को समझ लिया. और नयीं भाषाएं सीखीं. क्रांति में कदम रखने के बाद ही साक्षर होने के बावजूद कामरेड सोनी हिंदी और गोंडी अच्छे से पढ़ती थीं. तेलुगु, छत्तीसगढ़ी भाषाएं भी सीखी थीं. चेतना नाट्य मंच की डिविजन टीम की सदस्या रह कर उन्होंने क्रांतिकारी कार्यक्रमों से उत्तेजित करके युवती–युवकों को पीएलजीए में भर्ती किया.

दंडकारण्य को मुक्तांचल बनाने के लक्ष्य से गडचिरोली डिविजन में बने भामरागढ़ गुरिल्ला बेस में क्रांतिकारी जनताना सरकार के निर्माण के लिए जनता को संगठित करने, मिलिशिया का निर्माण करने और गांव की पार्टी को मजबूत करने में एक एसी सदस्या के तौर पर कामरेड सोनी का योगदान रहा. कामरेड सोनी सहित एसी के सभी कैडरों के प्रयासों के फलस्वरूप गडचिरोली जिले में 2006 में पहली जनताना सरकार का गठन हुआ.

2010 में कामरेड सोनी का तबादला टिप्रागढ़ एरिया में हुआ था. तब से अपनी शहादत तक उन्होंने वहीं पर अपना योगदान दिया. टिप्रागढ़ एरिया में पार्टी, पीएलजीए, जनताना सरकार और जन संगठनों को मजबूत करने के प्रयासों में उनका योगदान रहा. जनता में जल, जंगल, जमीन, अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की चेतना बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. विस्थापन और सरकारी हिंसा के खिलाफ जारी प्रतिरोध में उन्होंने अपने हिस्से की भूमिका निभाई.

2003 में कामरेड सोनी का विवाह अपने एरिया कमांडर से हुआ. दोनों ही एक अच्छी समझदारी के साथ क्रांतिकारी जरूरतों के अनुसार अलग–अलग यूनिटों में काम करते रहे.

अविश्रांत मेहनत करते हुए आंदोलन में अपनी भूमिका, राजनीतिक चेतना और सांगठनिक क्षमता को बढ़ाते हुए वह एक सक्षम नेत्री के तौर पर उभरी थीं. पार्टी में सीनियर महिला कामरेडों का योगदान देख कर उनकी क्षमताओं को और विकसित करने के लक्ष्य से चयनित डीवीसी कोर में कामरेड सोनी भी थीं. ऐसे में उन्हें खोना गडचिरोली आंदोलन के लिए बड़ा नुक्सान है.

कामरेड सोनी अमर रहें!

कोपेनखड़का शहीदों को लाल सलाम!

राजनांदगांव जिला, मानपुर ब्लॉक, खड़गांव एरिया के कोपेनखड़का गांव में 25 अक्तूबर, 2017 की रात 9–10 बजे को हुई मुठभेड़ में कामरेड महेश (एसीएम), कामरेड राकेश (एसीएम), कामरेड रंजित (पीएम) शहीद हुए.

कामरेड राजू ओयामी (महेश)

कामरेड ओयामी राजू (महेश) 28 वर्ष पहले बीजापुर जिला, भैरमगढ़ एरिया, तिम्मेम गांव के एक गरीब परिवार में जन्मे थे. मां–बाप की पांच संतानों में वे सबसे बड़े थे. कामरेड राजू बचपन में ही क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित हो गए. उनकी मां बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं. लेकिन फासीवादी सलवाजुडुम अभियान के कारण कामरेड राजू को पांचवीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

तिम्मेम गांव का सलवा जुडुम से डटकर मुकाबला करने का इतिहास रहा. इस विरासत को जारी रखते हुए कामरेड राजू क्रांतिकारी क्रियाकलापों में शामिल हुए थे. कुछ दिन के बाद उन्होंने पूर्णकालिन कार्यकर्ता बनने की इच्छा पार्टी के सामने जतायी थी. अनुभव हासिल करने के लिए उन्हें कुछ दिन मिलिशिया में रखा गया था. मिलिशिया में रह कर राजनीति व सैनिक विषय सीखने के लिए उन्होंने कोशिश की. उन्हें कुछ दिन कृषि विभाग में भी रखा गया था. उसके बाद उन्हें पेशेवर क्रांतिकारी के तौर पर पीएलजीए में भर्ती किया गया.

2007 में कामरेड राजू का तबादला मानपुर डिविजन में हुआ था, जहां वे महेश के नाम से लोकप्रिय हो गए थे. उस डिविजन में उनकी नियुक्ति एलजीएस–3 में हुई थी. नये एरिया में आने के कुछ ही दिनों में उन्होंने जनता और नौजवानों से दोस्ती करते हुए वहां की भाषा सीखी थी. और वहां के गांवों व जंगलों पर पकड़ हासिल की. उनके राजनीतिक–सैनिक अनुशासन को देखकर पार्टी ने कामरेड राजू को 2009 में पीपीसी में लिया. इसी समय उन्हें एलजीएस–1 के डिप्युटी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई.

डिविजन में मौजूद बेशकीमती खनिज संपदा को लूटकर ले जाने के लिए यहां के संघर्ष को खत्म करने के मकसद से इलाके में कार्पेट सेक्युरिटी के तहत कई पुलिस कैंप लगाए गए. जनता पर भीषण दमन शुरू हुआ. कुछ लोग पार्टी को छोड़ कर भाग गए. कुछ लोग गद्दार बन कर पुलिस के साथ मिल कर जनता पर हमलें करने लगे. ऐसी कठिन परिस्थिति में कामरेड महेश ने कैडरों एवं जनता को राजनीतिक रूप से समझाते हुए संघर्ष में खड़ा करने में अहम भूमिका निभायी. दुश्मन के हमलों का मुकाबला

करते हुए जनता में हिम्मत बढ़ायी. उनकी पहलकदमी एवं हिम्मत को देख कर कामरेड महेश को 2010 में एलजीएस–2 का कमांडर बना कर पल्लेमाड एरिया की जिम्मेदारी दी गई. इस एरिया में जनता को गोलबंद करते हुए खदान के खिलाफ जारी संघर्ष को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया. इस संघर्ष के फलस्वरूप पल्लेमाड खदान बंद हो गया. 2012 में एक साल के लिए वे पल्लेमाड दस्ते के कमांडर रहे थे.

सैनिक क्षेत्र में भी कामरेड महेश का अहम योगदान रहा. 2008 के विधानसभा चुनाव के समय पुलिस जीप पर फायरिंग करने में उन्होंने पहलकदमी दिखायी. 2008 में महामाया खदान में 2 टन जेलटिन जब्त करने की कार्यवाही में कामरेड महेश शामिल थे. 2008 में पल्लेमाड एरिया में किए गए अड़जाल एंबुश में कामरेड राजू की सक्रिय भागीदारी थी.

2014 में उन्होंने डिविजन कमांड सदस्य बन कर कोतरी एरिया की मिलटरी जिम्मेदारी उठाई. एक्शन टीम कमांडर का दायित्व भी उन्होंने निभाया. 2014 में लोकसभा चुनाव के समय में उनके नेतृत्व में किए गए विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान मारा गया. गद्दार लालसु को खत्म करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

डिविजन संघर्ष में कामरेड महेश का दस साल का महत्वपूर्ण योगदान रहा. बढ़ती उनकी भूमिका को देख कर दुश्मन ने टार्गेट करके उन्हें खत्म करने के लिए कई प्रयास किए. नतीजतन महेश को कम से कम 11 बार मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा, जिनका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया. फरवरी, 2017 में उन्होंने फिर पल्लेमाड एरिया की जिम्मेदारी उठा ली थी. इसी क्रम में 18 जून को पेंदोड़ी गांव के पास मुठभेड़ हुई. जिसमें कामरेड्स समीला, समीर और रम्मो शहीद हुए. कामरेड महेश के नेतृत्व में उन गद्दारों, जिनके द्वारा दिए गए समाचार पर वह मुठभेड़ हुई थी, को खत्म किया गया और नेटवर्क ध्वस्त किया गया. इसके तुरंत बाद राजनीतिक कार्यक्रम लेकर उनका दस्ता जनता के पास गया था. इसी क्रम में हुई मुठभेड़ में उनकी शहादत हुई.

कामरेड महेश अमर रहें!

कामरेड दुरवा मालू (राकेश)

नरायणपुर जिला, ओरछा ब्लॉक, पोरयुल आरपीसी के तोयनार गांव कामरेड मालू का जन्म स्थान था. माड़ इलाके के भूमि पुत्र कामरेड मालू एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे. मां–बाप की तीन संतानों में वे सबसे छोटे थे. बीमारी की वजह से मां गुजर गईं तो, पिता ने बच्चों का पालन–पोषण किया. कामरेड मालू के बड़े भाई जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में काम किया करते थे. उनकी दीदी भी 2006 में पार्टी में भर्ती हुई थी. हालांकि 2011 में वह घर वापस गईं. न सिर्फ गांव बल्कि परिवार के क्रांतिकारी माहौल के प्रभाव से 2006 में कामरेड मालू बाल सीएनएम में भर्ती हुए थे. उन्होंने उसका अध्यक्ष का पदभार भी संभाला. बाद में मिलिशिया में भर्ती हुए. उसी समय सलवा जुडुम शुरू हुआ. उसके खिलाफ संचालित प्रतिरोध में कामरेड मालू ने सक्रिय रूप से भाग लिया. सलवा जुडुम के गुंडों को सजा देने में भी उनकी भागीदारी थी.

2007 में कामरेड राकेश पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन गए. 2007 आखिरी में उनका तबादला एलजीएस में किया गया. एलजीएस में काम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई, सैनिक और राजनीतिक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया.

2008 में दुश्मन द्वारा संचालित ''इंद्रावति अभियान'' को विफल करने के लिए पीएलजीए ने एंबुश किया. इससे दुश्मन का अभियान विफल हुआ. इस एंबुश में कामरेड राकेश ने भी पहलकदमी के साथ भाग लिया.

2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर आये पुलिस बलों पर सबसे आगे रहकर कामरेड राकेश ने फायरिंग की थी. उस फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हुआ. 2011 में उन्हें एसजेडसीएम गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. दो साल तक उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद 2013 में कामरेड राकेश का तबादला आरकेबी डिविजन में हुआ था. तब से शहादत तक उस डिविजन के पल्लेमाड़ क्षेत्र में ही कार्यरत थे. कामरेड राकेश पल्लेमाड इलाके में जारी तीव्र दमन के चलते होने वाले बलिदानों और कुछ नेतृत्वकारी कमांडरों की गद्दारी से उपजी कठिन परिस्थितियों में टिके रहे और जनता के विश्वास को जीत लिया.

2013 से 2017 अक्तूबर तक पल्लेमाड़ एसी में 10 मुठभेड़ें हुईं. इन मुठभेड़ों में 8 कामरेड शहीद हुए. इन मुठभेड़ों में अपने दस्ते को बचाने के लिए कामरेड राकेश ने दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला किया. खासकर दिसंबर, 2016 में कोपेनखड़का गांव के पास तमाम दस्ता दुश्मन के एंबुश में फंस गया था. उस मुठभेड़ में कामरेड मीना गंभीर रूप से घायल हुई थीं. कामरेड राकेश गोलीबारी के बीच में ही कामरेड मीना को अपने कंधों पर लादकर लाये थे. हालांकि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से कामरेड मीना शहीद हुई. कामरेड राकेश टीसीओसी और प्रतिरोध कार्यवाहियों को सफल बनाने की बेहद कोशिश करते थे.

2015 और 2016 में पल्लेमाड़ क्षेत्र में दो जगहों में एंबुश करके दुश्मन बलों को घायल करने में वे शामिल रहे.

2013 से 2017 अक्तूबर तक खदानों पर तीन बार हमला कर शोषक–शासक वर्गों के करोड़ों रुपयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में, 2016 में पल्लेमाड़ खदान के मैनेजर को खत्म करने में कामरेड राकेश की भागीदारी थी.

कारपेट सेक्युरिटी के बीच में काम करने की क्षमता व अनुभव को कामरेड राकेश ने हासिल किया था. डिविजन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कामरेड राकेश बोल्शेविक स्फूर्ति के साथ दिन–रात मेहनत करते थे. अपने साथी कामरेडों से, जनता से विन्रमता के साथ पेश आते थे. गद्दारों से नफरत करते हुए कामरेडों में हिम्मत और विश्वास बढ़ाते थे. पल्लेमाड इलाके ने एक सीधा–साधा, मेहनती, साहसी, अनुशासित और मिलनसार स्वभाव के कामरेड को खो दिया.

कामरेड राकेश अमर रहें!

कामरेड सुखलाल नरोटी (रंजित)

कामरेड सुखलाल का जन्म नारायणपुर जिला, नारायणपुर ब्लॉक, उच्चाकोट गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था. गरीबी के चलते मात्र 6वीं पढ़ने के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

रावघाट पहाड़ के नजदीकी गांव होने के चलते उच्चाकोट में लंबे अरसे से क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई में जन संघर्ष खासकर विस्थापन विरोधी आंदोलन जारी है. इस माहौल में पलने–बढ़ने की वजह से कामरेड रंजित बचपन में ही क्रांति का रास्ता अपना लिया. बाल संगठन में काम करते हुए जवान हो गए. बाद में मिलिशिया के सदस्य बन कर जनता की रक्षा में लग गए थे. उस वक्त कई बार वे सेकंडरी बलों के साथ फौजी कार्यवाहियों में भाग लिया करते थे. 2008 में वे पेशेवर क्रांतिकारी बन गए. भर्ती होने के कुछ ही समय में उनकी नियुक्ति एसजड़सीएम गार्ड के तौर पर हुई थी. पांच वर्ष तक उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. गार्ड के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सी फौजी कार्रवाईयों में भाग लिया था. राजनीतिक व सैनिक प्रशिक्षण हासिल किया. पार्टी जरूरतों के मुताबिक उन्होंने मोटर साइकिल चलाना सीख लिया. स्नाईपर ट्रेनिंग हासिल करके वे शार्प शूटर बनने हमेशा प्रैक्टिश करते थे.

2014 में उनका तबादला आरकेबी डिविजन में हुआ था. आंदोलन पर नाकारात्मक असर डालने वाले पहलुओं जैसे तीव्र दमन, कार्पेट सेक्युरिटी, आत्मसमर्पण और गद्दारी आदि को भी सटीक समझते हुए वे वहां के आंदोलन में डटे रहे. कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए उद्दश्यित पार्टी के बोल्शेवीकरण के तहत जारी राजनीतिक व सैनिक प्रशिक्षण में उन्होंने भाग लिया.

आरकेबी डिविजन में उनकी नियुक्ति पल्लेमाड़ क्षेत्र में हुई थी. इस इलाके में नए–नए खदान खुलवाने के लिए दिन–ब–दिन दमन बढ़ रहा है. ऐसे में यहां काम करना हर कैडर के लिए एक चुनौती है. उस चुनौती को कामरेड रंजित हिम्मत व साहस के साथ स्वीकार किया. उन्होंने जनता के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया. टेर्रेइन पर भी पकड़ हासिल की. इसी क्रम में उन्होंने चार मुठभेड़ों का सामना किया. 2014 दिसंबर में हुई एक मुठभेड़ के दौरान संतरी में तैनात कामरेड रंजित हिम्मत व पहलकदमी दिखाते हुए फायरिंग करके दस्ते को सुरक्षित निकालने में अपनी जिम्मेदारी निभायी. जवकि गांव के पुलिस कैंप, जो पल्लेमाड़ खदान की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, के 50 गज दूर में जाकर बूबीट्रॉप लगाकर आये थे. ऐसे एक जाबांज योद्धा थे वे.

टीसीओसी कार्यवाहियों, खनन कार्य में लगी गाड़ियों को जलाने, नेटवर्क को ध्वस्त करने, गोदावरी खदान एजेंट को गोली मारकर घायल करने, रेल लाईन की सुरक्षा के लिए आये एसएसबी जवानों पर एंबुश करने और पंचायत चुनाव प्रतिरोध में उन्होंने भाग लिया.

राजनीतिक व सांगठनिक मामलों पर वे खुल कर चर्चा करते थे. बिना हिचकिचाहट अपनी राय जाहिर करते थे. वह एक मेहनती व अनुशासित कामरेड थे. कोई भी काम करने के लिए वह हर पल तैयार रहते थे.

कामरेड रंजित अमर रहें!

कामरेड बदरू (करण)

3 नवंबर, 2017 को गडचिरोली जिला, भामरागढ़ ब्लॉक, कोडोर गांव के समीप जंगल में सी–60 कमांडों बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कामरेड करण की शहादत हुई.

कांकेर जिला, कोयलीबेड़ा ब्लॉक, प्रतापुर पंचायत के चींदटोला के गरीब आदिवासी परिवार में कामरेड बदरू का जन्म हुआ था. उन्होंने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की. बाद में गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़कर खेती–किसानी में अपने मां–बाप का हाथ बंटाता था.

वह बालक संगठन में होशियारी से काम करते थे. बड़े होने के बाद क्रांतिकारी जनताना सरकार की रक्षा के लिए जन मिलिशिया के सदस्य बन गए. 2004 में वह गांव के डीएकेएमएस अध्यक्ष चुने गए. उस हैसियत से उन्होंने जन आंदोलनों में सैकड़ों जनता को गोलबंद किया.

जनता की समस्याओं के बारे में उनकी अच्छी समझदारी थी. जनता की इन समस्याओं को हल करने के लिए लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत को उन्होंने समझ लिया. पीएलजीए में भर्ती होने की पार्टी के आह्वान को स्वीकारते हुए 2007 में वह स्थानीय दस्ते में भर्ती हो गए.

उन्होंने तीन साल 5वीं पीएल में काम किया. 2010 में उन्हें सीओबी भेज दिया गया. वहां कम समय में ही बोलंगीर, बरगढ़, महासमुंद डिविजन में जनता के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया. जल्द ही उन्होंने ओडिया भाषा सीख ली. ओडीया भाषा में ही वहां की जनता में पार्टी की राजनीति को प्रचार करने में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभायी. छत्तीसगढ़ राज्य से ओडिशा राज्य को जब क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार होने लगा, दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा उस विस्तार को रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया. उस अभियान को विफल करने पार्टी द्वारा संचालित प्रतिरोध कार्रवाईयों में कामरेड करण हिम्मत के साथ शामिल हुए. इस प्रकार पार्टी के विस्तार में उन्होंने अपनी भूमिका निभायी.

छत्तीसगढ़–झारखंड राज्यों के बीच में समन्वय को जोड़ने में कामरेड करण ने अपनी जिम्मेदारी निभायी.

2013 में वह सीसी गार्ड के रूप में चुने गये. उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने अनुशासन, साहस, जुझारूपन, मेहनती स्वभाव, कैडरों और जनता के साथ घनिष्ठ संबंध, विनम्र व्यवहार आदि अच्छे गुणों से उन्होंने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया था. अलग–अलग राज्यों, डिविजनों में संचालित प्रतिरोध कार्रवाईयों में उनकी भागीदारी थी. 2013 में कामरेड करण को एसी सदस्यता दी गयी. गार्ड टीम कमांडर की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभायी.

समय का सटीक इस्तेमाल करते हुए वे पार्टी के दस्तावेज, सर्कुलर, पत्रिका पढ़ा किया करते थे. और साथी कामरेडों को पढ़ाते थे.

अपनी जान की जरा भी परवाह न करने वाले कामरेड करण आत्मबलिदान की उच्च भावना का प्रदर्शन किया.

कामरेड करण अमर रहें!

कन्नाईपाड़ अमर शहीदों को लाल सलाम!

बटालियन–1 में कार्यरत कामरेड सोड़ी सीता (पीपीसीएम) और कामरेड सोड़ी लखमा (पीएम) क्रांतिकारी जरूरतें निपटाने के लिए जब कोंटा थाना के अंतर्गत कन्नाईपाड़ गांव गए थे, इस खबर से वाकिफ पुलिस बलों ने रातों–रात मोटार साइकिलों पर आकर गांव में सोये हुए दोनों साथियों को पकड़ लिया. क्रूर पुलिस बलों ने दोनों के हाथ बांध कर निर्मम यातनाएं दी थी. अगले दिन, 17 नवंबर, 2017 की सुबह को सुन्नमगुड़ा गांव की मोल्लोलबंडा टोली के पास गोली मार कर उनकी हत्या की. बाद में हमेशा की तरह पुलिस द्वारा यह दावा किया गया कि दोरनापाल क्षेत्र में नक्सलियों के साथ एक घंटे तक हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार दिया गया जोकि कोरा झूठ है.

कामरेड सोड़ी सीता

कामरेड सीता सुकमा जिला, कोंटा तहसील के पुराना नेंड्रा गांववासी थे. पहले उन्होंने अपने गांव के मिलिशिया में सक्रिय रूप से काम किया था. कई सैनिक कार्रवाईयों में वे शामिल थे. जुलाई, 2005 में वे पूर्णकालिन कार्यकर्ता बने थे. कोंटा एरिया में उन्होंने काम किया. 2007 में उन्हें जन मिलिशिया कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने सक्षम रूप से निभाया. 2006 से 2009 तक सलवा जुडूम के खिलाफ जनता और मिलिशिया का प्रतिरोध बढ़ाने में उनका योगदान रहा. सलवा जुडूम के गुंडों, नेताओं, एसपीओं और पुलिस बलों को खत्म करने में उनकी अहम भूमिका रही. सलवा जुडूम गुंडों और जुडूम नेताओं में दहशत फैलाने वाले इंजरम और एर्राबोर के सलवा जुडूम शिविरों पर किए गए हमलों में वे सक्रिय भागीदार थे.

अगस्त, 2009 में जब बटालियन–1 का गठन हुआ था, तब कामरेड सीता उसके सदस्य बने थे. शहादत तक वे वहीं कार्यरत थे. बटालियन (बीएन) में करीबन आठ वर्ष तक के अपने कार्यकाल में पार्टी सदस्य, प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य और प्लाटून डिप्टी कमांडर की हैसियत से उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई. बीएन द्वारा किये गये सैनिक कार्रवाईयों में उनका सक्रिय योगदान रहा. सितंबर, 2009 में सिंगनमड़गू में 6 जन कोबरा कमांडो को खत्म करने में, 2010 के ऐतिहासिक मुकरम हमले में, 2011 के भेज्जी फ्रंटल अटैक में और चिंतलनार के नजदीक तिम्मापुरम के पास एसपीओ और एसटीएफ गुंडों को खत्म करने में, 2012–13 में की गई कई छोटी–छोटी सैनिक कार्रवाइयों में, 2014–2017 के बीच में की गई कस्सलपाड़, पिड़मेल, रामारम, करिगुंडम, डोंगल गुब्बाल, दुग्गमरका, कोत्ताचेरू, बुरकापाल, तोंडामरका जैसी छोटी व बड़ी कार्रवाईयों में न सिर्फ एक सदस्य बल्कि एक सक्षम कमांडर के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका अदा की. इस तरह सैनिक कर्यवाईयों में अनुभव हासिल करते हुए बीएन में वे एक जांबाज योद्धा के तौर पर उभरे थे. जब वे दुश्मन के हाथ लग गए थे, पुलिस की कई क्रूर यातनाओं के बावजूद पार्टी की गोपनीयता

को बचाते हुए उन्होंने जनता के लिए अपनी अनमोल जान की कुरबानी दी.

कामरेड सोड़ी सीता अमर रहें!

कामरेड सोड़ी लखमा

कामरेड लखमा सुकमा जिला, कोंटा तहसील के चिंतागुफा गांव में पैदा हुए थे. गांव में रहते समय उन्होंने मिलिशिया में काम किया था. मिलिशिया सदस्य के तौर पर वे पुलिस बलों के खात्मे और पुलिस की आपूर्ति की जब्ती आदि कई छोटी–छोटी कार्यवाहियों में शामिल हुए थे. दिसंबर, 2014 में वे पेशेवर क्रांतिकारी बने थे. भर्ति होने के तुरंत बाद डिविजन पार्टी कमेटी ने उन्हें बीएन में सदस्य के रूप में भेजा था. शहादत तक वे वहीं पर कार्यरत थे. बीएन के रोजमर्रा कार्यक्रमों और सैनिक प्रशिक्षण में वे अनुशासन के साथ शामिल होते थे. उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निभाने के लिए वे कोशिश करते थे. दो वर्ष के उनके कार्यकाल में बीएन द्वारा की गई कई कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी थी. पिड़मेल, दुग्गमरका, भेज्जी, बुरकापाल और तोंडामरका कार्रवाईयों में शामिल होकर उन्होंने अपनी भूमिका निभायी. जब कामरेड सीता के साथ वे दुश्मन के हाथ लग गए थे, दुश्मन द्वारा दी गई कई यातनाओं के बावजूद पार्टी की गोपनीयता को बचाते हुए उन्होंने अपने प्राणों को कुरबान किया.

कामरेड सोड़ी लखमा अमर रहें!

पद्दाम बुदरी (अनिता)

7 नवंबर, 2017 को माड़ डिविजन के कुतुल क्षेत्र के दुरवेडा गांव के गोटुल में ठहरे गुरिल्ला कामरेडों को घेर कर पुलिस बलों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में गोली लगने से डिविजन स्टाफ की सदस्या कामरेड अनिता की शहादत हुई थी.

माड़ डिविजन, इंद्रावती एरिया के आलवेड़ा गांव में कामरेड अनिता पैदा हुई थी. कामरेड अनिता के पिता का नाम मासो और माता का नाम चैते है. मां–बाप की पांच संतानों में वह बड़ी थीं. घर में उनका नाम बुदरी था. कामरेड बुदरी अपने पीछे मां–पिता, दो छोटी बहनों और दो छोटे भाईयों को छोड़ गई थीं. कामरेड अनिता का परिवार दंतेवाडा जिले से जमीन तलाशते हुए आलवेडा आया हुआ था. उनका परिवार प्रारंभ से ही क्रांतिकारी आदोलन का साथ देता था. क्रांतिकारी परिवार में पलने–बढ़ने की वजह से छोटी उम्र में ही कामरेड अनिता ने क्रांति की राह में कदम रखा था. बाल संगठन में भर्ती होकर उसकी कमांडर बनीं. वह सीएनएम क्रियाकलापों में बढ़–चढ़ कर शामिल होती थीं. जनताना सरकार की शाला में भर्ती होकर दो साल तक शिक्षा हासिल की. उसके बाद पीएलजीए में भर्ती होने के अपने मजबूत इरादे को उन्होंने स्थानीय पार्टी के सामने रखा था. हालांकि योग्य उम्र न होने के कारण उन्हें भर्ती करने से पार्टी ने इनकार कर दिया. लेकिन गुरिल्ला बनने के अपने मजबूत जज्बे से वह थोड़ा भी पीछे नहीं हटी. घर–बार छोड़ कर गुरिल्ला दस्ते के साथ ही घूमने लगीं. आखिरकार उनकी क्रांतिकारी जिद, चेतना व अनुशासन को देख कर जनवरी, 2014 में पार्टी ने उनकी भर्ती का अनुमोदन किया.

कामरेड अनिता ने एक पारंपरिक रीति–रिवाज को भी तोड़ दिया. आदिवासी रीति–रिवाज के अनुसार बचपन में ही उनके मामा के बेटे के साथ उनकी शादी तय हुई थी. लेकिन बड़ी होने के बाद उक्त शादी करने से अनिता ने इनकार कर दिया.

भर्ती होने के बाद 7–8 महीनें तक कामरेड अनिता ने ओरछा स्थानीय गुरिल्ला दस्ते में काम किया. उसके बाद उनका तबादला डिविजन स्टाफ में हुआ था, जहां काम करते हुए उन्होंने शहादत को पाया. वह एक फुरतीली कामरेड थीं. लगभग दो साल तक कठोर परिश्रम के साथ उन्होंने डिविजन स्टाफ में अपना अहम योगदान दिया. काम कितने ही कठिन हो, वह हंसी–खुशी से किया करती थीं. काम के अलावा पढ़ाई पर भी वह खूब ध्यान देती थीं. कोई भी चीज सीखने के लिए वह हर पल तत्पर रहती थीं, पहलकदमी दिखाती थीं. जनता के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हुआ करता था.

हंसमुख अनिता ने अपने अनुशासन, मेहनत, मिलनसार स्वभाव से न सिर्फ पूरे डिविजन बल्कि डिविजन के बाहर कार्यरत कितने ही कामरेडों पर अमिट छाप छोड़ी थी.

कामरेड अनिता की शहादत से उनके मां–बाप और परिजनों को दुख तो, जरूर पहुंचा. लेकिन उन्होंने यह गर्व भी महसूस किया कि उनकी बेटी जनता के लिए लड़कर अपनी जान की कुरबानी दी. परिजन और गांव वाले नारायणपुर जाकर कामरेड अनिता की लाश लाए. जनता और पीएलजीए ने मिलकर कामरेड अनिता का अंतिम संस्कार किया. बाद में स्मारक सभा का आयोजन हुआ. इस मौके पर कामरेड अनिता के आदर्शों को ऊंचा उठाते हुए उनके आशयों को आग बढ़ाने का संकल्प लिया गया.

कामरेड अनिता अमर रहें!

इरपानार शहीदों को लाल सलाम!

7 नवंबर, 2017 को माड़ डिविजन, नेलनार एरिया के इरपानार गांव के पास पुलिस द्वारा किए गए हमले में डीके सीएनएम सदस्या कामरेड ज्योति, डिविजन सीएनएम सदस्याएं कामरेड रैनी और कामरेड सुंदरी, कामरेड संतीला (गार्ड) के साथ–साथ इरपानार (वाला) गांव के जन नेता कामरेड फग्नु जो मुठभेड़ के दौरान घायल रैनी को नदी पार करा रहे थे, शहीद हो गए.

कामरेड रुकनी (ज्योति)

लगभग 24 वर्ष पहले कामरेड ज्योति का जन्म आरकेबी डिविजन के आमुकोड्डूर गांव में हुआ था. छोटी उम्र में ही वह क्रांति के प्रति आकर्षित हुई थीं. डिविजन की सीएनएम टीम के साथ घूमते हुए कला के माध्यम से गांव–गांव में क्रांतिकारी राजनीति को फैलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया. 2008 में वह पेशेवर क्रांतिकारी बन गयीं. उसके बाद भी उनका योगदान सीएनएम में ही जारी रहा. 2011 में जब जोन बाल सीएनएम का गठन हुआ, कामरेड ज्योति का चयन उसमें हुआ था. उसमें काम करते हुए उन्होंने न सिर्फ दंडकारण्य में जारी जनयुद्ध का दंडकारण्य के बाहर की विशाल जनता में प्रचार करने में बल्कि जनता की मदद जुटाने में अपना योगदान दिया. ऐसी कोशिशों में 2012 में जब वह अपनी टीम के साथ कला प्रदर्शन देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद गयी थीं, सभी टीम के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हुई. वहां के जन संगठनों एवं जनवादी वकीलों के प्रयासों के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में सभी टीम की रिहाई हुई. बाद में चूंकि बाल सीएनएम का विलय जोन सीएनएम में हुआ था, इसलिए कामरेड ज्योति जोन सीएनएम सदस्या बनीं. शहादत तक उनका योगदान वहां जारी रहा.

2009 में कामरेड ज्योति का दाखिला बीसीटीएस में हुआ था, जहां ध्यान देकर उन्होंने एकडेमिक व राजनीतिक शिक्षा को हासिल किया. उन्होंने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया. सीएनएम टीम में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर उनका अहम योगदान रहा.

दुबली, पतली, गोरी, छोटे कद व मासूम चेहरा वाली कामरेड ज्योति अपनी उम्र से छोटी लगती थीं. शारीरक रूप से कमजोर होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ती थी. अनुसाशन का सटीक पालन करते हुए गैर सर्वहारा रुझानों से बचते हुए कामरेड ज्योति सभी कामरेडों की चहेती बन गयीं.

कामरेड ज्योति अमर रहें!

कामरेड दुरवा लच्चिमी (रैनी)

कामरेड दुरवा लच्चिमी का जन्म 24 वर्ष पहले माड़ डिविजन, इंद्रावती एरिया के डोंड्रवेड़ा गांव में हुआ था. कामरेड रैनी के पिता का निधन हुआ था. मां और दो भाई हैं. कामरेड रैनी का परिवार क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है. उनके भाई 2012 तक जनताना सरकार के अध्यक्ष रहे.

कामरेड रैनी ने पांचवीं तक पढ़ाई की. बाद में उन्होंने बाल सीएनएम में भर्ती होकर क्रांति में अपना योगदान देना शुरू किया. जवान होने के बाद भी उनका योगदान सीएनएम में ही जारी रहा. वह एक अच्छी कलाकारिणी थीं. न सिर्फ अपने पंचायत बल्कि अन्य पंचायतों के गांवों में भी घूमते हुए सांस्कृतिक क्रियाकलापों के जरिए जनता में संघर्ष चेतना बढ़ाने की कोशिश की. उनकी क्रांतिकारी चेतना व योगदान को देख कर उन्हें पार्टी सदस्यता दी गई.

हालांकि कामरेड रैनी की सांगठनिक सक्रियता को गांव के मुखिया सहन न कर पाये. इसलिए उन्होंने कामरेड रैनी की मां पर उनकी बेटी की शादी करने के लिए बेहद दबाव डाला था. नतीजतन इत्तपारा के एक शख्स के साथ कामरेड रैनी की शादी हुई थी. शादी के बाद भी कामरेड रैनी सीएनएम में काम करती रहीं. लेकिन पति और ससुराल ने इसका विरोध किया. क्रांतिकारी रास्ता छोड़ने के लिए उन्होंने कामरेड रैनी पर बहुत ही दबाव डाला. लेकिन कामरेड रैनी क्रांति के रास्ते पर डटी रहीं. जिसके चलते उनका वैवाहिक जीवन में खलबली उठी. इसी वजह से डेढ़ वर्ष के बाद उनका वैवाहिक बंधन टूट गया. कामरेड रैनी फिर माइके आ गईं. और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिवधियां जारी रखी.

एक वर्ष के बाद, जनवरी, 2015 में वह पेशेवर क्रांतिकारी बनीं. कला क्षेत्र में उनकी क्षमता व दिलचस्पी के मुताबिक उन्हें एरिया सीएनएम में रखा गया. कुछ महीने वहां काम करने के बाद उनका तबादला डिविजन सीएनएम में हुआ था. वहीं काम करते हुए उनकी शहादत हुई.

बाल सीएनएम से लेकर कामरेड रैनी की पूरी क्रांतिकारी जिंदगी सांस्कृतिक क्षेत्र में ही गुजरी. एक कलाकारिणी के तौर पर उन्होंने क्रांति की अनमोल सेवा की. कोई भी कला रूप को न सिर्फ सीखने में बल्कि अन्य कामरेडों को सिखाने में भी वह माहिर थीं. कोई भी गाना व प्रदर्शन के पहले वह उसका आकर्षणीय परिचय देती थीं. गाना व अभिनय के अलावा वह गीत लिखती थीं, नाटक बनाती थीं और निर्देशन भी करती थीं. वह एक अच्छी वक्ता भी थीं.

2016 में डिविजन में हुई विशेष महिला बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने अपना बाल कटवा कर पितृसत्ता विरोधी चेतना को प्रदर्शित किया. न सिर्फ माड़

डिविजन बल्कि कला क्षेत्र ने एक विकासशील कलाकारिणी को खो दिया.

कामरेड रैनी अमर रहें!

कामरेड सुंदरी कुंजम

कामरेड सुंदरी कुंजम का जन्म 18 वर्ष पहले माड़ डिविजन, इंद्रावति एरिया के उरुमगुंडा गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था. बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया, तो अकेली मां ने ही खूब मेहनत करके अपनी तीन बेटियों का पालन–पोषण किया. उनका परिवार क्रांति की मदद देता था. उनकी मां केएएमएस में काम करती थीं. कुछ वक्त बीतने के बाद उनकी मां ने फिर शादी कर ली. बाद में मां की भी मौत हो गई. इसलिए कामरेड सुंदरी अपनी चाची–चाचा के घर में बड़ी हो गईं.

2013 में वह मिलिशिया में भर्ती होकर सक्रिय कार्यकर्ता बनीं. दो–तीन बार दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ों में भी वे शामिल हुई थीं. पुलिस ने मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार करके, खूब यातनाएं दी. उनके गांव के जनताना सरकार अध्यक्ष को भी गिरफ्तार करके, खूब यातनाएं देकर जबर्दस्ती आत्मसमर्पण कराया. कामरेड सुंदरी को भी एसपीओ द्वारा धमकियां दी गईं. इसके बावजूद वह हिम्मत के साथ मिलिशिया में डटी रहीं. मिलिशिया में उनकी सक्रिय भागीदारी देख कर उन्हें डिप्युटी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई. 2016 तक उन्होंने मिलिशिया में अपना योगदान दिया.

कुछ लोगों ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. लेकिन शादी करके साधारण जिंदगी बिताने के लिए वह राजी नहीं हो सकी. वह अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहती थीं. इसीलिए जनवरी, 2017 में वह पेशेवर क्रांतिकारी बन गईं. भर्ती होने के तुरंत बाद वह नेलनार एरिया में भेजी गईं. वहीं काम करते हुए उन्होंने शहादत को पाया.

कामरेड सुंदरी अमर रहें!

कामरेड पदाम कोपे (संतीला)

कामरेड संतीला माड़ डिविजन, इंद्रावती एरिया के पल्ली गांव में 20 वर्ष पहले जन्मी थीं. उनके पूर्वज दंतेवाडा जिले के बोदेम गांव से आजीविका तलाशते हुए इस गांव में आये थे. कामरेड संतीला मां–बाप, दो बहनों और एक भाई को अपने पीछे छोड़ गईं.

इस गांव में जमींदार विरोधी आंदोलन संचालित होने की वजह से गांव में मजबूत क्रांतिकारी माहौल व्याप्त है. कामरेड संतीला के परिजन क्रांति के हमदर्द हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप में ही कामरेड संतीला बचपन में ही क्रांति के प्रति आकर्षित हो गईं. वह पंचायत की सीएनएम कमेटी में शामिल होकर सांस्कृतिक क्रियाकलापों के जरिए जनता में क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करती थीं. न सिर्फ उनके गांव बल्कि अन्य गांवों में भी जाकर वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती थीं. गांव के युवाओं को सास्कृतिक प्रशिक्षण भी देती थीं. जब सीएनएम कार्यक्रमों से अवकाश मिलता था, तब मिलिशिया के साथ रहते हुए गांव की सुरक्षा में शामिल होती थीं. क्रांति पर मजबूत विश्वास रखनेवाले उनके मां–बाप भी अपनी बेटी का साथ देते थे. 2017 में उन्होंने पेशेवर क्रांतिकारी बन कर घर–बार छोड़ दिया. गांव छोड़ते समय उन्होंने न सिर्फ मां–बाप को बता कर उनका अनुमोदन हासिल किया बल्कि अपनी छोटी बहन को मिलिशिया में भर्ती कराया. पीएलजीए में भर्ती होने के तुरंत बाद उन्हें डीवीसी सदस्या की गार्ड जिम्मेदारी दी गई. हालांकि इस जिम्मेदारी को पूरी करने के पहले ही उनकी शहादत हुई.

कामरेड संतीला अमर रहें!

मंगतू कुहड़ामी (फगनू)

कामरेड मंगतू कुहड़ामी (29) का जन्म नारायणपुर जिला, टाकराम गांव में हुआ था. मां पायके और पिता पंडरू की पांच संतानों में कामरेड मंगतू चौथे थे. गरीबी के कारण उनका परिवार नारायणपुर जिला, ओरछा ब्लॉक के वाला गांव में जाकर बस गया था. हालांकि वाला में उन्हें जमीन मिली, लेकिन बैल न होने के कारण उनका परिवार अभी भी गरीबी से जूझ रहा है.

कामरेड मंगतू ने तीसरी तक पढ़ाई की. गरीबी के कारण 1998 में पढ़ाई छोड़ कर घर की हालत सुधारने में वे मां–बाप की मदद करने में लग गए थे. उसी समय अपने गांव में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति वे आकर्षित हुए थे.

2003 में वे जीआरडी में भर्ती हुए थे. क्रांतिकारी क्रियाकलापों में वे जोर–शोर से भाग लेते थे. उनकी क्रांतिकारी चेतना, क्षमता व पहलकदमी के अनुरूप उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ता गया. 2004 में उन्हें जीआरडी के डिप्टी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई. 2005 में

जीआरडी कमांडर बन कर उन्होंने गांव की सुरक्षा और उत्पादन के क्रियाकलापों में अपने दस्ते को सक्रिय रूप में शामिल करने में अहम योगदान दिया. 2006 में जब मिलिशिया पलटन का गठन हुआ, कामरेड फगनू का चयन उसके डिप्टी कमांडर के रूप में हुआ था. कुछ वक्त के बाद वे कमांडर बने थे. अपनी जिम्मेदारी सटीक निभाने के लिए उन्होंने दिन–रात मेहनत की. पलटन सदस्यों को प्रशिक्षण देने में वे ध्यान देते थे.

2008 में किए गए भट्टुम एंबुश में उनका पलटन का योगदान रहा. नवंबर 2008 में विधान सभा चुनाव के मौके पर किए गए एंबुश के दौरान उन्हें स्काउट कि जिम्मेदारी सौंपी गई. उस जिम्मेदारी के अनुसार जब वे फटाके विस्फोट कर रहे थे, फटाके उनके हाथों में ही विस्फोट हुए. जिससे उनका चेहरा जल गया. उनकी आंखों तक तकलीफ पहुंची. उस वक्त दुश्मन के हाथों में पड़ने से वे बाल–बाल बच गए थे. उसी वर्ष गोला–बारूद ढुलाई में उनकी पलटन एवं जनता को शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भगीदारी रही. अपने आस–पास के गांवों में क्रांतिकारी जरूरतों के अनुसार जब भी गुरिल्ला कैंपों का संचालन होता था, वे न सिर्फ सुरक्षा बल्कि अन्य जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी पलटन को लेकर जरूर हाजिर होते थे.

2009 में नारायणपुर साप्ताहिक बाजार से कामरेड फगनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पांच वर्ष उनकी जिंदगी जेल में गुजरी थी. 2014 आखिरी में उनकी रिहाई हुई. उनकी गिरफ्तारी के बाद तितर–बितर हुई मिलिशिया के पुनर्गठन के लिए उन्होंने फिर कोशिश की. युवाओं को एकजुट करके उन्हें उत्पादन काम में शामिल किया. एक हफ्ता काम करने के बाद काम की जगह में ही पूरे मिलिशिया कामरेडों के साथ कामरेड फगनू भी पुलिस द्वारा पकड़े गए थे. पुलिस बलों ने उनके साथ और एक बार बेरहमी से मार–पीट की थी. कुछ दिन के बाद चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां और दी गयी यातनाएं कामरेड फगनू के क्रांतिकारी दृढ़संकल्प को कमजोर करने में नाकाम रहीं. वे क्रांतिकारी गतिविधियों में लगातार आगे बढ़ते रहे. उन्होंने अपने परिवार को भी क्रांति के पक्ष में बनाए रखने के लिए चेतनापूर्वक प्रयास किए.

उनकी राजनीतिक चेतना और पहलकदमी को देख कर अक्तूबर 2017 में उन्हें डीएकेएमएस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. इसके कुछ ही दिनों में उन्होंने शहादत को पाया.

मुठभेड़ के वक्त वे निहत्थे थे. अपने कानूनों के मुताबिक पुलिस बल उन्हें पकड सकते थे. पकड़कर कोर्ट में हाजिर करना चाहिए था. लेकिन अपने ही कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बेरहमी से हत्या करने के अपने सर्व साधारण व्यवहार के अनुरूप ही खून के प्यासे पुलिस बलों ने कामरेड फगणु की निर्मम हत्या की.

ग्रामीण जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, नारायणपुर जाकर पुलिस से लड़–भिड़ कर उनकी लाश लायी. बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई जनता ने शहीदों के आशयों को आगे बढ़ाने की शपथ लेते हुए उनकी अंतिम विदाई दी.

कामरेड फगनू अमर रहें! ★

क्रांतिकारी दिवस

राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस

पूर्व बस्तर डिविजन

13 सितंबर – जतिन दास के शहादत दिवस को राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में मनाने के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूर्व बस्तर डिविजन में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. इस अवसर पर जेल बंदियों के परिजनों से मिलकर उनके सुख–दुख को साझा किया गया. और उन्हें ढाढ़स बंधायी गयी. जेल में बंद अपनों से मुलाकात के लिए उन्हें भेजा गया. जनताना सरकार और जनता द्वारा पहले से जारी मदद को आगे बढ़ाने का आश्वासन उन्हें दिया गया. इस अवसर पर डिविजनल कमेटी द्वारा छापे 1500 पोस्टरों को गांव–गांव में चिपकाया गया. केंद्रीय कमेटी द्वारा पुस्तिका के रूप में जारी किए गए संदेश को छात्र, बेरोजगार, नवजवान और बुद्धिजीवियों तक पहुंचाया गया.

माड़ डिविजन

माड़ डिविजन के कुतुल इलाके में डीएकेएमएस, केएएमएस और सीएनएम द्वारा पोस्टर व बैनरों के साथ व्यापक रूप में प्रचार किया गया. एरिया के अलग–अलग जगहों पर पंचायत स्तर की कई सभाओं का आयोजन हुआ. एक जगह में एक बड़ी सभा का संचालन हुआ. इस मौके पर रैली निकाली गई. और झंडा फहराया गया. वक्ताओं ने अपने भाषणों द्वारा न सिर्फ सरकारी दमन, क्रूर काननों, लंबी न्याय प्रक्रिया, कठिन सजाओं, जेलों में मौजूद अमानवीय परिस्थितियों बल्कि राजनीतिक जेलबंदियों द्वारा किए जा रहे जुझारू आंदोलनों के बारे में सभा में शिरकत करने वाले लोगों को अवगत कराया. इस दमन के विरोध में संघर्ष करने और जेल बंदियों की हर संभव मदद देने का आह्वान किया गया. इस सभा में लगभग 600 लोग जिनमें से 220 महिलाएं थीं, मौजूद रहे. ★

तीन गांवों की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंचीं कलेक्टोरेट, कहा–न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा

मुठभेड़ के बाद जवानों ने डटकर पी शराब फिर डंडों से महिलाओं और बच्चों को पीटा

बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली में गुरुवार को एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर करने के बाद इलाके में सर्चिंग कर रहे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर सावनार, कोरचोली, तोड़का की महिलाओं ने मारपीट का आरोप लगाया है. जिला मुख्यालय पहुंचकर पीड़ित महिलाएं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रम मंडावी के साथ न्याय की गुहार लगाते कलेक्टोरेट पहुंची थीं. पीड़ित महिलाओं ने जवानों पर पहली बार यह चौंकाने वाला आरोप भी लगाया है कि मुठभेड़ के बाद गश्त के दौरान जवानों ने पहले तो गांव से ही शराब लेकर जमकर शराबखोरी की. उसके बाद नशे की हालत में ही महिलाओं को लाठी और डंडों से बेदम पिटाई की. एसपी एमआर अहिरे ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर के न मिलने पर भोपलपट्नम के एसडीएम टीसी बंजारे को उन्होंने ज्ञापन सौंपा. महिलाओं ने कहा कि जब तक इस मामले में आरोपी जवानों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वे अपने बच्चों के साथ जिला मुख्यालय में ही डटी रहेंगी. पीड़ितों के मुताबिक जवानों ने प्रभावित तीनों गांवों में महिलाओं के अलावा बच्चों की पिटाई करने के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश भी की.

कोरचोली से पहुंची मंगली पोटाम व लक्ष्मी पोटाम ने बताया कि गुरुवार सुबह सावनार के नजदीक खेतों में गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ने पर गांव की महिलाएं दूसरे खेतों की तरफ भागीं. गांव के पुरुष खेतों के आसपास मिंजाई कर रहे थे और बच्चे मवेशी चराने गए थे. गोली की आवाज सुनकर अनहोनी की आशंका से महिलाएं खेतों की तरफ दौड़ी जा रही थीं. इनके अलावा कोरचोली और तोड़का गांव की महिलाएं भी खेतों की ओर आ रही थीं. इसी दौरान एक स्थान पर सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया और ज्यादती की.

भाजपा राज में पुलिस–प्रशासन तानाशाहः

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विक्रम मंडावी ने कहा कि कांग्रेस की एक टीम शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगी. मंडावी ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा के इस राज में पुलिस और अधिकारी अपना आतंक मचा रहे हैं.

जवानों को महिलाएं पहचानती हैं

महिलाओं ने बताया कि चार जवान जो नशे की हालत में थे, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की. सबको एक स्थान पर एकत्र कर नक्सलियों के बारे में पूछताछ शुरू की. थोड़ी देर बाद जवान उन्हें मारने लगे. महिलाओं ने इसका विरोध किया तो वे और भी उग्र हो गए. जवानों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा. कोरचोली की सुक्की ने बताया कि मारपीट में उसकी 6 साल की बच्ची लहूलुहान हो गई. महिलाओं ने दावा किया है कि मारपीट करने वाले कुछ जवानों को वे चेहरों से जानती हैं. उनमें एक पूर्व एसपीओ भी है जो गंगालूर इलाके का रहने वाला है. ★

(23 दिसंबर के दैनिक भास्कर से साभार)

फोर्स पर गांव से उठा ले जाने का आरोप...

चिंतागुफा के दो ग्रामीण एक माह से लापता, न्यायालय में दी अर्जी

भेज गया है जेल

इधर छपने वाले दैनिक समाचार पत्रों की कतरन् बस्तर की हालत को काफी कुछ बयां करती हैं. सरकार द्वारा कई तरह के रोक लगा देने के बावजूद बस्तर में लगातार बढ़ रहे दमन से संबंधित कई समाचारों को आएदिन मीड़िया में कुछ न कुछ जगह मिल रही है. गांवों पर हमलों, मुठभेड़ों, अत्याचारों, गिरफ्तारियों, यातनाओं के अलावा हाल के दिनों में मिस्सिंग मामलें भी बढ़ रहे हैं.

चिंतागुफा के दो ग्रामीण एक माह से लापता, न्यायालय में दी अर्जी

यह है 3 नवंबर के दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका का एक शीर्षक. इसके अनुसार सुकमा जिले के चिंतागुफा से एक माह पहले आठ लोगों – करटम हिड़मा, करटम पापाराव, करटम दूला, करटम राजा, पद्दम हिडमा, कोवासी कन्ना, करटम भीमा और तेलम हिडमा को पुलिस उठा ले गई. उन्हें दो दिन भेज्जी थाने में रखा गया. इसके बाद छह लोगों को छोड़ दिया गया. लेकिन दो लोगों – कोसी के बेटे करटम भीमा, सीता के पति तेलम हिडमा को नहीं छोड़ा गया. न सिर्फ इन दोनों के परिजन बल्कि सभी ग्रामीण पिछले एक माह से थाना और कैंप का चक्कर काट रहे हैं. लेकिन उनके बारे में कोई अधिकारी द्वारा कुछ नहीं बताया गया.

आप नेत्री सोनी सोढ़ी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में कोसी और सीता के पक्ष में आवेदन लगवाया.

पामेड़ क्षेत्र की आठ महिलाओं समेत 11 ग्रामीण 12 दिस से लापता

यह है 28 नवंबर के दैनिक समाचार पत्र, नई दुनिया का शीर्षक. इसके अनुसार पामेड़ थाना क्षेत्र के बोमगुड़ा गांव की आठ महिलाएं और तीन पुरुष समेत कुल 11 ग्रामीण पिछले 12 दिनों से लापता हैं. इनमें बोमगुड़ा निवासी हेमला हिड़मे, कड़ती दूले, मड़कम नंदे, मड़कम हिड़मे, मड़कम लक्खे, मड़कम हुंगी, ताती हुंगी, हेमला हिड़मे, माड़वी अंदा, हेमला देवा व हेमला हिड़मा शामिल हैं. इसके पहले 12 नवंबर को जगरगुंडा पुलिस के द्वारा आठ जन – मीनागट्टा निवासी मड़कम सोमा, बेट्टी सुक्का, मड़कम बंडी, बोमगुड़ा निवासी माड़वी मंगल, मड़कम सोमाल, मड़कम जोगा पिता हिड़मा, मड़कम जोगा पिता मंगलू व हेमला सोला को गिरफ्तार किया गया. इसकी सूचना पामेड़ थाने से दी गई. उन्हें मिलने के लिए उनके 11 परिजन जगरगुंडा के लिए रवाना हो गए थे जिनका बाद में किसी प्रकार का सुराग नहीं मिल पाया.

लापता ग्रामीणों की खोज–खबर के लिए जब अन्य ग्रामीण जगरगुंडा थाने पहुंचे, तो पुलिस ने कहा कि यहां कोई भी ग्रामीण नहीं आया है.

कानून के मुताबिक अगर पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी होती है, तो 24 घंटों के भीतर ही उन्हें अदालत

पामेड़ क्षेत्र की आठ महिलाओं समेत 11 ग्रामीण 12 दिन से लापता

में पेश करना चाहिए. लेकिन देश में खासकर संघर्षत इलाकों में संविधान, कानून, अदालत, न्याय जैसे शब्द निरर्थक साबित हो गए हैं.

दंडकारण्य इलाके में जारी भीषण दमन के विरोध में जनवादी–प्रगतिशील ताकतों और संगठनों को आवाज उठानी चाहिए.

★

जिनुगू नरसिंहा रेड्डी के शर्मनाक गद्दारी और आत्मसमर्पण की निंदा करें!

समझौताहीन संघर्ष और निस्वार्थ त्याग की क्रान्तिकारी परम्परा को ऊंचा उठायें!

सभी तरह के कीचड़ों का सफाया कर क्रान्ति अपने पथ पर आगे बढ़ेगी!

हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य जिनुगू नरसिंहा रेड्डी (जम्पन्ना, राजेश) ने उसकी पत्नी नवता (जया, डिवीजनल कमेटी सदस्य) के साथ 23 दिसम्बर को दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इससे पहले ही उसने सर्वहारा विचारधारा, माओवादी पार्टी, दीर्घकालीन जनयुद्ध, क्रान्तिकारी आंदोलन और उत्पीड़ित जनता की ताकत पर विश्वास खो दिया था. बदलती वस्तुगत परिस्थिति और दुश्मन के तेज होते चौतरफा हमले से उत्पन्न वर्ग संघर्ष के नये और कठिन दौर का मुकाबला करने में विफल होकर उसने भगोड़े का एक निहायती स्वार्थी, घिनौना और कायराना रास्ता अपनाते हुए दुश्मन के सामने घुटने टेक दिये. भारत के सर्वहारा वर्ग, उसके हिरावल पार्टी, भारतीय क्रान्ति तथा देश की मेहनतकश जनता के साहसिक संघर्ष के साथ यह सरासर विश्वासघात है. उस वर्ग दुश्मन, जिसके साथ निस्वार्थ रूप से लड़ते हुए हजारों शहीदों ने अपनी जान न्योछावर की थी, को आज नरसिंहा रेड्डी बेशर्मी से गले लगा रहा है. इसी के साथ क्रान्तिकारी आंदोलन में उसके तीन दशक के राजनीतिक जीवन का भी शर्मनाक अंत हुआ है. हमारी केन्द्रीय कमेटी नरसिंहा रेड्डी की गद्दारी और आत्मसमर्पण की कड़ी शब्दों में निंदा करती है. पार्टी कतारों, पूरे क्रान्तिकारी शिविर, व्यापक संघर्षरत जनता और भारतीय क्रान्ति के सभी मित्रों से हम अपील करते हैं कि ऐसे गद्दारों और उनके घिनौने आत्मसमर्पण की राह को खारिज करें. नरसिंह रेड्डी के पतन से जरा भी विचलित हुए बिना हमारी केन्द्रीय कमेटी पार्टी की तात्कालिक और अंतिम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ग संघर्ष के लाल परचम को दृढ़ता से आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराती है.

1980 के दशक के शुरूआती दिनों में नरसिंहा रेड्डी हैदराबाद शहर के एक फेक्टरी में टेकनिशियन के रूप में नौकरी करते समय क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हुआ था. कुछ समय के बाद वह एक पेशेवर क्रान्तिकारी बन गया और पार्टी ने उसे वरंगल जिले के एटूरुनागारम के जंगली इलाके में एक गुरिल्ला दस्ते के सदस्य के रूप में काम करने के लिए भेजा. 1986 और 1995 के बीच वह एक दस्ता कमांडर, एरिया कमेटी सदस्य, जिला कमेटी सदस्य और जिला कमेटी सचिव के रूप में विकसित हुआ. उत्तरी तेलंगाना में आधार इलाका निर्माण के दृष्टिकोण से गुरिल्ला युद्ध को विकसित करने की योजना के तहत 1995 में उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी (एनटीएसजेडसी) का गठन किया गया. उसी साल हुए एनटी स्पेशल जोन के पहले अधिवेशन में उसे इस कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया. 2000 में वह एनटीएसजेडसी का सचिव बना और 2007 तक इसी पद पर कार्यरत रहा. 2001 में वह केंद्रीय कमेटी में चुना गया और 2001 से 2007 के बीच एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में उसने उत्तर तेलंगाना में काम किया. 2007 में उसे केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) में को–ऑप्ट कर लिया गया और इसके बाद उसने उत्तर तेलंगाना सहित मध्य रीजियन के अन्य भागों में भी काम किया. 2011 में उसका ओडिशा तबादला किया गया जहां वह 2016 के अंत तक कार्यरत रहा. पिछले एक साल से वह वैचारिक और राजनीतिक ढुलमुलपन में डुबा हुआ था और आखिरकार नवम्बर 2017 में उसने संबंधित केन्द्रीय कमेटी सदस्यों को अपने आत्मसम्पर्ण करने के निर्णय के बारे में बताया.

यह सच है कि नरसिंहा रेड्डी ने तीन दशकों से भी ज्यादा के एक सापेक्षिक रूप से लम्बे समय तक क्रान्तिकारी आंदोलन में भाग लिया, पार्टी की सर्वोच्च नेतृत्वकारी इकाई केन्द्रीय कमेटी के सदस्य बनने लायक राजनीतिक रूप से विकसित हुआ, और इस क्रम में आंदोलन में योगदान भी दिया. लेकिन दूसरी तरफ, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वह व्यक्तिवाद, नौकरशाही और झूठी प्रतिष्ठा जैसी कई गंभीर कमजोरियों, कमियों और गैर–सर्वहारा रुझानों से घिरा रहा. इस पूरे दौर में उसके साथ गुरिल्ला दस्तों और पार्टी कमेटियों में काम करनेवाले कामरेडों तथा नेतृत्वकारी साथियों ने उसके इन नकारात्मक पहलुओं के खिलाफ लगातार संघर्ष किए. संबंधित कमेटियों ने हर कदम पर उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और उसने भी इनमें से कई आलोचनाओं को एक न एक तरीके से स्वीकार किया. लेकिन उसकी कमजोरियां, कमियां

और सीमितताएं जारी रहीं. खासकर पिछले कुछ सालों में ये नकारात्मक पहलुएं और भी बढ़ गए और पार्टी व आंदोलन की वर्तमान कठिन परिस्थिति में वह आखिरकार उस पर हावी हो गए. दुश्मन से वह इतना भयभीत हो गया था कि वह पार्टी द्वारा दिए गए कार्यभारों को पूरा करने में विफल हो गया. दुश्मन के संभावित हमलों को कारण बताकर उसने महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया जबकि उसी तरह की परिस्थिति में काम करने वाले अन्य कामरेडों को इस तरह की आधारहीन आशंका नहीं थी. उच्चतर कमेटियों के कामरेडों के अलावा उसकी सुरक्षा में जुटे कामरेडों ने भी उसके अकारण डर और हार मानने की भावना की आलोचना की. वर्तमान में जारी दुश्मन के गंभीर हमले की परिस्थिति की यह मांग है कि पार्टी के उच्चतम स्तर के नेतृत्वकारी साथी युद्ध के मैदान में मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रहें तथा पार्टी, पीएलजीए और आंदोलन की रक्षा के अभिन्न अंग के रूप में अपने आपको सुरक्षित रखते हुए काम जारी रखें. सैनिक क्षेत्र सहित क्रान्तिकारी गतिविधि के सभी क्षेत्रों पर यह लागू होता है. लेकिन इसके विपरीत, पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के एक सदस्य के रूप में उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना, तैयारी, साहस, अनुशासन, निस्वार्थ त्याग, आत्मालोचनात्मक रवैया सहित अन्य नेतृत्वकारी गुणों का परिचय देते हुए पार्टी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और कार्यभारों को निभाने में नरसिंहा रेड्डी असफल रहा.

नरसिंहा रेड्डी की कमजोरियां और सीमितताएं एक गंभीर स्तर तक पहुंच गई थी. इसे देखते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी ने उसके काम की समीक्षा की. केन्द्रीय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह गंभीर रूप से मनोगतवाद का शिकार हो गया है, जिसके चलते वह दुश्मन की ताकत का ज्यादा आंकलन कर रहा था जबकि क्रान्तिकारी आंदोलन और जनता की ताकत का कम आंकलन कर रहा था. उसने परिस्थिति को वस्तुगत रूप से देखने की क्षमता खो दिया. पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटी के सदस्य के रूप में परिस्थिति का सही आंकलन नहीं लगा पाने की स्थिति में पहुंचकर उसने गलत सांगठनिक पद्धतियां अपनायी. इसके अलावा उसकी मनोगतवादी और व्यक्तिवादी सोच को पार्टी कमेटियों पर थोपने की उसकी पुरानी कमेजोरी भी जारी रही. जनवादी केन्द्रीयता और सर्वहारा अनुशासन को ताक में रखकर व्यक्तिगत समस्याओं पर संकीर्ण रूप से तर्कहीन वाद–विवाद और बहस सामने लाने की उसकी आदत बन गई. कभी कभी संबंधित पार्टी कमेटी के काम में वह गतिरोध पैदा करता था और अन्य कामरेडों द्वारा आलोचना करने पर कुछ बैठकों का बहिष्कार करने की भी धमकी देता था. उसके संगठनविरोधी आचरण और कामकाज के चलते उसने धीरे–धीरे अपने साथियों का विश्वास खो दिया और अलग–थलग पड़ गया. संबंधित पार्टी कमेटियों के कामरेडों ने एकता–संघर्ष–एकता की बुनियाद पर उसकी गलतियों और कमजोरियों को सुधारने में मदद देने के लक्ष्य से कई बार उसके इन गलत रुझानों की आलोचना की. लेकिन वह अपने नकारात्मक पहलुओं की गंभीरता को पहचान करने में विफल रहा, आत्मालोचनात्मक रवैया अपनाने से बचता रहा और मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की रोशनी में अपने विश्व दृष्टिकोण को बदलने में नाकाम रहा. इसके परिणामस्वरूप न केवल उसका राजनीतिक पतन हुआ बल्कि पार्टी को भी उसने काफी नुकसान पहुंचाया.

इन सभी बातों को नजर में रखकर हमारी केन्द्रीय कमेटी ने इस साल की शुरूआत में नरसिंहा रेड्डी को दो साल के लिए केन्द्रीय कमेटी से निलम्बित करने का निर्णय लिया. उससे अपेक्षा थी कि वह अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करेगा और अपने साथियों की मदद से इनसे उबरने का गंभीर प्रयास करेगा. लेकिन न ही उसने इस निर्णय को सकारात्मक ढंग से ग्रहण किया और न ही कोई आत्मालोचना पेश की. केन्द्रीय कमेटी द्वारा दिए गए राज्य कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी लेने से भी उसने मना कर दिया. केन्द्रीय कमेटी द्वारा उसे निलम्बित करने के निर्णय के बाद नरसिंहा रेड्डी ने अवसरवादी तरीके से पार्टी लाईन के साथ उसके 'मतभेद' का मुद्दा उठाया. उसने दावा किया कि भारत अब अर्ध–औपनिवेशिक व अर्ध–सामंती देश नहीं रह गया है और यह अब एक पूंजीवादी देश में तब्दील हो गया है. इसलिए उसका कहना था कि इन बदलती परिस्थितियों के मुताबिक हमारी पार्टी की लाईन को बदलकर हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सशस्त्र बगावत की लाईन को अपनाना चाहिए. उसने इन बातों को पार्टी के किसी भी मंच पर नहीं उठाया बल्कि व्यक्तिगत तौर पर कुछ साथियों से चर्चा की. साथियों ने उसे इन मतभेदों को सुलझाने के लिए पार्टी मंचों पर उठाने की सलाह दी. लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था और पार्टी से भाग निकला. इससे यह साबित होता है कि उसके तथाकथित राजनीतिक मतभेद उसके वैचारिक–राजनीतिक पतन पर पर्दा डालने के बहाने के अलावा और कुछ नहीं. निम्न पूंजीवादी झूठी–प्रतिष्ठा और स्वार्थी संकीर्णतावाद से ग्रस्त होकर उसने पार्टी के निर्णय को खारिज कर दिया, उसके अंदर मौजूद गैर–सर्वहारा रुझानों के खिलाफ संघर्ष करने से इन्कार कर दिया और अपने आपको एक सच्चे कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी के रूप में ढालने में विफल हो गया. विनम्रता से सिर झुकाकर क्रान्ति और जनता की सेवा करने के बजाय उसने आत्मसमर्पण

कर दुश्मन की दया पर पलने वाले एक गंदे कीड़े का जीवन बिताना ही बेहतर समझा. इस तरह एक क्रान्तिकारी का एक गद्दार और प्रतिक्रान्तिकारी के रूप में परिवर्तन पूरा हो गया.

हर एक क्रान्ति कई उतार–चढ़ावों, करवटों और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरती है. चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करते हुए ही एक सर्वहारा पार्टी अपने आपको मजबूत करती है और क्रान्ति को जीत के मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता हासिल करती है. इस तरह की परिस्थितियों में सभी कम्युनिस्टों के लिए – खासकर गैर–सर्वहारा वर्गों से कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होनेवालों के लिए – यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वे अपने सैद्धांतिक और राजनीतिक समझदारी को गहरी करें, सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण को अपनाकर खुद को इसके मुताबिक ढालें तथा इस पर अडिग रहें. इन चुनौतीपूर्ण समयों में उन्हें जनवादी केन्द्रीयता का और भी दृढ़ता से पालन करना चाहिए, पार्टी की लौह अनुशासन के मुताबिक चलना चाहिए, अपने साथियों तथा जनता के साथ और भी नजदीकी से घुलमिल जाना चाहिए, व्यवहार से सीखकर गलतियों को सुधारना चाहिए, निजी स्वार्थ के खिलाफ लड़ना चाहिए, निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करनी चाहिए और आखिरी दम तक एक वचनबद्ध क्रान्तिकारी के रूप में बने रहने के संघर्ष में पहली कतार पर खड़ा रहना चाहिए. लेकिन इस तरह की परीक्षा की घड़ी में विफल होनेवाले लोग भी हमेशा रहते हैं. इतिहास गवाह है कि अपने स्वार्थ और अस्तित्व को ही सबसे ज्यादा महत्व देनेवाले मुठ्ठीभर लोग खुद को बदलने या त्याग के लिए तैयार नहीं होते हैं. ऐसे लोगों का संकटपूर्ण मोढ़ों में अपने आपको आंदोलन से अलग कर लेना बहुत ही आम बात है. वे क्रान्तिकारी शिविर से भाग खड़े होते हैं और कभी–कभी दुश्मन की सेवा में प्रतिक्रान्तिकारी भी बन जाते हैं. नरसिंहा रेड्डी इसी तरह के एक क्रान्तिकारी का नकारात्मक उदाहरण पेश करता है. अपने कामरेडों और जनता से एकाकार होने से इन्कार कर, अपनी कमजोरियों से संघर्ष करना बंद कर और दुश्मन से आतंकित होकर वे दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और जनता के लिए अपनी उपयोगिता को खुद अपने ही हाथों से खत्म कर देते हैं. वर्ग संघर्ष के क्रम में क्रान्ति इस तरह के लोगों को समय–समय पर रद्दी के रूप में उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है.

इसमें कोई आश्चर्य नहीं अगर ऐसे कुछ लोग दुश्मन का राग आलापते हुए पार्टी, पार्टी नेतृत्व, क्रान्तिकारी आंदोलन और भारतीय क्रान्ति के भविष्य पर कीचड़ उछालने लगे. दुश्मन द्वारा खड़े किए गए ये लोग पार्टी तथा क्रान्ति को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से छद्म 'बुद्धिजीवी', 'पत्रकार', 'सामाजिक कार्यकर्ता' आदि के नये अवतार में प्रकट हो सकते हैं. हमारे कामरेडों, मित्रों और भारतीय क्रान्ति के शुभाकांक्षियों को इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए. उन्हें दुश्मन के दुष्प्रचारतंत्र के एक भाग के रूप में पहचान करते हुए इन गद्दारों के झूठे आरोपों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए.

ऐसे गद्दारों और पाखंडियों के बिल्कुल विपरीत, हर सर्वहारा क्रान्ति समझौताहीन कम्युनिस्ट योद्धाओं को सामने लाती है जो अपने आखिरी सांस तक जनता की सेवा करते हैं. हजारों वीर शहीदों के निस्वार्थ आत्मत्याग की लम्बी और महान परम्परा की वारिस भारतीय क्रान्ति भी इसका अपवाद नहीं है. इन अमर शहीदों में शामिल हैं, हमारे प्यारे महान नेता कामरेडस चारू मजुमदार और कन्हाई चटर्जी, सरोज दत्त, सुशीतल रायचौधरी, अमुल्य सेन, चंद्रशेखर दास, कृष्णमूर्ति, सत्यम, कैलाशम, अप्पु, वर्गीस, विश्वकर्मा, बालन, दिनकर, श्याम, महेश, मुरली, करम सिंह, परिमल सेन, संदे राजमौली, वडकापुर चंद्रमौली, अनुराधा गांधी, पटेल सुधाकर, चेरुकूरी राजकुमार, मल्लोझुला कोटेश्वरलु, रऊफ, सुशील राय, श्रीधर श्रीनिवासन, कुप्पु देवराज, नारायण सन्याल, शाखमूरी अप्पाराव, रामचंदर, श्रीकांत, सुखदेव, पद्मा, ललिता, उर्मिला, रजिता, अजिता, साकेत राजन, मैमुद्दीन, आशीष यादव, प्रसाद, दया, प्रभाकर, मंगतू, शहीदा, रामकृष्ण, यादन्ना, माधव, महेंदर, मस्तान राव, पुलि अंजन्ना, कंचन, शशिधर महतो, जनार्दन, भूमैया–किष्टा गौड और हजारों अन्य शहीद कामरेड्स जो क्रान्ति और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अंत तक अडिग रहे. वे ही जनता के असली वीर और आदर्श हैं जो हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं.

प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के हाथों पलने वाले कुछ गद्दारों और धोखेबाजों का विश्वासघात क्रान्ति को कभी नहीं रोक सकती. ज्यादा से ज्यादा वे कुछ तात्कालिक अवरोध और नुकसान ही पैदा कर सकते हैं. लेकिन इस तरह के परजीवियों को अपनी राह से हटाकर क्रान्ति अपनी मुकाम की ओर अवश्य आगे बढ़ेगी. वीर शहीदों से प्रेरणा लेकर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में देश की करोड़ों–करोड़ उत्पीड़ित जनता नरसिंहा रेड्डी जैसे गद्दारों को उनके आकाओं सहित इतिहास के कूड़ेदान में फेंकते हुए अपनी अंतिम जीत हासिल करेगी.

(अभय)

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

(आखिरी पेज से...)

जारी जनयुद्ध/छापामार युद्ध. इसके साथ–साथ रोजमर्रा की व मौलिक समस्याओं पर जन आंदोलनों को संचालित करना, संयुक्त मोर्चे की गतिविधियों को बढ़ाना, विस्थापन विरोधी आंदोलनों को तेज व व्यापक करना आदि शामिल हैं जो दुश्मन के हमले का मुकाबला करने में बहुत ही मददगार साबित हुए. पार्टी और सैनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों की नेतृत्वकारी शक्तियों को शिक्षित–प्रशिक्षित करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कैंपों को संचालित करने, नई कार्यनीतियों को तय करने के लक्ष्य से सामाजिक शोध करने, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कृषि क्रांतिकारी कार्यक्रमों व क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने के द्वारा बेहतरीन परिणाम हासिल किए गए हैं.

मिशन–2017 को हराने के लिए पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता द्वारा संचालित जनयुद्ध/छापामार युद्ध कार्रवाइयों का ब्यौराः

इस वर्ष दण्डकारण्य में पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बलों के 72 जवानों का सफाया कर 96 पुलिस वालों को घायल किया गया है. दुश्मन के पास से 21 एके–47 रायफलों सहित 35 आधुनिक हथियार, लगभग 3,500 कारतूस जब्त की गयी. कई जन दुश्मनों और दुश्मन के दलालों का सफाया किया गया. विभिन्न दलाल कार्पोरेट वर्गों की परियोजनाओं को रोकने के लिए कई जगहों पर रोड, पुल–पुलियाओं, मोबाइल टॉवर, रेल लाइन को ध्वस्त किया गया. गाड़ियों व इमारती लकड़ी को जला दिया गया.

डीके में संचालित जवाबी प्रत्याक्रमण अभियानों (टीसीओसी) और प्रतिरोध कार्रवाइयों के तहत चार बड़ी कार्रवाइयां – कोत्ताचेरुवु, बुरकापाल, कारमपल्ली, तोंडामरका हुई हैं. इनके साथ–साथ कई छोटी व मझौली कार्रवाइयां हुई. इन कार्रवाइयों खासकर बुरकापाल एम्बुश ने समूचे देश के क्रांतिकारी शिविर को ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतिकारी शिविर में नयी उमंग व विश्वास बढ़ाया. इसी तरह दुश्मन के बलों के मनोबल पर गम्भीर चोट पहुंचायी.

दण्डकारण्य में संचालित टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयां मिशन–2017 का जबर्दस्त व मुंहतोड़ जवाब था. इन कार्रवाइयों के साथ–साथ देश भर में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों व इनकी सफलता की नींव रखने वाले जन आधार की व्यापकता और आज की देशीय व अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति ने दुश्मन को अपनी मिशन–2017 की रणनीति में बदलाव कर नयी प्रतिक्रांतिकारी रणनीति 'समाधान' (2017–2022) तय करने बाध्य किया जो अगले पांच वर्षों में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन करने के लिए संकल्पित है.

दण्डकारण्य में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयां छापामार आधार क्षेत्रों की रक्षा करने में मददगार साबित हुईं. इस वर्ष प्राथमिक स्तर के इंप्रूवाइज्ड आर्टिलरी के निर्माण व इस्तेमाल, स्नाइपरों को तैयार करना, इंप्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइजों के जरिए माइन युद्ध तंत्र को तेज व व्यापक करना आदि नए अनुभव हासिल हुए हैं. ये अनुभव देश भर में विभिन्न छापामार जोनों में व लाल प्रतिरोध इलाकों में पीएलजीए बलों को विकसित करने में मददगार साबित होंगे.

एओबी में 2016–2017 में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयों में 15 पुलिस जवान मारे गये और 21 घायल हुए. इसमें मुंगारुगुम्मि–सुंकि एम्बुश बड़ी कार्रवाई थी. इसमें ओएसएपी (ओड़िशा राज्य सशस्त्र पुलिस) के 9 जवानों का सफाया और चार को घायल किया गया.

तेलंगाना में 2016–2017 में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में चार पुलिस जवान मारे गये और तीन घायल हुए. लम्बे अंतराल के बाद तेलंगाना में छापामार कार्रवाइयों में पुलिस वालों को सफाया करने में कामयाब होना अच्छा बदलाव है.

मध्यप्रदेश–महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ (एमएमसी) में 2016–2017 में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में चार पुलिस जवानों का सफाया और तीन को घायल किया गया. ओड़िशा में एक पुलिस जवान का सफाया कर सात को घायल किया गया.

इस तरह मध्य रीजियन के डीके, एओबी, तेलंगाना, ओड़िशा और एमएमसी में पिछले डेढ़ वर्ष के समय काल में 96 पुलिस जवान मारे गये और 134 घायल हुए.

पूर्वी रीजियन के बिहार–झारखण्ड, पूर्वी बिहार–पूर्वोत्तर झारखण्ड, पश्चिम बंग राज्यों में पिछले 10 महीनों में पीएलजीए द्वारा संचालित 40 से ज्यादा प्रतिरोध कार्रवाइयों में 12 पुलिस मारे गये और सात घायल हुए. एक जनविरोधी राजनेता और 10 प्रतिक्रांतिकारी तत्वों का सफाया किया गया. करोड़ों रुपयों की सरकारी, शोषक वर्गों और दलाल नौकरशाह कार्पोरेट कंपनियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया.

विगत 10 महीनों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, एओबी, ओड़िशा, तेलंगाना, एमएमसी, पश्चिम बंग, पश्चिमी घाटियों के विभिन्न छापामार जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में 200 से ज्यादा छापामार हमलों का पीएलजीए ने अंजाम दिया. इन हमलों में लगभग 110 पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जवान मारे गये और लगभग 135 घायल हुए. लगभग 75 जन दुश्मनों, जन विरोधी राजनेताओं, प्रतिक्रांतिकारी तत्वों, मुखबिरों और कोवर्टों का सफाया किया गया.

इसके साथ–साथ हमारे क्रांतिकारी इलाकों में हजारों जनता को गोलबंद कर सामंती विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, विस्थापन विरोधी जन आंदोलनों, राज्यहिंसा के खिलाफ प्रतिरोधी आंदोलनों को संचालित किया गया जिनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हुई थीं.

इस तरह अभी तक क्रांतिकारी इलाकों में आर्जित अनुभवों पर निर्भर होकर इन अनुभवों को ठोस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करने के जरिए, छापामार युद्ध को तेज व व्यापक करने के जरिए 'समाधान' हमले को हरा सकेंगे.

देशीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर क्रांति के पक्ष में बढ़ती अनुकूल परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के हमले को परास्त करेंगे:

1991 से लेकर आज तक विगत 26 वर्षों में केंन्द्र व राज्य सरकारें भूमण्डलीकरण की नीतियों के तहत मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को लागू करने के कारण मजदूर व किसान जनता का जीवन दूभर हो गया है. मजदूरों के नाममात्र के अधिकार भी कुचल दिए जा रहे हैं. संगठित व असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं. मजदूर आंदोलनों पर भीषण दमन जारी है. दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र संकट में फंसी हुई है. फसलों के उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण कर्ज के बोझ से किसान आत्महत्या करने मजबूर है.

देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए लायी गयी नोटबंदी, जीएसटी नीतियों की वजह से कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र और खुदरा व्यापार तहस–नहस हो गए है. औद्योगिक विकास धीमी पड़ गयी है. भारतीय अर्थ व्यवस्था की 'विकास दर' बहुत गिर गयी है. मुद्रास्फीति बढ़ रही है. इससे छोटे उद्यमियों व व्यापारियों के साथ–साथ समाज के सभी तबकों को आर्थिक रूप से तीव्र मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इनके आंदोलन पर उतरने की परिस्थितियां पनप रही हैं.

देश में 18 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं. हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने के मोदी का चुनावी वादा सफेद झूठ साबित हो गया है. इससे आगामी दिनों में बेरोजगार सेना जुझारू आंदोलनों में उतरने की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं.

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकियों को ही पहली प्राथमिकता की नीतियां लागू कर रहे हैं. इससे अमेरिका में भारतीयों को रोजगार के अवसर घट गए हैं. इतना ही नहीं विदेशों में भारतवासियों को नौकरियों से न सिर्फ निकाला जा रहा है, बल्कि नए अवसर न के बराबर हो गए है. वहीं रंगभेद से भारतवासियों पर अमेरिका सहित कई देशों में हमले बढ़ रहे हैं. इससे आइटी उद्योग के कर्मचारियों सहित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी व छात्र आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं.

देश में दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, उत्पीड़ित राष्ट्रों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों पर दिन–ब–दिन ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के हमले बढ़ रहे है. इसके विरोध में ये सभी तबके विभिन्न तरीके अपना कर संघर्ष कर रहे हैं. हिंदू फासीवादियों के हमलें भारतीय समाज में मौलिक अंतरविरोधों को और तेज करते हुए क्रांतिकारी परिस्थितियों को और अनुकूल बना रही हैं. ये सब ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा गठित करने के लिए बहुत ही अनुकूलताएं उपलब्ध करा रही हैं.

कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी जुझारू आंदोलनों पर दमन तेज किया गया है.

वर्ष 2008 में अमेरिका में शुरू होकर पूरे विश्व में विस्तारित आर्थिक संकट का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है. इससे साम्राज्यवादी देश इसके निपटारे के लिए आर्थिक तौर पर 'संरक्षण नीतियां', राजनीतिक रूप से फासीवाद और सैनिक रूप से युद्ध के मार्ग अपना रहे है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मौलिक अंतरविरोध तीखे होते जा रहे हैं. मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया), दक्षिण चीन सागर का इलाका, कोरियाई प्रायद्वीप साम्राज्यवादी अमेरिका, रूस और चीन के बीच संघर्षों का केन्द्र बने हुए हैं. कमजोर होते अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को कायम रखने के लिए ट्रम्प द्वारा लागू नीतियां विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रही हैं. इसके परिणामस्वरूप क्रांति के अनुकूल बढ़ते बदलावों का विश्व सर्वहारा वर्ग, क्रांतिकारियों, क्रांतिकारी पार्टियों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है. इसके तहत हमारे देश में साम्राज्यवाद और देशीय दलालों के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत है.

वर्तमान में साम्राज्यवादी देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अपनाई जा रही नीतियां जिस तरह उन देशों में शोषक वर्गों के दक्षिणपंथी और फासीवादी पार्टियों की वृद्धि के लिए अवसर दे रही हैं, उसी तरह सर्वहारा वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों के उद्‌भव होने तथा छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के रूप में विकसित होने, उनके द्वारा जुझारू संघर्ष संचालित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रही हैं.

हमारे देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति और सामंती शोषण व उत्पीड़न की तीव्रता के कारण रोजगार खोने वाले किसान, जंगलों पर अपने अधिकार खोने वाले आदिवासी, नौकरियां खोने वाले मजदूर, कर्मचारी, नौकरियां मिलने का भरोसा उठ चुके बेरोजगार युवा एवं

छात्र, ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों के शिकार दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उत्पीड़ित राष्ट्र – सभी पहले के मुकाबले अभी ज्यादा व्यापक व जुझारू रूप से गोलबंद हो रहे हैं. यह रुझान और बढ़ सकता है. यह क्रांतिकारी आंदोलन की अग्रगति के लिए व दुश्मन के हमले को परास्त करने के लिए बहुत बड़ा स्रोत व आधार है. अंतरराष्ट्रीय व देशीय तौर पर विकसित होती इन अनुकूलताओं के आधार पर उचित कर्तव्य व कार्यनीति तय कर दुश्मन के हमले को परास्त करेंगे. भारत की नवजनवादी क्रांति को आगे बढ़ाएंगे.

कर्तव्य :

फरवरी, 2017 में हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा जारी 'वर्तमान परिस्थिति–हमारे कर्तव्य' नामक सर्कुलर में आम तौर पर अगले दो वर्ष के समय काल में पूरा करने वाले कर्तव्यों और कार्यनीतियों के बारे में दिशानिर्देशन है. उन्हें ध्यान में रखकर निम्नांकित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करना होगा.

1 भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' (2017–2022) हमले को हराने पर हमारा ध्यान केन्द्रित करें!

दुश्मन और हमारी मजबूती व कमजोरियों के बारे में सही विश्लेषण करना होगा. इस समझ पर आधारित होकर इस प्रतिक्रांतिकारी हमले का मुकाबला करने की आक्रमणकारी व आत्मरक्षात्मक कार्यनीतियां तय करनी होगी. इस समझ के साथ हमारी पार्टी व पीएलजीए कतारों, स्थानीय सांगठनिक इकाइयों और क्रांतिकारी जनता को लैस करना होगा और उन सभी को दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार करना होगा जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है.

2. 'नवभारत' निर्माण के नाम पर भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अमल में लायी गयी इस योजना के बारे में देश भर में राजनीतिक तौर पर भण्डाफोड़ करने का प्रचार आंदोलन तेज करें!

3. भारत के शोषक–शासक वर्गों के युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद का भण्डाफोड़ करें!

देश के अंदर गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, भुखमरी, किसान आत्महत्याएं आदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के शोषक–शासक वर्ग युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद को भड़का रहे हैं. इनका शिकार होने से लोगों को बचाने के हिसाब से राजनीतिक रूप से जागरूक करना होगा.

4. तेजी से बढ़ते फासीवाद के खिलाफ पार्टी के हाथों मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्त मोर्चे को ढाले और विकसित करें!

तेजी से बढ़ता फासीवाद समाज के अंतरविरोधों को और तेज करेगा. परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिस्थितियां क्रांतिकारी संकट की ओर आगे बढ़ेंगी. इस स्थिति का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए पार्टी के हाथों में मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्तमोर्चा को ढालना और विकसित करना होगा. पहलकदमी और लचीलापन हासिल करना होगा.

5. ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी शक्तियों, जनवादियों, प्रगतिशील शक्तियों, संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्ष ताकतों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को एकजुट कर व्यापक संयुक्तमोर्चा और मजबूत व जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

6. आंदोलन के सभी इलाकों में साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, राज्य विरोधी वर्ग संघर्षों को तेज करें!

7. बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जनयुद्ध की कार्यनीतियां विकसित करने के लक्ष्य से सभी राज्यों/स्पेशल एरिया/स्पेशल जोनों में सामाजिक शोध व वर्ग विश्लेषण का कार्य संचालित करें! उनके आधार पर सही कार्यनीतियां रेखांकित कर ठोस परिस्थितियों के साथ सृजनात्मक रूप से जोड़कर जनयुद्ध को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं!

8. पार्टी व फौजी नेतृत्वकारी कतारों व कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक स्तर के उन्नतीकरण के कार्यक्रम लागू करें!

9. पीएलजीए को राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक तौर पर मजबूत करें!

केन्द्रीय सैन्य आयोग का आह्वान :

15 अगस्त 1947 के सत्ता हस्तांतरण के बाद के 70 वर्ष के समय काल में देश की राजनीतिक पार्टियां व संसदीय व्यवस्था जनता के रोजमर्रा की व मौलिक समस्याओं का हल करने में पूरी तरह विफल हुई हैं. भविष्य में भी इन राजनीतिक पार्टियों व संसदीय व्यवस्था जनता की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगी. अभी नरेंन्द्र मोदी द्वारा प्रवचित 'नए भारत' भी जनता की समस्याओं का उन्मूलन नहीं कर सकता. उल्टे वह शोषक वर्गों को और सुदृढ़ करेगा. वह दरअसल हिंदुत्व फासीवादी भारत ही होगा. इसलिए जनता की मूलभूत समस्याओं के हल के लिए नवजनवादी भारत का निर्माण ही एकमात्र रास्ता है जिसके लिए नवजनवादी क्रांति की जीत आवश्यक है. उसके लिए सशस्त्र संघर्ष की राह पर आगे बढ़ना ही होगा.

पीएलजीए की प्रतिरोध कार्यवाही

दक्षिण बस्तर डिविजन में – कोंटा क्षेत्र के पोलेमपल्ली के नजदीक 17 अगस्त को पीएलजीए द्वारा लगाए गए बूबीट्राप विस्फोट होकर कोब्रा बटालियन का एक जवना गंभीर रूप से घायल हुआ. 19 नवंबर को कोंटा क्षेत्र के तेमेलवाड़ा गांव के पास बूबीट्राप विस्फोट होकर सीआरपीएफ का एक प्रधान आरक्षक खत्म हुआ. 14–15 दिसंबर को केरलापाल एरिया में आतंक मचाने निकले पुलिस बलों पर पीएलजीए के तीनों बलों द्वारा 8 जगहों में हमलें किए गए. पहले गोंगे गांव के पास किए गए माइन विस्फोट में डीआरजी के तीन जवान घायल हुए थे. इन घायल जवानों को लेकर जा रहे पुलिस पर माडोम गांव के पास मिलिशिया ने क्लेमोर विस्फोट किया. इसके जवाब में पुलिस ने अंधाधुंध हजारों गोलियां चलायी. उसके बाद दुश्मन बलों का पीछा करते हुए मिलिशिया ने भरमारों के साथ फायरिंग की. कई बार फटाके विस्फोट करके भी दुश्मन बलों को हैरान–परेशान किया गया. एक ओर खाना, पीना और नींद से वंचित होकर दूसरी ओर मृत्यभय से पुलिस बल बहुत ही घबरा गए थे. इन सिलसिलेवार घटनाओं ने जनता और पीएलजीए में आत्मविश्वास बढ़ाया.

पश्चिम बस्तर डिविजन में – 11 अक्टूबर को गंगालूर इलाके के पालनार गांव के पास पीएलजीए द्वारा लगाए गए बूबीट्राप विस्फोट होकर पुलिस के दो जन जिसमें एक टीआई शामिल है, घायल हुए. 7 नवंबर को इसी क्षेत्र के बचेली गांव के पास पीएलजीए ने हमला करके आरपीएफ के एक जवान को खतम किया. इस हमले में और एक जवान भी घायल हुआ. 8 नवंबर को मद्देड़ इलाके के देपाला गांव के पास हुए बूबीट्राप विस्फोट में एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ, जिसने इलाज के दौरान एक सप्ताह के बाद दम तोड़ा. 30 नवंबर को गंगालूर क्षेत्र के पुंबाड़ के पास बूबीट्राप्स विस्फोट होकर दो जवान – एक डीआरजी का और एक एसटीएफ का– घायल हुआ.

दरभा डिविजन में – 29 अक्टूबर को सुरनार गांव के पास हुए बूबीट्राप्स विस्फोट में डिआरजी का एक जवान घायल हुआ.

उत्तर बस्तर डिविजन में – नवंबर महीने में 1 से 5 तक प्रतापुर एरिया मेंडकी एलओएस क्षेत्र के लगभग 25 गांवों में 500 की तादाद में आने वाले पुलिस बलों द्वारा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का संचालन किया गया. इस ऑपरेशन को विफल करने के लिए 3 नवंबर को आपा टोला के पास किए गए एंबुश में मोहित पटेल नामक डीआरजी गुंडा मारा गया. जबकि डीआरजी का और एक जवान घायल हुआ. 8 नवंबर को अंतागढ़ ब्लॉक के आमाबेड़ा थानांतर्गत सापेनहुर गांव के पास पीएलजीए द्वारा की गई फायरिंग में डीआरजी का एक जवान घायल हुआ. कोयलीबेड़ा थानांतर्गत उदनपुर बीएसएफ बेस कैंप के ऊपर 29 नवंबर को जन मिलिशिया द्वारा फायरिंग की गई. बाद में फटाके फोड़े गए. 12 दिसंबर को कोयलीबेड़ा ब्लॉक के बारदा बाजार में पीएलजीए की एक्शन टीम द्वारा गोपनीय सैनिक कारू दुग्गा का खात्मा किया गया.

★

इसलिए हमारी केन्द्रीय सैन्य आयोग का आह्वान है कि सभी उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों व उत्पीड़ित राष्ट्र भाकपा (माओवादी) और पीएलजीए में हजारों–लाखों संख्या में भर्ती हो जाए.

पिछले वर्ष में समूचे देश में ऑपरेशन ग्रीनहंट हमलों को परास्त करने के लक्ष्य से हमारी पीएलजीए द्वारा संचालित साहसिक टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयों में हासिल सफलताओं के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें. पूरे दिसम्बर माह में भर्ती अभियान संचालित करें.

- प्रतिक्रांतिकारी नए 'समाधन' हमले को परास्त करें! दुश्मन के बलों का सफाया करते हुए, उनसे हथियार छीन लें!
- दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना गुलामी के बराबर है! रंगबिरंगे लालच दिखाकर अपने पक्ष में झुकाने की दुश्मन की एल.आई.सी. नीति का मुंहतोड़ जवाब दे!
- पार्टी, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को संगठित करें!
- पीएलजीए में बड़ी संख्या में युवक–युवतियों की भर्ती करें!
- सामंती व साम्राज्यवादी विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!
- ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ मजबूत व जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!
- मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिन्दबाद!
- पीएलजीए, जिन्दबाद!
- भाकपा (माओवादी), जिन्दबाद!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी)

भाकपा (माओवादी)

देश भर में गुरिल्ला युद्ध–जनयुद्ध को तेज व विस्तारित करें!

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के सफाए के लिए जारी नई प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017–2022) को हराएं!

(2 से 8 दिसंबर तक आयोजित होने वाली पीएलजीए की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर केन्द्रीय सैन्य आयोग (सी.एम.सी), भाकपा (माओवादी) द्वारा जारी आह्वान के मुख्य अंश)

प्रिय कामरेडों व जनता!

2 दिसम्बर, 2000 भारत के क्रांतिकारी इतिहास में यादगार दिन है. इस दिन साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीवादी व सामंतवादी शोषण व उत्पीड़न से देश की उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) का गठन हुआ था. हमारी पार्टी के संस्थापक, शिक्षक व भारतीय क्रांति के निर्माता, अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दिशानिर्देशन में हमारे प्रिय नेता व अमर शहीद कामरेड्स श्याम, महेश व मुरली की प्रेरणा से, हजारों शहीदों द्वारा मिली स्फूर्ति से उस दिन देश की उत्पीड़ित जनता के अधूरे सपनों को साकार करते हुए पीएलजीए की स्थापना हुई. इस मौके पर सभी पार्टी कमेटियों व कमानों, पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के साहसिक कमांडरों व योद्धाओं, जन मिलिशिया बलों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं तथा उत्पीड़ित जनता का केन्द्रीय सैन्य आयोग लाल अभिवादन पेश करती है.

इस अवसर पर 2 से 8 दिसम्बर तक समूचे देश में संघर्षरत सभी इलाकों में, गांवों व शहरों में पीएलजीए की 17वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश–स्फूर्ति के साथ मनाने सभी का सीएमसी आह्वान करती है. दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017–2022) को हराने के लक्ष्य से पीएलजीए को संगठित करने, देश भर में इस अवसर पर पूरे दिसम्बर माह भर भर्ती अभियान संचालित करने का आह्वान करती है.

भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने की दिशा में एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए, ऑपरेशन ग्रीनहंट का मुकाबला करते हुए इस वर्ष लगभग 140 कामरेड शहीद हुए. इनमें 30 महिला कामरेड शामिल थीं. शहीदों में हमारी पार्टी के दो केन्द्रीय कमेटी सदस्यों के साथ–साथ डीके में 98, बीजे में 19, तेलंगाना में दो, एओबी में 7, ओड़िशा में दो, पश्चिम बंग में एक, एमएमसी में दो, पश्चिम घाटियों में एक कामरेड शामिल थे. इनमें तीन राज्य कमेटी स्तर के कामरेड, सात जेडसी/डीवीसी कामरेड, तीन सब–जोनल कमेटी के कामरेड, 22 एसी/पीपीसी कामरेड, 50 से ज्यादा पार्टी व पीएलजीए के सदस्य, लगभग 40 क्रांतिकारी जन सरकारों व संगठनों तथा मिलिशिया कार्यकर्ता और लगभग 15 क्रांतिकारी जनता शामिल थे.

इन शहीदों में भारतीय क्रांति के नेता व हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कामरेड नारायण सान्याल (बिजय दा, पोलिट ब्यूरो सदस्य), कामरेड कुप्पु देवराज (रमेश, योगेश), राज्य कमेटी स्तर के कामरेड्स रघुनाथ महतो (बीजे सैक सदस्य), हिमाद्रि राय (पश्चिम बंग के एससी सदस्य), अजिता (कावेरी, पश्चिम घाटी एसजेडसी सदस्या) शामिल थे.

बुरकापाल सहित विभिन्न साहसिक हमलों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के क्रम में, कई मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों, भीतरघात व दुश्मन के कोवर्ट ऑपरेशनों, दुर्घटनाओं में, जेलों में, सर्पदंश, बीमारी आदि कारणों से जान गंवाने वाले इन सभी अमर शहीदों को सीएमसी पीएलजीए की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी श्रद्धांजली अर्पित करती है. उनके द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट मूल्यों, साहसिकता, निडरता, जनता के प्रति समर्पण की भावना से हम सब सीख व प्रेरणा लेते हुए, उनकी अधूरे सपनों व अरमानों को पूरा करने आखिरी दम तक अविश्रांत लड़ने की शपथ लेती है. सीएमसी को विश्वास है कि देश भर में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में घायल कई कामरेड शीघ्र ही ठीक होकर जुझारूपन व जोश के साथ फिर से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ेंगे.

मिशन–2017 को हराने के लिए देश भर में हमारे द्वारा संचालित राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास व उसके परिणामः

हमारे आंदोलन की शक्ति–क्षमताओं के आधार पर देश भर में राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास को तेज करते हुए मिशन–2017 को एक हद तक रोकने में हम कामयाब हुए. इसमें महत्वपूर्ण है – शोषक–शासक वर्गों के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध का प्रतिरोध करते हुए पीएलजीए द्वारा

(शेष पेज 50 में...)